हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 फरवरी 1986

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 18 फरवरी, 1986

पृष्ठ सख्यां

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न उठाना––	
23.1.1986 को राज्य में रास्ता रोको आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने सम्बन्धी	(2) 21
वाक आउट्स	(2) 24
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)25

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 18 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे ।

Sugarcane crushed in Cooperative Sugar Mills, Palwal

***1046. Chaudhri Azmat Khan :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the total quantity of sugarcane crushed in Cooperative Sugar Mills, Palwal (Faridabad) during the year 1984-85; and

(b) whether any wood was purchased for use in the above said Sugar Mills during the period as referred to in part (a) above together with the details of procedure adopted for the purchase of the said wood ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) :

(क) 45201.75 क्विंटल ।

(ख) हां, ईंधन की लकड़ी की सप्लाई के लिए समाचार पत्र के माध्यम से टैंडर आमन्त्रित किए गए । पार्टियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था । मित्र की ईंधन लकड़ी की कुल मांग का कुछ हिस्सा वन विभाग द्वारा सप्लाई किया गया । जब पार्टियां, जिन्होंने निविदाएं प्रस्तुत की थीं, लकड़ी सप्लाई करने में असफल रहीं तो यह चेयरमैन की अनुमति लेने के बाद एक स्थानीय फर्म से खरीद ली गई जिसे बाद में मिल के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मेरा मेन सवाल यह है कि कितना गन्ना पीड़ा गया और उसके लिये कितनी लकड़ी खरीदी गई, दूसरे जो गन्ना पीड़ा गया उसके लिए लकड़ी की खपत की क्या रेशो है?

श्री प्यारा सिंह : पलवल वाली मिल ने 21– 2– 1985 से वास्तव में गन्ना पीड़ना आरम्भ किया । वर्ष 1984– 85 का सीजन मिल के लिए परीक्षणात्मक था और मिल दिनांक 12– 3– 85 यानि बन्द होने की तिथि तक केवल 45201.75 क्विटल ही गन्ना पीड़ पाई । जहां तक लकड़ी खरीदने का सवाल है इस चीनी मिल ने 30– 10– 84 को समाचार पलों में विज्ञापन द्वारा 10 हजार क्विटल लकड़ी खरीदने के लिए टैडर आमन्त्रित किए थे । इसके उत्तर में 4 पार्टियों ने निम्न प्रकार से टैडर भेजे –

1 मै० गिरराज मशीनरी स्टोरेज, हांसी रोड जीन्द 45. 00 रुपये प्रति क्विटल

2. मै ० सनशाईन ईन्टरप्राईजीज, अनाज मन्डी, जीन्द 35.80 रुपये प्रति क्विटल

3. मै ० सीता राम सतीश कुमार, किरयाना मरचौन्ट, अनाज 40.50 रुपये प्रति क्विटल मंडी, जीन्द

4. डिवीजनल फोरैस्ट आफिसर, प्रोडक्शन डिवीजन, रोहतक 61.70 रुपये प्रति क्विटल

इन सभी पार्टियों को 15– 12–84 को बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वन अधिकारी रोहतक के प्रतिनिधि के सिवाए बाकी तीन पार्टीज उपस्थित नहीं हुई । सरकारी संगठन होने के कारण डिवीजनल फोरैस्ट आफिसर रोहतक को लकड़ी की सप्लाई के लिए आदेश दे दिया गया । मिल कर्मचारियों द्वारा वन विभाग के विभिन्न डिपुओं जैसे महम, रोहतक, होडल, सिरसा तथा सोहना में बार–बार दौरा करने के बावजूद भी मिल की आवश्यकता अनुसार लकड़ी उपलब्ध नही हो रही थी । आरम्भिक सीजन में मिल चालू करने के लिए लकड़ी की शीघ्र आवश्यकता थी, अतरू मिल के पास लोकल मार्किट से लकड़ी खरीदने के सिवाय कोई चारा नहीं था । इसी दौरान दी संगम कैमीकल तथा कन्ट्री मैडीसन प्रोडक्शन सहकारी औद्योगिक समिति ने मिल का दौरा किया तथा वन विभाग के 60.51 रुपये प्रति क्विटल की दर

के मुकाबले में 47.80 रुपये प्रति क्विटल एफ० ओ० आर० एट साईट लकड़ी की कोटेशन दी । ईंधन की लकड़ी के भाव बाजार में बहुत बढ जाने के कारण समिति कोटेशन देने के बाद नही आई । उसके बाद मिल का एक प्रतिनिधि, जिन तीन और पार्टियों ने अपनी कोटेशन भेजी थी, उनके पास लकड़ी की सप्लाई हेतु भेजा गया । परन्तु तीनों पार्टियों ने लकड़ी की सप्लाई करने से डकार कर दिया । तब मै० हैबर कोन्ट्रैक्टर, पलवल, ईंधन की लकडी सप्लाई करने के लिये मिल में आए और अर्ध सूखी लकड़ी का 42 रुपये प्रति क्विटल तथा सूखी लकड़ी का 45.60 रुपये प्रति क्विटल के भाव का प्रस्ताव किया जो वन विभाग तथा संगम कैमीकल एरण्ड कन्ट्री मैडीसन प्रोडक्शन सहकारी औद्योगिक समिति, रोहतक से भी काफी कम थे । चूकि मिल शीघ्र चालू होनी थी इसलिये लकड़ी की तुरन्त आवश्यकता थी । अतः इसके पास दिनांक 7– 2–85 को चेयरमैन की अनुमति से मै ० हैबर कोन्टैरक्टर पलवल को लकड़ी सप्लाई करने के आदेश देने के सिवाए और कोई चारा नहीं रह गया था । उक्त खरीद को बाद में मिल के निदेशक मण्डल ने अनुमोदित कर दिया था ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या स्टेट के अन्दर और कोई शुगर मिल लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हें?

श्री अध्यक्ष : क्या आप उस मिल के लिए लकड़ी सप्लाई कर देंगे? (हंसी)

चौधरी फूल चन्द : स्पीकर साहब, इस सवाल के प्रथम भाग में पूछा. गया है कि पलवल कोआपरेटिव शूगर मिल में कितना गन्ना पीड़ा गया । लेकिन मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शाहबाद शूगर मिल में कितना गन्ना पीड़ा गया? दूसरे जो गन्ना पीड़ा गया है, क्या वह कम था या काफी था?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो पलवल शूगर मिल से सम्बन्धित है ।

श्री प्यारा सिंह : शाहबाद मिल की सूचना तो मेरे पास इस समय नहीं है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, शाहबाद शूगर मिल में 9 लाख 25 हजार क्विटल गन्ना पीडा गया है ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो लकड़ी खरीदी गई है वह कीकर की लकड़ी है, शीशम की है या आम की है?

श्री प्यारा सिंह : जो लकड़ी मिल के लिये खरीद की गई है, उसमें आम, शीशम, कीकर तथा दूसरी मिली–जुली लकड़ियां शामिल हैं ।

चौधरी अजमत खां : मैंने तो यह सवाल पूछा था कि कितनी लकडी खरीदी गई और कितना गन्ना पीड़ा गया और

इसकी क्या रेशो रही? दूसरे इन्होंने अब यह बताया है कि जो लकड़ी खरीद की गई थी उसमें आम, शीशम और कीकर आदि की लकड़ियां शामिल थीं । मैंने उस मिल में जा कर खुद देखा है, वहां पर आम या शीशम आदि की कोई लकड़ी नही थी । जो लकड़ी खरीद की गई है वह गन्ने की पीड़ाई की अपेक्षा बहुत अधिक खर्च हुई है जिससे मिल को नुक्सान हुआ है ।

श्री प्यारा सिंह : मिली जुली लकड़ियां खरीदी गई थी । शुरू शुरू में जब मिल को चालू किया जाता है तो उस समय लकड़ी की खपत कुछ अधिक होती ही है क्योंकि शुरु शुरू में जितनी मात्रा में मिल को गन्ना चाहिए वह नहीं आता ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मण्डी जी के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि आम और शीशम की लकड़ी के भाव और कीकर की लकड़ी के भाव में 2० रुपये क्विटल तक का अन्तर होता है । इसलिये मिली–जुली लकडी की जो यह बात कह रहे हैं वह समझ में न आने वाली बात है ।

श्री प्यारा सिंह : जो लकड़ी खरीदी गई है उसमें सभी प्रकार की लकड़ियां शामिल हैं ।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पलवल शूगर मिल द्वारा 1985–86 में कितना गन्ना पीड़े जाने की उम्मीद है क्योंकि गन्ने की पीड़ाई का अब सीजन भी खत्म होने जा रहा है?

श्री प्यारा सिंह : इस सीजन में इस मिल ने 4 लाख 44 हजार क्विंटल गन्ना पीड़ा है । वैसे भी अब यह मिल 11– 2–86 को बन्द हो चुकी है ।

चौधरी फूल चन्द : अध्यक्ष महोदय, चौधरी अजमत खां के सवाल की यह मन्शा है कि गन्ने की पीड़ाई के लिए जो लकड़ी खरीदी गई थी, क्या वह गन्ने का रस पकाने के लिए ज्यादा तो नहीं थी?

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर साहब, पलवल शूगर मिल के लिए टोटल लकडी 18277, 48 क्विटल खरीदी गई है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पोजिशन क्लीयर कर देता हूं । जब नई मिल लगाते हैं तो लकड़ी से आग जलाई जाती हैं । जिस तरह से भट्ठे को शुरू में स्टार्ट करते हैं उसी तरह से मिल स्टार्ट की जाती है । कोयला बाद में जलता है, शुरू में लकड़ी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है । लगभग 18,277 क्विटल लकड़ी ली गई लेकिन सारी जली नही, कुछ बच भी गई है । तकरीबन आधी लकड़ी जली होगी । टैण्डर दो किस्म की लकड़ी कीकर और शीशम के लिये इन्वाइट किए गए थे लेकिन जब वह लकड़ी नहीं मिली तो मजबूरी में मिली–जुली लकड़ी लेनी पड़ी । जो लकड़ी लील गई थी, वह डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसकी देख–रेख में ली गई । अध्यक्ष महोदय, मजबूरी की हालत में, जल्दी की वजह, से चूंकि मिल को

ट्रायल देना था, इसलिए यह लकड़ी लेनी पड़ी । इसमें खदशे की कोई बात नहीं है ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जींद में जो नई शूगर मिल लगी है उसमें अब तक कितना गन्ना कश किया गया हे?

चौधरी भजन लाल : जींद में अब तक 8,62,675 क्वींटल गन्ना पेला गया एं ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, अभी यहां बताया गया कि पलवल की मिल ने 45 लाख क्वींटल गन्ना क्रश किया है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस मिल की टोटल कैपेसिटी कितनी है और गन्ना पूरी कैपेसिटी पर पेला गया है या विलो कैपेसिटी क्रश हुआ है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस मिल ने केवल 45 हजार क्वींटल गन्ना पेला है 45 लाख. क्वींटल नही । इसकी डेली कैपेसिटी 12 हजार क्वीटल गन्ना कश करने की है । जैसा सरदार प्यारा सिंह जी ने बताया, बाद में गन्ना न मिलने के कारण यह मिल बन्द हो गई थी ।

तारांकित प्रश्न सं० 1052

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राम बिलास शर्मा, सदन में उप–स्थित नहीं थे ।

Science Classes in Government College, Safidon

***1050. Chaudhri Kundan Lal :** Will the Minister of Stale for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration to start science classes in Government College, Safidon ; if so, the time by which the said classes are likely to be started?

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra) : Yes. A proposal for starting science classes in Government College, Safidon is under the consideration of the Government.

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अब तक वहां क्या क्या साधन जुटाए गए हैं और ये क्लासिज वहां कब तक चालू हो जाएं गी?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, वह ओं लै बोरेटरीज वगैरा बननी हैं । गवर्न मैट की तरफ से 18 लाख रुपए सैंक्शन हो गए हैं और टैण्डर काल कर लिए गए हैं । जहां तक क्लासिज चलने का सम्बन्ध है, लैबोरेटरीज बनने के बाद ही क्लासिज चालू की जाएगी ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, क्या मन्डी जी बताएंगे कि कितने गवर्नमैंट कालेजिज ऐसे हैं जिनमें साईंस क्लासिज नहीं

हैं? क्या ये यह भी बताएंगे कि साईस क्लासिज चलाने के लिए क्या क्राइटेरिया है?

श्री जगदीश नेहरा : इस समय 34 गवर्नमैंट कालेजिज में से 17 में साईंस क्लासिज हैं । दूर दराज के एरियाज में जो कालेजिज है वहां अगर साईंस क्लासिज की मांग हो तो लैबोरेटरीज बनने के बाद ही सहित– क्लासिज चालू की जाती हैं ।

श्री निहाल सिंह : जिन 17 कालों–मुंज में अभी तक साईंस क्लासिज नहीं हैं, क्या मन्त्री जी बताएंगे किं उनमें कब तक ये चालु की जाएंगी? क्या गवर्नमैंट यह महसूस नही करती कि आजकल के साईंस युग मैं सब जगह साइंस पढ़ाना जरूरी है? क्या मन्त्रो जी यह भी बताएंगे कि लड़कियों के कितने कालेज ऐसे हैं जहां साईस क्लासिज नही हैं?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि आजकल के साईस के जमाने में साईंस क्लासिज हर जगह होनी चाहिए । सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है । पिछले साल 6 कालेजिज में साईंस क्लासिज शुरू की गई थी । इस बार 10 कालेजिज में साईंस क्लासिज शुरू करने की कोशिश हौ रही है । टोटल प्राईवेट कालेज 90 हैं । 41 में साईस क्लासिज हैं । कुछेक में पिछले साल शुरू की गई हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां से मांग आती है और जहां पर खोलने की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहां

इन्हें शुरू करने का प्रयत्न किया जाता है । लड़कियों के जो कालेज सैपरेट है, उनमें साईंस क्लासिज हैं ।

Acquisition of land by H.U.D.A. in Gurgaon Constituency

***1058. Chaudhri Dharam Bir Gauba :** Will **the** Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any land for the construction of Industrial and Residential Complexes has been acquired by HUDA in Gurgaon Constituency since May, 1982 to date; if so, the total acreage thereof;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to acquire land for the purpose as referred to in part (a) above in Gurgaon Constituency during the year 1986-87; if so, the acreage proposed to be acquired; and

(c) whether the payment of compensation has been made to the owners of acquired land as referred to in part (a) above ?

मुख मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(ए) हां जी 1880.63 एकड ।

(बी) हां जी, लगभग 2000 एकड ।

(सी) हां जी, अर्जित की गई भूमि के मुआवजे की अदायगी की जा चुकी है ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन से पहले जो जमीन ऐक्वायर की गई थी, उसका भी कम्पनसेशन पे कर दिया गया है या नहीं? इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जमीन ऐक्वायर करने में जो डिसक्रिमिनेशन होती है, यह कभी रुकेगी या नहीं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें यह लिखा है कि गुड़गांव कांस्टिच्यूऐसी में मई 1982 से लेकर अब तक इंडस्ट्रियल और रैजिडैन्शल कंप्लैक्सिज बनाने के लिए कितनी जमीन ऐक्वायर की गई और क्या उसका कम्पनसेशन दे दिया गया है या नहीं । मई 1982 से लेकर 15 फरवरी, 1986 तक जो जमीन ऐक्वायर की गई उसका कुल मूआवजा 11 करोड़ 37 लाख 88 हजार रुपये दिया जा चुका है ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले जो जमीन ऐक्वायर की गई थी उसका मुआवजा अभी देते को रहता है । गुड़गांव कांस्टिच्यूएसी में 1976 और 1978 में भी कुछ जमीन ऐक्वायर की गई थी । क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि उसकी पेमैंट अब तक क्यों नहीं हुई और अब वह कब तक हो जाएगी?.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई केस कोर्ट में हो सकता है । इसके अलावा नौन–पेमैंट का कोई और कारण भी

हो सकता है । इन्होंने इस बारे में अपने सवाल में पूछा नहीं था लेकिन फिर भी माननीय सदस्य जब भी ठीक समझें मुझसे मिल सकते हैं और अगर कोई खास वजह नहीं हुई, कोर्ट की कोई कानूनी प्रौब्लम नही हुई, तो जिनका मुआवजा बाकी है उनको भी बहुत जल्दी पेमैंट कर दी जाएगी ।

श्री ए० सी ० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं । जिन लोगों की जमीन ऐक्वायर होती है उन्हें गवर्नमैंट की नीति के अनुसार एक प्लाट दिया जाता है । वह प्लाट उन्हें एक इन्सैन्टिव के रूप में होता है लेकिन अफसोस यह है कि उनसे हाई रेटस चार्ज किए जाते हैं । मिसाल के तौर पर गवर्नमैंट स्वयं यदि जमीन 10 रुपये गज के हिसाब से. ऐक्वायर करती है तो उसे प्लाट प्रोवेलिग मार्किट रेट से यानी 300– 400 रुपये गज के हिसाब से दिया जाता है । दूसरे मायने में मतलब यह कि जो 2 एकड़ का प्लाट एक लाख रुपये के मुआवजे में ऐक्वायर किया जाता है उसके बदले मे किसान को. साढ़े चार सौ गज का प्लाट ही मिल पाता है । क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि इस तरह से दिया जाने वाला डवैलिग हाउस का प्लाट किसान को ऐक्वायर्ड प्राईस पर ही दिया जाएगा?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिस किसान की जमीन ऐक्वायर की जाए उसको एक प्लाट दिया जाए । जहां तक कीमत ज्यादा लेने का ताल्लुक है, इसके बारे में निवेदन यह है कि जो

कीमत ली जाती है उसमें डिवैल्पमैंट चार्जिज शामिल होते हैं । माननीय सदस्य को मालूम है कि जमीन ऐक्वायर करने के बाद सरकार को सड़कें बनानी होती कुंए, सीवरेज का इन्तजाम करना होता है, पीने के पानी का इन्तजाम करना होता है तथा और कई किस्म की सुविधाएं देनी होती हैं । उसके हिसाब से फर्ज करो हम सौ एकड़ पर कोई कालोनी बनायें तो हमें 45 परसैन्ट जमीन खाली रखनी पड़ती है । यह खाली जमीन स्कूलों, हस्पतालों और ग्रीन पार्क आदि के लिए देनी पड़ती है । रिहायशी प्लाटों में कोई प्रौफिट नही लिया उगाता है । ये प्लाटस नो–प्रोफिट और नो–लौस बेसिज पर दिये जाते हैं और जिन लोगों की जमीन ऐक्वायर की जाती है उनको कीमत हाल के मार्किट रेट के हिसाब से देते हैं । पहले पिछले पांच साल के रेटस का हिसाब लगाकर कीमत दी जाती थी लेकिन आजकल हम आज का हिसाब लगा कर कीमत देते हैं । आज की सरकार ने फैसला लिया है कि एक साल के अन्दर उस एरिया में जिस हिसाब से जमीन बिकी है उसी हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाये और देते हैं ।

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय यह बात सच है कि हुड्डा द्वारा ऐक्वायर की हुई जमीन का लैन्ड ऐक्वीजिशन आफिसर अवार्ड दे देता है तो वै पैसे दे दिये जाते हैं लेकिन जो लोग कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट द्वारा जो मुआवजा निर्धारित किया जाता है, वह दस दस साल तक नही मिलता है । सन 1976–77– और 1977–78 के केसिज का मुआवजा किसानों को

अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । किसानों को लैन्ड ऐक्वीजिशन आफिसर, पटवारी और कानूनगो पर निर्भर रहना पडता है । इस तरह के केसिल मे अगर कोई आदमी पोलिटिकल ऐप्रोच करता है तो उसकी फाइल दबा दी जाती है और अगर कोई दसरे प्रकार की ऐप्रोच करता है तो उसका मुआवजा मिल जाता हे इस तरह से दस दस साल से लोगों को पैसा नहीं मिला है । क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात की जांच. करवायेंगे और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवायेंगे?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात बहिन शारदा रानी जी ने कही है, हो सकता है इस में वजन हो । जब कोई आदमी या सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गई हो तो हो सकता है उस वजह से डिले हुई हो लेकिन अगर फैसला आने के बाद कीमत देने में डिले हुई है और सन 1976– 77 के केसिज पैंडिग हैं तो सरकार किसानों को तीन महीने के अन्दर अन्दर जरूर पैसा दे देगी बशर्ते कोई कानूनी दिक्कत न हो ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो जमीन हुड्डा द्वारा ऐक्वायर की जाती है उस जमीन का कम्पनसेशन देने से पहले ही प्लाटस काट कर नीलाम कर दिए जाते हैं, क्या यी कानूनी तौर पर जायज है? मैं मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीन सरकार द्वारा ऐक्वायर की जाती है, क्या उस का मुआवजा ऐक्वायर करने के बाद यानी नीलाम करने से पहले दे दिया जायेगा?

चौधरी भजन लाल : ये पहले की बात करते हैं, पहले ऐसा होता रहा होगा । आज की सरकार ने फैसला किया है कि जमीन ऐक्वायर होने के बाद अगर मुआवजे का फैसला सुना दिया जाता है तो पहले पैसा दिया जाता है और बाद में जमीन पर कब्जा लिया जाता है तथा बाद में ही प्लाटस काटे जाते हैं । अगर कोई ऐसा केस उनके नोटिस में है तो हमें बतायें, हम फौद्री तौर पर कार्यवाही करवायेंगे ।

चौधरी कुन्दन लाल : स्पीकर साहब, मेरे हल्के सफीदों में पीलूखेड़ा ब्लाक में ड्रेन के लिए जमीन ऐक्वायर हुई थी.

श्री अध्यक्ष : यह सवाल हुड्डा की जमीन के बारे में पै । इसलिये आपका सप्लीमेंटरी क्वैश्चन नहीं बनता है । आप बैठिए ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, जो जमीन हड्डा द्वारा ऐक्वायर की जाती है उसके बारे में किसान लोग कोर्ट में चले जाते हैं और उन्हें वहां से कम्पनसेशन विद इन्ट्रैस्ट मिल जाता है । बहुत से लोग कोर्ट में भी नहीं जाते हैं लेकिन खजाने में पैसा न होने की वजह से उन्हें लेट कम्पनसेशन मिलता है । क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि गवर्नमैंट खाते से उन लोगों को इन्ट्रैस्ट समेत कम्पनसेशन दिया जायेगा जो कोर्ट मे नहीं जाते हैं?

चौधरी भजन लाल : कोर्ट के मुताबिक कीमत मिलती है । पहले कीमत देते हैं, बाद में जमीन पर कब्जा लेते हैं ।

श्री निहाल सिंह : मेरा सवाल इन्ट्रैस्ट के बारे में है ।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय नीति के अनुसार जो जमीन मकानों के लिये ऐक्वायर की जाये वह खेती योग्य नहीं होनी चाहिए यानी अच्छी जमीन पर मकान न बनाये जायें बल्कि बेकार जमीन पर बनाये जायें । क्या मख्य मन्त्री महोदय रोशनी डालने की कृपा करेंगे कि जिन जिन शहरों में जमीन अधिग्रहण की गई है, वह अच्छी जमीन थी या बेकार जमीन थी?

चौधरी भजन लाल : चौधरी नेकी राम जी ने पूछा है कि कौन सी जमीन ऐक्वायर की गई है और किन किन शहरों में ऐक्वायर की गई । शहरों में जमीन बहुत कम होती है । गुड़गांवा– के बारे मै सवाल पूछा गया पं । वहां पर जिन बीस गांवों की जमीन ऐक्वायर की गई है उनके नाम हैं कारटरपुरी, कादीपुउर, खांडसा, सुमा, गुडगांव, सुखराली, झांडसा, चिलोखेड़ा, घनखोट, मुलाहेड़ा, धर्मापुर, खेरकी, शाहपर, डुंडाहेड़ा, शकरपुर, गवाल पहाडी, बडौला, सहरोल, नाशपुर और सिकन्दरपुउर । ये बीस गांव हैं जिनकी हमने जमीन ऐक्वायर की है । हमारी ओर से कोशिश यह होती है कि बहुत ज्यादा अच्छी जमीन न ली जाये जिसमें पैदावार ज्यादा होती हो । अगर जमीन शहर के नजदीक न मिले और लोगों की डिमांड हो कि जमीन मिले तो उस हालत में ही अच्छी जमीन ऐक्वायर की जाती है ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : क्या सरकार का तीन सौ गज की बजाए सौ गज और पचास गज के छोटे छोटे प्लाटस काटने का विचार है ताकि गरीब लोगों को प्लाटस मिल सके?

चौधरी भजन लाल : सरकार ने ऐसा पहले से ही प्रावधान किया हुआ है । हमने अनुसूचित जातियों के लिये 20 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के लिये पांच परसैन्ट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए पांच परसैन्ट, विकलांग के लिए एक परसैन्ट, फ्रीडम फाइटर्ज के लिये दो परसैन्ट की रिजर्वेशन रखी है । ये प्लाटस दो मरले के हैं । ये बाकायदा 20 परसैन्ट सबसेडाइज्ड रेटस पर देते हैं और इनकी कीमत बड़े प्लाटस पर डालते हैं । रिजर्वेशन का प्रावधान किया हुआ है और रेट्स भी ठीक रखे हैं ताकि गरीब आदमी को ठीक कीमत पर प्लाट मिल जाये ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : क्या हरियाणा गवर्नमैंट ऐसा कर सकती है कि जो प्लाटस काट रहे हैं, वे पचास परसैन्ट हरियाणा निवासियों के लिये रिजर्व हो सकें?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, प्लाटस देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है लेकिन ऐक्ट में प्रावधान करना ठीक नहीं रहेगा और न ही सरकार के हित में होगा । बहुत से लोग बाहर से आकर यहां बसते हैं और इन्डस्ट्री भी लगाते हैं । दूसरे विदेश से आ कर भी लोग बस जाते हैं । हरियाणा निवासियों के लिए रिजर्व करने से प्रगति में रुकावट आयेगी लेकिन हरियाणा निवासियों का ध्यान रखा जाता है ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मेरे पहले सवाल का तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिल सका । शायद मैं समझाने में

कमी कर गया । मेरी सबमिशन थी कि जिस तरीके से छोटे प्लाट होल्डर्ज को जिसकी एक या दो एकड़ जमीन एक्वायर हुई है, उसे पचास हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देते हैं तो उसे दो एकड़ का एक लाख रुपया मुआवजा मिला । अगर उसी आदमी को तीन सौ गज का प्लाट दिया जाये तो उससे एक लाख 2० हजार रुपया लिया जाता है यानि तीन सौ और चार सौ गज के बीच का प्लाट दिया जाये तो उससे 'इतना रुपया लिया जाता है । उस आदमी ने जो सरकार को जमीन दी है, उस की कीमत से ज्यादा उसे प्लाट की कीमत देनी पड़ती है । स्पीकर साहब, मैं एक बहुत ही इम्पौटैंट बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हु । हुड्डा जो बनी है यह अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए बनी है लेकिन आज के दिन अर्बन एरियाज में स्लम दिन–प्रति– दिन बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर इन्डस्ट्रियल टाउन्ज में। वहां पर लोकल बाडीज के लिए यह बड़ा भारी सिरदर्द बना हुआ है । हुड्डा के ई० डब्ल्यू ० एस ० के मकान ओपनली अलाट करने की बजाय अगर लोकल बौडीज के धू दिये जायें तो स्लम एरियाज में रहने वालों को रिहैबलिटेट करने में काफी सुविधा होगी । ऐसा करने से न कोई कानूनी अड़चन होगी और न ही हरियाणा में जो स्लम का कलंक बढ़ता जा रहा है, वह बढ़ेगा । सरकार को भी राहत की सांस मिलेगी और लोगों को भी सुविधा होगी । मैं इस बारे में सरकार की ऐसी नीति चाहता हूं जिस के तहत मकानात लोकल बाडीज के थ्रू दे दिये जायें और ओपन अलाटमेंट बन्द कर दी जाये ।

10.00 बजे

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब को और सारे सदन को मैं यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो हुड्डा के प्लाटस के रेट्स हैं, वह 18० रुपये से 210 रुपये सुकेयर मीटर के बीच में हैं । उन्होंने यह कहा कि किसी ने एक या दो एकड जमीन देकर एक लाख रुपया लिया और जब उसको प्लाट मिला तो एक लाख 20 हजार रुपया देना पड़ा । अगर वह मकान बनाने के लिये. प्लाट या जगह, अच्छी विकसित की हुई लेना चाहेगा तो उसको जरूर फालतू कीमत देनी पड़ेगी । यह तो मुनासिब बात है क्योंकि जब उस जगह की डिवैल्पमैंट होगी तो उस जमीन की वैल्यू बढ़ेगी और उसको लेने के लिये जो रेट होगा वह तो उसे देना ही पड़ेगा । इसके अलावा हमने रेट्स बड़े वाजिब रखे हैं । छोटे आदमियों के लिए हमने 20 परसैन्ट सबसीडाइज भी कर रखे हैं ताकि गरीब लोग भी प्लाट्स ले सकें । जहां तक स्लम्ज का ताल्लुक है, यह ठीक बात है कि फरीदाबाद में कुछ नीची जगहों पर स्लम्ज बन गये है । सरकार ' ने बाकायदा वहां पर रहने वाले लोगों को मकान बनाकर दिये है । फरीदाबाद काम्पलैक्स इस काम में लगा हुआ है क्योंकि म्युनिस्पिल कमेटी उस एरिया में नही आती । फरीदाबाद. काम्पलैक्स इन गरीब लोगों को मकान आदि बनाकर देने की कोशिश कर रहा है । इसके अलावा, मैं चौधरी साहब से. यह कहूंगा कि. ये लिखकर सुझाव भेजें । जो भी ये सुझाव देंगे, उन पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि किसानों को जमीन का मुआवजा देने के बाद जब उन्हें प्लाटस दिये जायेगे तो सरकार को डिवैल्पमैंट चार्जिज लेने पडेंगे तभी वह प्लाटस देगी । स्लम्ज के बारे में जो हाउस में बात आयी है, उस बारे में एक सबमिशन मैं भी करना चाहता हूं । स्लम्ज ज्यादातर यूं बनते हैं कि हमारा जो एक्वीजीशन का सिस्टम है, उसमें पहले सैक्शन 4 का, फिर 6 का और फिर 9 का नोटीफिकेशन होता है । जो कौलोनाईजर्ज हैं, वह अन–अथोराईज्डु कालोनीज इस दौरान बसाते रहते हैं । इस तरह से ये स्लम्ज बन जाते हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिस के तहत सैक्शन 4 और सैक्शन 6 के नोटीफिकेशन्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति सेल–परचेज न करे और अन अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता रहता है, वह समाप्त हो जाए? अगर पुराना सिस्टम लागू रहेगा तो स्लम एरियाज तो बनते ही रहेंगे आप इनको समाप्त नहीं कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो पहले ही है ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : ऐसा होता है कि सैक्शन 4 का नोटीफिकेशन होने के बाद भी सेल–परचेज चलता रहता है । इसके कारण अन–अथोराईजड कालोनीज और स्लम एरियाज बनते जाते हैं । मेरी अर्ज यह है कि दफा 4 का नोटीफिकेशन होने के बाद यह कानून बन जाये कि चाहे उस जमीन का मुआवजा सरकार

न दे पाये, वहां पर सेल–परचेज नहीं हो सकेगी । दूसरे. जो झुग्गी–झोपड़ियों का मामला है, क्या उसके लिये सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जब तक 'उनको किसी दूसरी जगह पर नहीं बसाया जाता, उनके वहां से उठाया न जाये क्योंकि शहरों में आजकल बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पर झुग्गी–झोपड़ियां बन गयी हैं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे बहुत काबिल मैम्बर हैं । शायद उनको पता नहीं होगा, यह कानून तो पहले से ही बना हुआ है कि दफा 4 का नोटीफिकेशन होने के बाद कोई भी व्यक्ति जमीन की सेल नहीं कर सकता । आम तौर पर लोग बाज नहीं आते लोग सेल–परचेज करते रहते हैं और कई दफा तो लोग मकान भी बना लेते हैं । दफा 6 का नोटीफिकेशन होने के बाद भी कई लोग मकान वना लेते हैं और जब मुआवजे के लिये आते हैं तथा हम पूछते हैं कि मकान कब बनाया है तो कहते हैं कि दफा 4 या 6 के नोटी–फिकेशन के बाद । जब हम कहते हैं कि यह अन–अथोराईज्ड है तो कहते हैं कि गरीब आदमी हू । सारी बात समझते हुए भी लोग ऐसा करते हैं । इसलिए कई दफा दिक्कतें आती हैं । हमारी सरकार की कोशिश यह रहती है कि सैक्शन 4,6 और 9 का नोटीफिकेशन होने के बाद काम जल्दी पूरा हो जाये और कोई भी आदमी वहां पर मकान आदि न बना सके । दूसरी बात मैम्बर साहब ने झुग्गी । झोपड़ी और स्लम्ज के बारे में कही । जहां तक

इनका ताल्लुक है जो बड़े–बड़े लोग होते हैं, वे गरीब आदमियों से मिलकर वहां पर झुग्गी–झोपड़ियां डलवा देते हैं । उनको ये कहते हैं कि जब कम्पनसेशन या इसके बदले में दूसरी जगह मिलेंगी तो आपको भी कुछ हिस्सा देंगे । वहां पर लोग बैठ जाते हैं । जब सरकार उनको हटाने की कोशिश करती' है तो उसके लिये दिक्कत पैदा होती है । जो लोग 15 साल, 10 साल या 5 साल पुराने बैठे होते हैं, सरकार यह कोशिश करती है कि उनको कोई दिक्कत न हो । सरकार यह पूरी कोशिश करती है कि गरीब लोगों को हटाने से पहले उनको किसी दूसरी जगह पर बसाया जाये । यह हमारी सरकार की भरपूर कोशिश रहती है ।

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा प्रश्न यह है कि काफी ऐसे लोगों को मुआवजा इसलिये नहीं दिया गया है क्योंकि उसमें लैड एक्वीजीशन कम्पलीट हो गयी है और कोलैक्टर के आफिस के कर्मचारियों की वजह से उनके पैसे वहां पर पड़े हुए हैं । उनका किसी किस्म का कोई कोर्ट में भी केस नहीं है । अगर जांच करने के बाद यह पाया जाये कि यह मुआवजा उन कर्मचारियों की वजह से नहीं दिया गया है तो क्या उनको कोई सजा सरकार देने के लिये तैयार है? मेरा एक प्रश्न और है । हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी हरियाणा में जिस तरीके से विकास कर रही है, वह देखने योग्य है । बहुत सी जगहें ऐसी है जो कहने के लिये तो ग्रीन पार्क के नाम पर छोड़ दी गयी हैं लेकिन बाद में उनको भी प्लाट्स काट काट कर बेचा

जा रहा है । हमारे फरीदाबाद में कहीं–कहीं सैक्टरों में ग्रीन पार्क के लिये जगह छोड़ी गयी लेकिन बाद में उसको कम कररू दिया गया । मिसाल के तौर पर हमारे यहां पर सैक्टर–6 में चारों तरफ इंडस्ट्रीज हैं । बीच में वर्कर्ज के लिये एक ग्रीन पार्क छोड़ा गया था । पहले तो वह पार्क छोटा कर दिया गया । फिर भी उसमें इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्ज कुछ बैठ सकते थे । लेकिन बाद में वहां पर भी 800–900 गज के प्लाट्स काट कर रातों–रात चिट्ठियां इशु कर दी गयी । इसी तरह से हमारे यहां सैक्टर 23 है ।

श्री अध्यक्ष : आप स्पीच न कीजिये, सवाल पूछिये ।

श्रीमती शारदा रानी : अगर मैं उदाहरण नहीं दूंगी तो मेरा प्रश्न समझ नहीं पायेंगे । यहां पर कहा गया कि कुछ पोलीटीकल लोग एप्रोच करते हैं, कई बार कुछ दूसरे लोग भी एप्रोच करते हैं । वहां पर जिस तरीके से सैक्शन 4 का नोटीफिकेशन होने के बाद कालोनाईजर्ज ने प्लाट काटे और लोगों को बिठा दिया, उसमें मैं यह समझती हूं कि इस में किसी भी एम० एल० ए० का हाथ नहीं होगा । वहां पर इस तरीके से पूरी अन–अथोराईज्ड कालोनी बन गयी है । क्या इन सब चीजों को देखते हुए हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी को सरकार हरियाणा अर्बन डिस्ट्रक्शन अथौरिटी कहना पसन्द करेंगी?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी के काम का ताल्लुक है, उसकी जितनी तारीफ की जाये, उतनी ही कम है । मैं यह समझता है कि हुड्डा ने स्टेट में बहुत ही शानदार ढंग से काम किया है । यह बात मैं ही नहीं कहता, यह बात भारत सरकार बाकी प्रान्तों के मुख्य मन्त्रियों को कहती है कि हरियाणा मैं जाकर काम का देखो कि हुड्डा ने कितना शान– दार काम किया है । यह बात कहना मुनासिब नही है जो बहिन जी ने कही है । जहां तक इनकी दूसरी शत का ताल्लुक है कि जिन लोगों को मुआवजा नही मित्रा है उसमें उनकी अपनी कोई गलती नहो है, कर्मचारी की कोड गलतों है । मैं फिर यह बात कहना चाहता –हूं कि हौ सकता है कोई कानूनो अडचन हो जिसकी वजह से मुआवजा न दिया जा सका होगा । अगर किसी ने जान बूझकर ऐसा किया है आर उसमें चाहे किमी भी अधिकारी की कोताही होगी, इंक्वायरी के बाद जिसका भी कसर पाया गया, उसके खिलाफ जरूर ऐक्शन लेंगे औंर जैसे मैंने पहले कहा, में साथ ही यह भी कहना चाहता हू कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, उनको तीन महीने के अन्दर अन्दर मुआवजा दे दिया जायेगा । इन्होंने एक बात सैक्टर 23 के बारे में कही कि वहां पर एक पार्क था, उसके अन्दर कुछ प्लाट्स काट दिये गये । ऐसी बात नहीं हो सकती कि ग्रीन पार्क हो और प्लाट्स काट दिये जायें । शायद इनको पता नहीं होगा, वहां पर पहले. कोई ग्रीन पार्क नही होगा । जहां तक इन्होंने यह बात कहा है कि दफा 4 का नोटिफिकेशन होने के

बाद कई लोगों ने वहा पर मकान बनाये हैं । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यही नहीं, लोग तो दफा 4 का, दफा 6 का और दफा 9 का नोटिफिकेशन होने के बाद भी मकान बना लेते हैं और जब उनकी कीमत खजाने में जमा होती है तो वे यह कहते हैं कि साहब हमारा तो मकान बना हुआ है । मेहरबानी करके इसको छुडवाओ । सरकार कोशिश करती है कि किसी को कोई तकलीफ न हो और जो जायज बात हो, वह होनी चाहिये ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : मैं आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि जो मकान बनाये जाते हैं, उन्हें यह तो ठीक है कि झुग्गी–इगेंपडियों में रहने वालों को दिया जाये लेकिन साथ ही ब्लाईन्डज और विकलांगों के लिये भी सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये । क्या उनको बसाने के लिये सरकार कोई प्रोवीजन करने के लिये तैयार है, जैसा कि हांसी रेलवे स्टेशन पर कई सालों से विकलांग लोग पड़े हें?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, गरीब आदमियों को बसाने के लिए हाउसिंग बोर्ड मकान बनाता है और उनसे मुनासिब कीमत किस्तों में लेता है ताकि गरीब आदमियों को रहने का सहारा मिल सके ।

Faulty alignment of Uttawar Distributory

***1047. Chaudhri Azmat Khan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the water in the Uttawar

Disty. of Gurgaon Canal does not reach the Tail due to faulty alignment; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken to set right the said fault ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : It is understood that there is no fault in the alignment of Uttawar distributory.

चौधरी अजमल खां : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि इस डिस्ट्रीब्यूटरी की अलाइनमैंट में कोई फाल्ट नहीं है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर इसमें कोई फाल्ट नहीं है तो इस डिस्ट्रीव्यूटरी से पिछले पन्द्रह साल में कितनी जमीन की आबपाशी हुई है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने आबपाशी की फिगर्ज मांगी नहीं थी, इसलिए मेरे पास इस समय आबपाशी की फिगर्ज नहीं है । स्पीकर साहब, मैंने कैटेगौरिकली यह नहीं कहा मके इस डिस्टीव्यूट्री की अलाडनमैंट में बिल्कुल कोई नुक्स नही है । यह बात ठीक है कि पानी टेल पर कम पहुंचा है और डिपार्टमैंट ने जो इंफरमेशन दी है उसमें मुझे बताया है कि सात फुट की लिपट इस मैं है और यह लिपट इरिगेशन स्कीम है और लिपट को बिजली की निरन्तर सप्लाई नही मिलती । कई बार बिजली की सप्लाई बन्द होने के कारण टेल पर पानी नहीं पहुंचता । मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इस डिस्ट्रीब्य्टरी के लैवल और अलाइनमैंट के बारे में मौके पर जाकर पता करें और जल्दी से जल्दी मुझे रिपोर्ट करें

। स्पीकर साहब, अगर इसके लैवल और अलाइनमैंट में कोई नुक्स होगा तो हम उसको दूर करेंगे । जहां तक बिजली की सप्लाई का सवाल है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको निरन्तर बिजली की सप्लाई की जाए ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, पिछले पन्द्रह साल मे सिर्फ वर्ष 1982 और 1985 को छोड्कर कभी भी टेल पर पानी नहीं पहुंचा । मन्त्री महोदय कहते हैं कि टेल पर पानी कम पहुंचा है । ऐसी बात नहीं है । स्पीकर साहब, पानी टेल पर नदी पहुंचा । 1982 में भी पानी इसलिए पहुंचा था कि उस साल गुड़– गांव कैनाल में हमेशा से ज्यादा पानी पहुंचा था । इस तरह से नालियां बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वह बेकार गया । इनके पास रिकार्ड होगा और उससे पता लग सकता है कि कितने एरिया में आबपाशी हुई थी । अगर कोई आबपाशी हुई है तो मन्त्री महोदय बता दें । स्पीकर साहब, वास्तविकता यह है कि 1982 में भी और आज भी जोहडो को कोई पानी नहीं दिया गया । मेरा कहना यह है कि वहां पर एक टीम भेजी जाए और वह टीम मौके पर जाकर इंक्वायरी करे कि उस इलाके में कितनी जमीन की आबपाशी की गई ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, अगर मैम्बर साहब अपने सवाल में यह पूछ लेते कि पिछले सालों में कितनी आबपाशी हुई और कितना पानी दिया गया तो सारी बात साफ हो जाती । जहां तक टेल पर पानी न पहुंचने की बात है,

मैंने खुद यह माना है कि टेल पर पानी न पहुंचने की शिकायत है और लैवल ठीक न होने की शिकायत है और इसीलिए मैंने महकमें की बात को नहीं माना । मैंने उनको कहा कि यह शिकायत एक एम०एल ०ए ० साहब की है इसलिए मैं उनकी बात से संतुष्ट नहीं हूं कि लैवल ठीक है । आप हंसको दुबारा वैरीफाई करवाए । स्पीकर साहब, बारह साल से या अठारह साल से टेल पर पानी नहीं पहुँचा इस बारे में उनको मुझे शिकायत करनी चाहिए थी । लेकिन मैम्बर साहब ने कभी भी मुझे लिखित रूप में या जबानी कोई शिकायत नहीं की ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय को कई बार मैंने लिखा है कि पानी नहीं पहुंच रहा है । जब भी मेरी मीटिंग अफसरान के साथ और मिनिस्टर साहब के साथ हुई मैंने उनका ध्यान इस तरफ दिलाया है । '' क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन अफसरान की गल्ती की वजह से गल्त अलाइनमैंट हुई और सरकार का और जनता का नुक्सान हुआ है, क्या उन अफसरान के खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, अगर रिपोर्ट के आधार पर और इंक्वायरी के बाद यह पाया गया कि गल्त कंस्ट्रक्शन हुई है तो सरकार जरुर ऐक्शन लेगी । स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चौधरी अजमत खां ने यह सुझाव दिया था कि यह टेल बहुत लम्बी है इसलिए इसको दूसरी जगह से फीड कर दिया जाए । मैंने इस बारे में डिस्कशन

की है और नक्शा देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हं कि यह टेल वाकई लम्बी है इसलिए इसको किसी और जगह से फीड किया जाना चाहिए ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, यह मसला बहुत सोलो से हल नहीं हो रहा है । गुड़गांव कैनाल से यह टेल एक किलोमीटर रह जाती–है इसलिए इसके गुड़गांव कैनाल से फीड कर दिया जाए ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मौके पर इसको हम ऐग्जामिन कर लेंगे ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, अलाइनमैंट खराब होने और लैवल ठीक न होने के कारण दु:खी होकर किसानों ने पठियार अमर माइनर के बैड तोड़ दिए । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसका खर्चा किसानों से वसूल किया जाएगा या सरकार खुद वहन करेगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, ये एम०आई०टी०सी० के चेयरमैन हैं । इनके दिमाग में एम०आई०टी०सी० की कंस्ट्रक्शन की बात है इसलिए यह गल्त लैवलिंग की बात कर रहे हैं । (हंसी)

श्री भले राम : स्पीकर साहब, सदन में टेल पर पानी न पहुंचने की बात चल रही है । यहां पर कहा गया है कि लोग गल्त तरीके से कट लगा लेते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना

चाहता हूं कि क्या सरकार ने टेल पर पानी पहुंचाने के लिए कुछ इंतजाम किया है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले दो तीन साल में वे इन्तजामात किए हैं जिनसे किसानों को उनका मुनाफा पहुंचना शुरु हो गया है और पिछली फसल में और इस खरीफ फसल में भाखड़ा से, यमुना से और गुड़गांव कैनाल से पानी टेल पर पहुंचा हैऔर यही कारण है कि तीस प्रतिशत से लेकर 130 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई है । पानी की मिकदार में और इरीगेशन में वृद्धि होने के कारण पिछले साल और इस साल रिकार्ड उत्पादन हुआ है और इस साल खरीफ की फसल का उत्पादन भी बहुत ज्यादा हुआ है. । यह बात ठीक है कि वैदर का भी उत्पादन बढ़ाने में हाथ है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पर टेल पर इस साल और पिछले साल पानी न पहुंचा हो तो वहां का नाम मुझे मैम्बर साहिबान बता दें, मैं फौरन ही उस पर कार्यवाही करूंगा । इस बारे में अभी चौधरी अजमत खां ने भी कहा है कि 1982 और 1985 में उस डिस्ट्रीब्यूटरी में टेल पर पानी पहुंचा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1053

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम बिलास शर्मा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Construction of drains in Safidon

***105 1. Chaudhri Kundan Lal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following drains in Safidon

1. Kalwa-Bhuran Drain ;

2. Ram Nagar Drain ;

3. Parana Drain; and

(b) if so, the time by which the said drains are likely to be constructed ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) :

(a) Yes.

(b) Substantial work has already been done on Parana drain which is likely to be completed by 30th June, 1986. Decision has also been taken to construct Kalwa Bhuran and Ram Nagar drains. However, work thereon will commence after land has been acquired for the purpose.

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, स्वयं मन्त्री महोदय ने यह सारा बाढ का इलाका देखा है । खासतौर पर मेरे हल्के के अन्दर रोहडू की हरिजन बस्तियों में बाढ़ का पानी काफी भर जाता है और इसी कारण से हाडवां गांव के अन्दर लडाई का

अन्देशा भी हो गया और आदमियों के मरने का भी खतरा हो गया था । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इन सभी ड्रेनज को मुकम्मल करवाने का काम जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि पड़ाना ड्रेन इस इलाके में सब से बड़ी ड्रेन है और लगभग 40 लाख रुपया उसकी लागत पर खर्च होने की संभावना है । इस ड्रेन का सैक्शन 4 और सैक्शन 6 का नोटीफिकेशन इशू हो गया है । प्रोजैक्ट ऐस्टी– मेट्स सैक्शन हो गये हैं और काम आरम्भ कर दिया गया है । इस की टोटल लैन्थ 92 हजार फीट है । इसके अलावा आऊटफाल पोर्शन की रीच में आर०डी० 52 हजार से आर०डी० 92 हजार तक इनके एरिये में काम तकरीबन तकरीबन कर दिया गया है और एक यूनिट सैक्शन, आलरेडी खोल दिया गया है । बरसात सीजन आरम्भ होने से पहले हमारा इस काम को पूरा करने का पक्का इरादा है । ड्रैग लाईन के द्वारा हम इसकी खुदाई करवा रहे हैं । जहां तक दूसरे काम का संबंध हैं, उस बारे में मैं बता देता हूं कि जीन्द – गोहाना सड़क पर एक–ऐरजिसटिंग ब्रिज है उसको बी०एंड०आर० वाले री–माडल कर रहे हैं और उसका जो पम्पिग अरेन्जमैंट है, वह 55 क्यूसिंक्स की बजाये 155 क्यूसिक्स कर रहे हैं ताकि उसकी पूरी कैपेसिटी को

अपग्रेड कर सकें । हम यह सारा काम अगले बरसात सीजन से पहले पहले पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हू कि इन सभी ड्रेन्ज के लिये आज से चार साल पहले जमींदारों की काफी जमीन ऐक्वायर की गयी थी लेकिन आज तक उन जमींदारों को इसका मुआवजा नहीं मिला है । क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि कब तक उन जमीदारों को उनकी जमीनों का मुआवजा दे दिया जाएगा? इस संबंध में जमींदार लोग और मैं स्वयं भी कई बार मन्त्री महोदय से मिल चुका हूं । साथ में जिन लोगों की फसलें बरबाद हो गयी हैं, क्या उनका मालिया माफ भी किया जाएगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुआवजे का सवाल है, उस बारे. में मेरा यह कहना है कि जैसे जैसे मेरे नोटिस में इस तरह की बातें चाहे जमींदार लाएं, चाहे कोई मैम्बर या मन्त्री महोदय या डिपार्टमैंट वाले लाकर दें, मैं तुरन्त इस बात का प्रयत्न करता हूं कि लोगों को उनकी जमीनों का सही मुआ– वजा सही समय पर दिया जाये । साथ में हमारा यह भी प्रयत्न होता है कि डिपार्टमैंट वाले जल्दी ही एल०ए०ओज ० के पास मुआवजा दाखिल करवा दें ताकि संबंधित लोगों को रुपया मिल सके । इस बारे में, मैं हर महीने सफीदो, जुलाना व जीन्द एरियाज में संबंधित विभाग के साथ मीटिंग भी करता रहता हूं और इन मीटिंगों में हर प्रकार की बातों को रिव्यू किया जाता

है । किसी स्पेसिफिक केस का मुझे पता नहीं । मैम्बर साहेबान यदि मुझे बता दें तो मैं स्वयं कोशिश करूंगा कि विभाग के पास जो मुआवजे के केसिज पैंडिंग पड़े हुए हैं, जो अभी दाखिल नहीं हुए हैं, उनको दाखिल करवा के जल्दी ही मुआवजा दे दिया उना सके । जहां तक लैन्ड रैवेन्यू और वाटर चार्जिज का सवाल है, इस बारे में सरकार हमेशा नैचुरल कैलेमिटी के बाद ही छूट अनाऊंस करती है । माननीय सदस्य यदि कोई स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम पता करके बता देंगे । अव्वल तो ऐसे केसिज में मालिया माफ कर दिया' गया होगा या फिर पोस्टपोन कर दिया गया होगा । जिस प्रकार की सिचुएशन होती है सरकार उसके अनुसार ही केसिज का निपटारा करती है ।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर लोगों को पीने का पानी खालों व नालों के जरिये सप्लाई किया जाता है लेकिन वे खाल ढके हुए नही होते । लोग उनमें गन्दे हाथ मारते हैं, जिसके कारण पानी से बदबू, मारने लगती है । इससे गन्दगी फैलती है और बीमारियां फैलने का भय रहता पै । क्या मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान देकर इन नालो व खालों को कवर करवाने का कष्ट करेंगे ताकि इनमें कोई हाथ न डाल सके और लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हू कि जो नाले वगैरह हैं, उनको पब्लिक हैल्थ विभाग बनाता णै, इरीगेशन

विभाग तो उनको केवल पानी देता है । ज्यादातर नाले पक्के हैं । अगर कोई नाला कच्चा है और माननीय सदस्य अगर इस बारे में संबंधित मन्त्री या विभाग को कहेंगे तो अवश्य ही उचित कार्यवाही होगी ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, यहां –पर जिन तीन ड्रेन्ज का जिकर चल रहा है ये तीनों ड्रेन्ज मेरे हल्के के इसापुर खेड़ी, छापड़ा वगैरह में से होकर गुजरती हैं जिस कारण से मेरे हल्के में कई बार फ्लड आता रहता है । इसलिये मेरा आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि या तो इन ड्रेन्ज को कंवर्ट कर के कहीं और डाला जाए, या फिर इन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए । कोई न कोई तरीका अवश्य निकाला जाए ताकि मेरे हल्के में फ्लड न आ सके ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : दिल्ली वाले भी यही कहेंगे कि दिल्ली की बजाये पानी कहीं और ले जाओ । सर, इन सब का लैवल एक सार यमुना के अनुसार है चाहे गुहाने का है, चाहे जीन्द का है, चाहे सोनीपत का है और चाहे रोहतक का है । इनके एरिया में 1983 में काफी फ्लड आता था, इनको इस बात का पता है लेकिन अब हमने सारी ड्रेन्ज री–माडल कर दी हैं । अब ऐसी स्थिति फिर हद–नके इलाके में नहीं आएगी । छोटे मोटे काम तो हो जाएंगे लेकिन पानी जाने का रास्ता तो एक ही है । ड्रेन नम्बर 8 और सप्लीमैंट्री डेरन्ज का पानी यमुना में ही जाता है ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नलवी, शाहबाद प्रोजैक्ट्स की लाईनिंग फाईनल होने जा रही हैं

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, यह ड्रेन्ज की बात है, लाइनिंग की नहीं । आप बैठ जाइए ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : एक ही बात है जी । आपके हल्के के मुताल्लिक

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय ने मेरे इलाके में काफी चक्कर लगाये हैं और पिछली मीटिंग में इन्होंने जिन अफसरों की ड्यूटी लगायी थी उन्होंने जवाब दे दिया है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है जिससे मुझे और मेरे किसान भाइयों, जिनका मुआवजा रहता है को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । क्या वे. बताएंगे कि यह काम कब तक पूरा हो जाएगा और लोगों को मुआवजे का पैसा कब तक मिल जाएगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एफ० एम० साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और ये भी करें । हमारी यह कोशिश भी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके और यह सारे काम निपटाये जा सकें ।

मास्टर राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज का पोल्युटिड वाटर मेरे गांव कानजू, रादौर, जुव्वत्र, दोलड़ा और कुरदवन घोड़ी वगैरह के साथ साथ से होकर वैस्टर्न–यमुना कैनाल में गिरता है और यह पानी रास्ते में खड़ा रहता है जिससे बड़ी गन्दी बदबू आती है और बीमारियां फैलने का अन्देशा रहता है । अगर कोई मवेशी पानी पाई जाए तो उसकी मौत हो सकती है । तो क्या मिनिस्टर महोदय यह बताएंगे कि इसके लिये वे कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे ताकि यह पानी रास्ते में न रुके और सीधे वेस्टर्न यमुना कैनाल में ही जाए ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : इसकी सूचना हमारे पास अभी तक नहीं है । दो साल पहले मैंने मौके पर भी जा कर देखा था । मैं इनकी बताना चाहता हूं कि सरकार पहले ही इस बारे में जागरुक है कि इस तरह की कोई बात न होने पाए । वैसे यह सवाल तो सफीदों ड्रेन के बारे में पूछा गया था । इस सवाल से इस बात का कोई संबंध नहीं है ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न उठाना–

23– 1– 1986 को राज्य में 'रास्ता रोको' आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने सम्बन्धी

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक ऐडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया था । स्पीकर साहब, जब हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों के हितों –की रक्षा नहीं कर सकी तो 23 जनवरी को हरियाणा के लोगों ने सड्कों पर आकर अपने गुस्से जाहिर किया । हरियाणा की सड्कों पर उस दिन एक पहिया भी नही गुजरा । लोगों ने रास्ता रोक कर और बाजार बन्द करके अपनी भावनाएं व्यक्त की । हरियाणा सरकार की जो ..... थी उसके बारे में लोगों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया ।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द रिकार्ड न किया जाए ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, 23 जनवरी को हरियाणा के लोगों पर गोलियां चलाई गई और उसमें तीन लोगों की हत्या हुई जबकि वहां पर गोली चलाने का कोई ऐसा मौका नहीं था । कैथल के पास प्योदा गांव की घटना को लेकर आज भी एच०सी०एस० अफसर आदोलित हैं । अखबार में भी आया है कि पुलिस ने जबरदस्ती जे०पी० कौशिक से दस्तखत करवाए । ये अफसर हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी साहब से भी मिले हैं । ला एण्ड आर्डर की हालत इतनी खराब है कि लगता है ..कि हरियाणा में कोई सरकार ही नही है । आज हालत यह है कि मन में आए तो गोली चला दें या और कुछ कर दें । मन में आए तो यह किसी पर गोली चला दें, लोग मर जाएं, कोई नहीं पूछता । हमने अपने मोशन में कहा है कि उस पर आपकी इजाजत से डिस्कशन

हो और इस इसीडैट की हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवाई जाए ।

मास्टर शिव प्रशाद : स्पीकर साहब, हमने आपकी सेवा में आज सवेरे जो ऐडजर्नमैंट मोशन भेजा है सबसे पहले उसको लिया जाता और बाकी काम रोके जाते । हमारे देश में महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलने के लिए नारे लगते हैं और कहते भी हैं । इस बात को लेकर हरियाणा की जनता ने 23 तारीख को रास्ता रोको आन्दोलन इस शान्तिपूर्वक तरीके से किया जिसकी कल्पना भौं नहीं की जा सकती थी । अगर कही गडबड हुई तो वह हरियाणा सरकार और पुलिस. की वजह से हुई । तीन लोगों की मुत्यु पुलिस की गलती के कारण हुई । हरियाणा के हितों को हम भी चाहते है और मुख्य मन्त्री भी इस बारे में कहते रहते हैं लेकिन ये तीन आदमी भो हरियाणा के हितों के लिए ही शहीद हुए हैं । इस सरकार ने सबमें बड़ी .....की । हम चाहते हैं कि कल इन तीन आदमियों को भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा न करके हरियाणा सरकार ने अपने फर्ज को पूरा नहीं किया । हम चाहते हैं कि इन तीन लौगों ने जो शहादत की है इस बारे में जुडिशियल इंक्वायरी करवाएँ जाए जिसे हाई कोर्ट का मौजूदा जज करे । जो अफसर कसूरवार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए । अन्त मे मैं यही कहूंगा कि सब से पहले हमारे मोशन पर अनुमति प्रदान की जाए ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, सदन को चलाने के लिए हमने कुछ नियम छाप रखे हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वे मैंने पढ़ रखे हैं । आप कृपया बैठिए ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : सर, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं.

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, आप हमारे मोशन को ऐडमिट कर लीजिए उसके बाद इनको भी कहने का मौका मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा । उसके बाद ही मन्त्री जी बोल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : जब मैं फैसला करूंगा तो दोनों पार्टियों को सुन कर ही करूंगा । आप बैठें ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, ये कैसे बोल सकते हैं । क्या' इन्होंने किसी ऐडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है । मैं आपकी सेवामें अर्ल कर रहा हूं कि हमने रूल 66 के तहत एक एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दियाथा । मैं. आपकी इजाजत से बोल रहा हूं लेकिन क्या आपने मन्त्री महोदय को बोलने की इजाजत दी है और क्या उन्होंने इस बारे में कोई नोटिस दिया है? ये कैसे बोल सकते हें?

श्री अध्यक्ष : इस समय मैंने आपको –बोलने की इजाजत नही दी है, आप बैठ जाएं ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि .....

श्री अध्यक्ष : मेरी परमिशन के बगैर जा 'बोला जाएगा, वह रिकार्ड पर नहीं आएगा ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सिर्फ एक मिनट में यह कहना चाहूंगा कि इनका यह ख्याल है कि रूल के तहत अगर ये कोई मोशन दे दें और उसकी एडमिशन 'के लिए सबमिशन करें तो उस बारे में केवल यही बोल सकते हैं दूसरे लोग गूंगे रहेंगे हाउस में इस बारे में और किसी को कहने का कोई हक नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है । दूसरी वात मैं यह कहुंगा कि यहां पर बी०जे०पी० के सदस्य बोले । उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि तीन आदमी शहीद हुए और स्टेट में ला एण्ड आर्डर नहीं है इसलिये उनका मोशन एडमिट कर लिया जाए । उन्होंने यह भी कहा कि कल के कडोलैसं मोशन में इन तीन शहीदों का नाम आना चाहिए था । मैं यह कहना चाहता हू कि अपोजीशन के विधायकों को प्रजातन्त्र में यकीन नहीं है । अगर इनको सही मायनों में दु:ख होता तो कल ये हाउस में आ सकते थे और अपना मोशन या सुझाव दे सकते थे । मगरमच्छ के आबू बहाने की बजाए इनके पास कुछ नही है । इनको अपनी पोजीशन का ही पता नहीं है । आज हरियाणा में दो इशू हैं जिनको लेकर इन्होंने रास्ता रोको आन्दोलन किया । एक इशू पानी का है और दूसरा टैरेटरी का है । श्रीमती इंदिरा गांधी ने

1970 में एवार्ड दिया जिसके जरिए फाजिल्का अबोहर हरियाणा को दिए और चण्डीगढ़ पंजाब को दिया । उस वक्त यही लोग थे जिन्होंने लोगों को मरवाया । इन्होंने उस वक्त स्ट्डैट्स और लोगों को भडकाया और दर्जनों गरीब लोग मरे और ये लोग इनके अपने इलाके में मरे । फिर– पहली बार 1976 में एवार्ड आया पानी के लिए । फिर 1981 में जब दूसरी बार एग्रीमैंट हुआ तो इन्हीं लोगों ने उसकी मुखालिफत की । लेकिन आज 15 साल के बाद इनकी अकल का ताला खुल गया । आज ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी का एवार्ड लागू करो और 35 एम०ए०एफ ० पानी दो । उस समय इसी एवार्ड की इन्होंने मुखालिफत की थी । इस हिसाब से कल को ये कोई और बात भी कह सकते हैं । इसलिये इस एडजर्नमैंट मोशन को एडमिट करने की कोई वजह नहीं है । अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए ये लोगों को सड्कों पर लेकर गए जबकि हरियाणा के हितों को कोई खतरा नहीं था । उस समय न कोई एवार्ड आया था और न ही कोई दूसरा फैसला हुआ था । हरियाणा सरकार और दिल्ली की सरकार इस बारे में पूरी तरह जागरूक है और हरियाणा के हितों के लिए पूरे प्रयत्न कर रही है । इन द्वारा मगरमच्छ के आसू बहाने का इससे फालतू नही है । ये असैम्बली में आकर लोगों के हितो के लिए नहीं लड़ सकते, ये हमेशा असैम्बली से बाहर लोगों को मिस–गाइड करते हैं ।

श्री देवी दास : स्पीकर साहब, अभी सुरजेवाला साहब ने फरमाया कि अगर शहीदों से हमारा इतना प्यार था तो हम कल

उनके लिए यहां आते और उनको श्रद्धा जलि देते । हमारा कल का यहां आने का प्रोग्राम नही था लेकिन आज आते ही हमने उनके बारे में कहा है । मैं इनको कह ना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस के लोगों को ही शहीदों को श्रद्धांजलि देने का हक नहीं है, बल्कि हमको भी है ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी रुलिंग चाहता हूं। जिस समय श्री राम बिलास शर्मा जी और मास्टर शिव प्रशाद जी बोल रहे थे तो उस समय आपने यह कह दिया कि कुछ नहीं लिखा जाएगा और जब चौधरी शमशेर सिह सुरजे वाला जी बोले तो उनकी सारी बातें रिकार्ड हो गई ।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप तो काफी पुराने लैजिस्लेटर हैं । जब कोई मै म्बर चेयर को डिस–ओबे करेगा तो उसके लिए चेयर के पास यही अख्तियार है कि वह न लिखा जाए । जो कुछ मेरी परमिशन से बोलेंगे वह लिखा जाएगा और जो मे री परमिशन के बगैर बोलेंगे वह नही लिखा जाएगा ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, यदि सवाल ही नही लिखा जाएगा तो उसका जवाब कैसे लिखा जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, वह तो मुझे पता है कि क्या लिखा जाना है और क्या नही लिख जाना है ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, मैं आप की इजाजत से कहना चाहूंगा । अभी सुरजेवाला सा हब आज से 15

साल पहले की बात कर रहे थे कि उस समय हमारी तरफ से ऐजीटेशन किया गया । लेकि न मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि उस समय ये कांग्रेस पार्टी में थे ही नहीं, उस समय तो ये आगू थे ।

Mr. Speaker : Mr. Ram Bilas Sharma, I have disallowed your motion on the ground that the matter relates to an ordinary administration of Iaw which cannot be raised through an adjournment motion vide Rule 68(x) of the Assembly Rules.

वाक आउट्स

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, अगर आप हमारी ऐडजर्नमैंट मोशन एडमिट नहीं करते और इस हाउस में हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं की जाती तो हम एज–ए–प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं । (शोर)

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सर्वश्री राम बिलास शर्मा, शिव प्रशाद, फतेह चन्द विज तथा देवी दास सदन से वाक आउट कर गए) ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं भी इनके साथ ही वाक आउट करता हूं, लेकिन वापिस आने के लिए ।

(इस समय कांग्रेंस (जे०) के माननीय सदस्य, श्री निहाल सिह भी सदन से वाक आउट कर गए) ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : अब गवर्नर साहब के ऐड्रैस पर बहस होगी । श्री ईश्वर सिंह ।

Chaudhri Ishwar Singh (Pundri) : Sir, I beg to move—

'That an Address be presented to the Governor in the following terms :-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor *for* the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 17th February, 1986".

स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय ने कल विधान सभा में जो अभिभाषण दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । उन्होंने अपने अभिभाषण में हरियाणा की प्रगति की तस्वीर खीची है और कहा है कि हरियाणा स्टेट सारे हिन्दुस्तान में सबसे फर्स्ट है । प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि हरियाणा की प्लान पर–कैपिटा के हिसाब से अगर सारे हिन्दुस्तान की पर–कैपिटा एवरेज ली जाए तो उससे लगभग डबल. है । वह लिखते हैं–

"It may be seen from the following table that the per capita plan outlay of Haryana is substantially higher than all the States 'average."

स्पीकर साहब, थ्री ऐनुअल प्लान 1966 से 1969. तक हरियाणा की पर– कैपिटा आउटले 91 रुपए और सारे हिन्दुस्तान

की 61 रुपए । फौरथ प्लान 1969 से 1974 तक हरियाणा की पर–कैपिटा आउटले 35 छ रुपए और सारे हिन्दुस्तान की 142 रुपए । फिफथ प्लान 197 न से 1979 तक हरियाणा की पर–कैपिटा आउंटले 599 रुपए और मारे हिन्दुस्तान की 338 रुपए । सिकस्थ प्लान 1980 से 1985 तक हरियाणा की पर कैपिटा आउटले 1793 रुपए और सारे, हिन्दुस्तान की 872 रुपए । ऐनुअल प्लान 198०–81 में हरियाणा की 249 रुपए और सारे हिन्दुस्तान की 134 रुपए, ऐनुअल प्लान 1981–82 में हरियाणा की 289 रुपए और सारे हिन्दुस्तान की 152 रुपए, ऐनुअल प्लान 1982–83 में हरियाणा की 319 रुपए और सारे हिन्दुस्तान की 171 रुपए, ऐनुअल प्लान 1983–84 में हरियाणा की 405 रुपए और सारे हिन्दुस्तान की 199 रुपए, ऐनुअल प्लान 1 984– 85 में हरियाणा की 428 रुपए और सारे हिन्दुस्तान की 219 रुपए, सैवन्थ प्लान 1985 से 1990 तक हरियाणा की 2888 रुपए और सारे हिन्दुस्तान की 1442 रुपए और ऐनुअल प्लान 1985–86 में हरियाणा की 478 रुपए और सारे हिन्दुस्तान की 234 रुपए । यह ऐवरेज रही है । इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में प्रगति के लिहाज से सबसे आगे है । मैंने आपके सामने जो फिगर्ज दी हैं वे अपने आप बोलती हैं कि हरियाणा ने कितनी तरक्की की है । हरियाणा ने जितनी तरक्की की है उसके लिए प्रदेश में अमन और शांति. बहुत जरूरी है । हालांकि हमारे पड़ौसी प्रदेश पंजाब में काफी गड़बड़ होती रही है और अब भी गड़बड़ होती है । वहां पर अब भी हालात नार्मल नहीं हैं क्योंकि पंजाब में हर रोज कोई

न कोई इनोसैट आदमी एक्क्रीमिस्टसं की गोलियों का शिकार हो जाता है । लेकिन हरियाणा प्रान्त में ला एण्ड आर्डर की पोजीशन बहुत अच्छी है । हरियाणा में ला एण्ड आर्डर की पोजीशन अच्छी होने के कारण यहां पर लोग इंडस्ट्रीज भी लगाना चाहते हैं । जो लोग हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं उनको थोड़ी 'सी बिजली के बारे में झिझक है । लेकिन हरियाणा सरकार ने पांच साला प्लान में इतनी स्कीमें बना दी हैं कि आने वाले चार सालों के बाद हरियाणा के अन्दर 24 घंटे बिजली की सप्लाई रहेगी । इस बारे में मैं आपके सामने फैक्टस एण्ड फिगर्ज देना चाहूंगा लेकिन इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा और हरियाणा सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहुंगा कि किसी भी एक्स्ट्रीमिस्ट की हरियाणा के अन्दर दाखिल होने की हिम्मत ही नही हुई और न ही हरियाणा के अन्दर कोई ऐसा वाका हुआ । यदि कहीं पर कोई ऐसा वाका हुआ भी तो उसको उसी वक्त पकड़ लिया गया । किसी भी ऐक्स्ट्रीमिस्ट की हरियाणा में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई । इसके अलावा स्पीकर साहब, मै कहना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले मैथ्यू कमीशन का अवार्ड भी आया है । उसके बारे में लोग अपने अपने ढंग से और अपने अगने एंगल से इन्टरप्रैटेशन करते हें । इसी तरह से बालकृष्ण इराडी कमीशन नहर के पानी के डिसप्यूट के लिए मुकर्रर हुआ है । उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब ने इस बारे में काफी कोशिश की है । सुरजेवाला साहब दोनों मामलों के इन्चार्ज भी हें । उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है और

पूरी हिम्मत के साथ जिस तरह से वकील अपने केस के बारे में बोलते हैं उसी तरह से इन्होंने इस बारे में बात की है । स्पीकर साहब, जैसे अपोजीशन के मैम्बर साहेबान बाहर कहते फिरते हैं उससे कुछ नही बनता । अपोजीशन के भाईयों ने कहा है कि हमने रास्ता रोको आन्दोलन किया उसके कारण चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं गया । वे इस बात का इस तरह से क्लेम करते हैं लेकिन उनकी यह बात बिल्कुल गलत है और उनके ईस तरह की बात कहने से कुछ नहीं बनता । जिस समय हरियाणा प्रान्त में सवा दो साल जनता पार्टी का राज रहा और दिल्ली में भी राज रहा तो उस वक्त उन्हेंने इस बारे में कितने ऐजीटेशन किए । क्या उस वक्त मेरे अपोजीशन के भाईयों ने एस०वाई०एल० नहर को खोदने के लिए एक भी कस्सी मारी, यह उनके मगरमच्छ के आसू हैं, सारा पोलिटिकल स्टंट है और ये चाहते हैं कि किसी तरह से तवा तपता रहे जिस तरह से जमींदार लोग बारिश के बाद अपने खेतों में आल दबा देते हैं । क्योंकि इलैक्शन का सवा साल रहता. है इसलिए मेरे अपोजीशन के भाई चाहते हैं कि किसी तरह से तवा गर्म रहे । लेकिन ये लोग इतने दिन तक लोगों को कहां तक बहका सकते हैं । अभी बालकृष्ण इराडी कमीशन का भी फैसला आएगा और एस०वाई०एल० नहर के पानी का फैसला भी आपके सामने अभी पांच महीने के अन्दर आ जाएगा । अपोजीशन के भाई कहां तक लोगों को बहका सकते है । स्पीकर साहब, हमारी स्टेट में जो डिवैल्पमैंट के काम हुए हैं वह आपके सामने हैं । मैथ्यू कमीशन ने तो हमारे स्टैंड को स्पोर्ट किया है और राज्यपाल

महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि अबोहर और फाजिल्का भी हमारे इलाके हैं । स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी यही इनटैंशन थी कि अबोहर औररू फाजिल्का का एरिया जब हरियाणा को मिलेगा तब चण्डीगढ़ पंजाब को मिलेगा । इस समय भी ऐसा ही है कि जब चण्डीगढ़ पंजाब को जाएगा तो अबोहर और फाजिल्का के एरियाज हमें मिलेगे । राज्यपाल महोदय ने आखिर में कहा है कि haryana has a claim not only on the towns of Abohar and Fazilka but also on at least 83 villagesof that area which are Hindi Speaking, क्योंकि एक गांव कटीग्यूटी के हिसाब से नहीं आया । इसलिए मैथ्यू कमीशन ने कहा है कि मैं यह गांव नहीं दे सकता यह गवर्नमैंट आफ इंडिया का काम है वह इस गांव के बारे में कुछ भी फैसला करे और हरियाणा को हिन्दी स्पीकिंग एरिया देने का कोई भी रास्ता निकाले । श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यही इन्टैशन थी कि यह गांव भी हरियाणा को दिया जाए तो यह जो हमारा स्टैड है इससे उसकी पुष्टि होती है । इसी तरह से एस ०वाई०एल० नहर के पानी के बारे में इधर उधर की बातें होती हैं कि पानी देने के लिए है ही नहीं । इस तरह ये पंजाब की बोली बोल रहे हैं । ये लोग हरियाणा के हितों की बात नहीं करते ।. ये तो चाहते हैं कि हरियाणा को कुछ न मिले ताकि यहां की पब्लिक रूलिंग पार्टी के खिलाफ हो जाये । इनकी नीयत इसी ढंग की है । यहां जो तरक्की हुंई है वह बहुत अधिक हुई है । मैं इकबाल कवि की कही हुई एक बात कहना चाहूंगा । इकबाल कवि ने एक जगह कहा है—

चमन जारे सियास ने, खामोशी मौत है बुलबुल,

बुलबुल यहां की रस्में, वफा आह वो फंगा तक है ।

तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपने केस को जिस ढंग से प्लीड करना चाहिए था, उसी ढंग से प्लीड किया । लोक दल वालों ने असैम्बली से भी इस्तीफे दे दिए । जबकि उनको चाहिए तो यह था कि वे यहां आकर बोलते और अपना स्टैण्ड लेते । अब ये कहते हैं कि रूलिग पार्टी वालों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए । अगर सभी इस्तीफा दे देंगे तो यहां पर इस केस को कौन प्लीड करेगा, कौन हरियाणा के हितों की रक्षा करेगा? हरियाणा के हितों की रक्षा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी और उनकी माता स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो ने पूरी तरह से की है । इन्दिरा गांधी जी ने तो हरियाणा के हितों की रक्षा करते हुए कपूरी गांव में जा कर एस०वाई०एल० नहर का कस्सी मार कर उदघाटन किया था । इस नहर के निर्माण के लिए 110 करोड़ रुपये और अढ़ाई करोड रुपये की मशीनरी हरियाणा ने अपने हिस्से की पंजाब को अब तक दी है । इसके अलावा 90 करोड़ रुपये का हिस्सा भी इस साल के लिये प्रोवाइड किया गया है । इसके लिए प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने मूख्य मन्त्री को आश्वासन दिया है कि वह हर किस्म की सहायता करेंगे । उनका अब भी यही विचार है यह नहर समय के अन्दर बन कर तैयार हो, चाहे इसके लिए एक–एक पुल का अलग–अलग ठेका दिया जाए चाहे अलग–अलग थोड़े–थोड़े हिस्से का ठेका दिया जाये । इस

बात को आप भी जानते हैं कि एक सूबा दूसरे सूबे के मामले में दखल नहीं दे सकता । इस काम को सैन्टर ही करवा सकता है । अब सैन्टर ही हमें समय पर नहर बनवा कर देगा और हमें पानी भी देगा । हरियाणा के लिए पानी और बिजली की और भी दूसरी बहुत ' सारी स्कीमें हें । बिजली के बारे में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा में दरिया तो कोई है नहीं । यमुना से हमें पानी आता है और उस पर ताजेवाला के बीच–में और दादू– पूरे के बीच में 3 हाईडल के 16– 16 मैगावाट के हमारे बिजली घर बनने हैं । इनमें से 2 ए और बी तो अन्डर कन्स्ट्रक्शन हैं । ए पावर हाउस जो 16 मैगावाट का है, इसी 31 मार्च तक चालू हो जायेगा और दूसरा थोड़े दिनों बाद यानि बी पावर हाउस की भी बिजली काम में आ जाएगी। तीसरा सी पावर हाउस भी 2 सालो में काम में आ जायेगा । इसके अलावा, 10 मैगावाट का प्रोजैक्ट दादूपुर में और बनेगा । इसके अलावा हथनी कुण्ड बैराज भी बन जायेगा, इसको बनने में अभी तीन साल लगने हैं । यह 16 मैगावाट का या इससे ज्यादा मैगावाट कैपेसिटी का बिजली घर बन सकेगा । इनके अलावा, बहुत सारी छोटी–छोटी माइक्रो हाइडल की रुकीमें भी हैं जो झालों पर बनाई जाएगी । जैसे सोनीपत जिले में ककरोई, करनाल जिले में खेड़ी और बडौता आदि की स्कीमें बनाई जा रही हैं । इसी प्रकार की और भी बहुत जगहों पर ऐसी स्कीमें बनाई जाएंगी । फरीदाबाद में 195 मैगावाट और पानीपत में 220 मैगावाट यानी हमारे पास अब तक 415 मैगावाट औन पावर है, 1446 मैगावाट में से । बाकी का

औन–औफ तो हमारे हाथ से बाहर की बात है । दिल्ली भी हमारे हिस्से की कुछ बिजली को ओवर ड्रा कर लेती है । हमारी ही नहीं बल्कि पंजाब और दूसरी स्टेट्स की बिजली को भी ओवर ड्रा कर लेती है । मुराद नगर के अन्दर भी सैन्ट्रल गवर्नमैंट एक अपना प्लांट बनाने जा रही है ताकि वह प्लांट दिल्ली को फीड कर सके । ऐसा हो जाने पर हमारा पीछा छूटेगा । इसी तरह से नग्गल और पानीपत के जो फर्टीलाईजर प्लांट हैं इनमें भी बहुत बिजली लगती है । उनके लिए भी इन प्लांटों ने अपनी स्कीम बना ली है कि 2 सालों में वे भी अपने प्लांट बिजली के बना लेंगे और उन्ही प्लांटों से अपनी बिजली इस्तेमाल करेंगे । दूसरे सैन्ट्रल प्रोजैक्ट बहुत से चले हुए है । उन प्रोजैक्टस में भी हमारा हिस्सा है । कहने वाले कह देते है कि नाथपा झाकड़ी का प्रोजैक्ट हमने खो दिया है । नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट हमने खोया नहीं है । इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि न हमारे पास इतना पैसा था कि वह हम बना सके और न हिमाचल प्रदेश के पास इतना पैसा है कि वह इस प्रोजैक्ट को पूरा. कर सके । इस प्रोजैक्ट को सम्भाल सके । यह तो बहुत खुशी की बात है कि इस प्रोजैक्ट को सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने अपने हाथ में ले लिया है । हमें पूरी– प्री उम्मीद है कि सैन्टर इस प्रोजैक्ट को बहुत जल्दी पूरा करेगा और हमारे हिस्से की 35 प्रतिशत बिजली हमें मिलेगी । वैसे अभी सैन्टर ने कोई डिसीजन नहीं किया है कि किस को कितनी बिजली मिलनी है । यह जरूर है कि इस प्रोजैक्ट से हमें बिजली मिलेगी । इसके अलावा हिमाचल के भाभा प्रोजैक्ट से. भी हमे 60 मैगावाट बिजली

आनी है और भी दूसरे जो सैन्टरल प्रोजेक्टस हैं उन सभी से हवे अपने हिस्से की बिजली मिलनी है । संगरौली, बैरास्ल, रिहाड और चमेरा आदि सभी जगहों से हरियाणा को बिजली आनी है । इसके अलावा हम अपने भी कुछ और प्रोजैक्टस लगायेंगे' । इसी तरह से यमुनानगर का 420 मैगा– वाट का प्रोजैक्ट बनने जा रहा है और एक और 420 मैगावाट का प्रोजैक्ट 8 वीं प्लान में बनाने की योजना है क्योंकि इस सम्बन्ध में कनाडा से चीफ मिनिस्टर साहब को कोशिश से सौपट लोन मिलने की उम्मीद है । अभी पिछले दिनों साठे साहब जब पानीपत में आये थे तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वह हर मुमकिन मदद करेंगे । इसी तरह से हमारे फरीदाबाद और पानीपत के जो थर्मल प्लांटस हैं वे. बहुत लोड फैक्टर के हैं । वे इतनी बिजली पैदा नहीं कर सकते कि सारी जरूरत पूरी कर सके । फरीदाबाद प्लांट की तो मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी है । उसको चेन्ज करने के लिए, मौडेरनाईज करने के लिए पैसा भी इस प्लान में रखा हुआ है और सैन्टर भी इसमें कुछ मदद दे रहा है । इनकी मशीनरी चेन्ज होने से दोनों प्लांटों का लोड फैक्टर ठीक ढंग से हो जायेगा । दूसरे हम अपने लाईन लौसिज भी कम करेंगे । इसी तरह से हरियाणा में इस पांच साला प्लान में 1113 मैगावाट नई बिजली पैदा को जायेगी । हमारे यहां 8 मिलियन एकड़ फीट टयूबवैल्ज के लिये अन्डर ग्रांउड वाटर है जिसमें से 6 मिलियन एकड़ फीट यूटेलाईज हो चुका है । अब सिर्फ 2 मिलियन एकड़ फीट पानी बाकी है । हमारे कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में दो–दो और तीन–तीन एकड' पर टयूबवैल्ज

लग चुके हैं । मेरे कहने का मतलब यही है कि आखिर सैचुरेशन प्वायंट कहीं न कही तो आना ही है । इसलिए अब टयुबवैल्ज आगे ज्यादा नहीं लगेंगे । इसी तरह से पिछले पांच साला प्लान में 72 हजार ट्यूबवैल्ज को बिजली के कुनैक्शन दिए गए, 4 लाख जनरल कुनैक्शन दिए गए और 16 हजार से अधिक इण्डस्ट्रीज को कुनैक्शन दिए गए । इसी तरह से आने वाली 7वी योजना के अन्दर 75 हजार टयूबबैल्ज को कुनैक्शन दिये जाएंगे । 4.25 लाख जनरल कृउनैक्शन दिए जाएंगे और 40 हजार के करीब इण्डस्ट्रीज के कुनैक्शन दिए जाएगे । बिजली की खपत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । इस खपत को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सकेके लिए 2900 करोड़ रुपये की हमारी प्लान है । इसमें से 1000 करोड़ रुपये सिर्फ बिजली के लिये दिए गए है और नहर के लिए 585 करोड़ रुपये दिए गए हैं । इस प्रकार लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा बिजली और पानी पर खर्च होगा । कहने वाले तो कह देते हैं कि किसानों के लिये क्या किया है? लोक दल वाले तो किसान–किसान का पक ही नारा लगाते हैं । जबकि 90 प्रतिशत बजट किसान पर खर्च हो रहा है । बिजली और पानी का ताल्लुक भी किसानों से है । मवेशियों के लिये हस्पताल, आदमियों के लिए हस्पताल, स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी, सड़कें तथा तथा मण्डियां व ड्रेनें आदि किसानों के लिए ही तो बन रही हैं । किसानों के लिए क्या चीज नही बन रही है? जितना भी बजट है वह किसानों के लिए ही ज्यादा से ज्यादा है । किसानों से डायरैक्ट टैक्स सिर्फ लगान के रूप में ही लेते हैं ।

उस हिसाब से देखा जाये तो पटवार खाने भी कितने बनाये जा रहे हैं । भगवान ना करे ओले आदि पड़ जाएं तो उसी साल में 15– 20 करोड़ रुपया किसानों को अतिरिक्त देना पड़ता है । इसके अलावा मुलाजिमों का खर्च भी है और दूसरे खर्च भी है जो सरकार को सहन करने पड़ते हैं । बिजली के बारे में मैं बता रहा था कि कितनी बिजली है । बिजली की जो स्कीमें हैं उनमें से हमें 126 मैगावाट तो इसी साल में मिल जायेगी और 208 मैगावाट अगले साल में, 313 मैगावाट उससे अगले साल में, 70 मैगावाट उससे अगले साल में, और 277 मैगावाट बिजली जो इस प्लान का आखिरी साल होगा, उसमें मिल जाएगी ।

11.00 बजे ।

इस तरह से 1113 मैगावाट नई बिजली आ जाएगी । बाहर भी जो बिजली पैदा हो रही है, उसमें भी हमारा हिस्सा है । पंजाब के अन्दर जितनी भी हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीम्ज हैं उनमें भी हमारा बिजली का हक है । परमाणु बिजली घर के बारे में सोचा जा रहा है कि यह हरियाणा में लगे या पंजाब में लगे । परमाणु बिजली घर रीजन के लिए होता है, एक सूबे के लिए नहीं होता । यह बात दूसरी है कि जिस सूबे में वह लगे उसे ज्यादा शेयर मिल जाए लेकिन उससे विजली सारे रीजन को दी जाती है । इस तरह का बिजली घर यू० पी० में नरौरा के स्थान पर और राजस्थान में कोटा के स्थान पर लग चुका है । इस रीजन में भी यह जल्दी ही लग जाएगा । सिक्सथ फाईव इयर प्लान के अन्त तक केवल एक

हजार मैगावाट ऐटौमिक बिजली पैदा होती थी लेकिन गवर्नमैंट ने 2000 ए० डी० तक 10,000 मैगावाट ऐटौमिक बिजली पैदा करने का लक्ष्य बनाया है और इसे पूरा करने के लिए वह तेजी से काम कर रही है । (इस समय थी उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, बाहर से हमें जो बिजली मिलनी है उसका ब्योरा इस प्रकार है । सलाल से 75 मैगावाट, संगरौली से 118 मैगावाट, रिहांड से 60 मैगावाट नरौरा से 28 मैगावाट, चमेरा से 7 मैगावाट और भाभा से 60 मैगावाट। हम अपनी बिजली की लाईनों को भी स्ट्रैग्थन कर रहे हैं । जगह जगह 220, 440, 132, 66 और 33 मैगावाट के बिजली घर बनाए जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई के पानी का सम्बन्ध है, सिक्सथ प्लान के अन्त तक 16,255 स्प्रिंक्लर्ज थे लेकिन इस फाईव ईयर प्लान के अन्त तक इनकी संख्या 31,255 तक पहुंचाने का हमारा निशाना है । जैसे मैंने पहले बताया हमारे यहां इस वक्त बिजली और तेल से चलने वाले टयूबवैल्ज की संख्या लगभग 3 लाख 91 हजार है लेकिन इस प्लान के अन्त तक इनकी संख्या साढ़े चार लाख के करीब हो जाएगी । हथनी कूंड बैराज बनाने की स्कीम भी इस फाईव ईयर प्लान में डाली जा चुकी है । इस पर लगभग 40 करोड़ रुपया खर्च होगा । इस बारे में यू० पी० के चीफ मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर की बात होनी है । इस बैराज के बनने के बाद बरसात के दो तीन महीनों में 28 हजार क्यूसिक पानी निकल सकेगा और उससे कुरुक्षेत्र, अम्बाला और

करनाल के जिलों में सिंचाई होगी । दादुपुर से जो नहर निकलेगी उसने भी अम्बाला जिले को सिंचित किया जा सकेगा । इस बैराज के बनने के बाद जींद के कुछ हिस्से को भी पानी मिलेगा । कुरुक्षेत्र और करनाल जिले के पूर्वी हिस्सों को नहर का पानी नही मिलता । टयूबबैल्ज का पानी भी बहुत नीचे जा चुका है । उन इलाकों की सिंचाई करने के लिए नलवी और लाडवा स्कीम्ज पर इसी साल से काम शुरू होगा । इसके लिए इस साल डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । एस ० वाई० एल ० स्कीम का काम खत्म होने के बाद इन इलाकों को और ज्यादा पानी दिया जा सकता है क्योंकि उस पानी से अनुमान है लगभग 7 लाख एकड़ भूमि सिचित हो सकेगी । इससे लिपट इरीगेशन स्कीम्ज को भी हम ज्यादा पानी दे सकेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, एस० वाई०एल० नहर हरियाणा के लिए लाईफ लाईन है । इस पर हमारा विकास बहुत हद तक निर्भर करता है । कई भाई कहते हैं कि सरप्लस पानी नहीं बचा है । मैं उन्हें बताना चाहता हू कि सैन्टर के पास सारा रिकार्ड होता है । दरियाओ के पानी का प्रा हिसाब किताब रखा जाता है । पाकिस्तान में जो पानी जाता है, बांध बांध कर उसे रोका जाएगा और वह पानी यहां आएगा । जैसा एग्रीमैंट है और प्राईम मिनिस्टर साहब की अश्योरैंस भी है एस० वाई० एल० नहर का काम टाईम बाउन्ड है । इस काम के लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट लिबरली इमदाद भी दे रही है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि एस० वाई०एल० का पानी अवश्य आएगा और उससे हरियाणा के जितने भी सूखे

इलाके हैं, चाहे वे अम्बाला जिले के हैं, या चाहे कुरुक्षेत्र, करनाल महेन्द्रगढ़, गुडगांव, फरीदाबाद, हिसार या भिवानी जिले के हैं उन सबमें नहर? का पानी जा सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शुरू में फडग्रेन्ज की पैदावार 26 लाख टन थी लेकिन अब यह बढ़ कर 75 लाख टन हो, गई है । हमारे सारे गोदाम, चाहे वे एफ ० सी ० आई ० के हैं या मार्किटिंग बोर्ड आदि के हैं, भरे हुए है । रबीन्द्र नाथ टैगोर जी ने कहा था, "Let the homes and marts, the forests and fields of my country be full, my Lord." उनके कथनानुसार भगवान की कृपा से और सरकार व लोगों की अनथक कोशिश से हमारे यहां तो जंगल भी भरे हुए हैं, खेत भी भरे हुए हैं, मंडियों भी भरी हुई हैं । जगह जगह पर तरपालों के नीचे बोरियां रखी हुई हैं । इस वक्त सवा चार करोड़ बोरियां हरियाणा के अन्दर गोदामों में या बाहर रखी हुई हैं । यहां तो माल को उठाने की प्रौब्लम है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हस्पतालों का ताल्लुक है, उनके बारे में सरकार ने यह स्कीम बनाई है कि पांच हजार की आबादी वाले गांव में या आस पास के गांव की आबादी को मिला कर डेढ़ लाख रुपये की बिल्डिग बनाई जाएगी तथा वहां एक कम्पांउडर और नर्स होगी । 30 हजार की आबादी के एरिया में एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर या सबसिडियरी हैल्थ सैन्टर या मौडिफाड्ड डिसपैन्सरी खोली जाएगी । उसमें एक डाक्टर होगा,

एक लेडी डाक्टर होगी और अन्य आवश्यक स्टाफ होगा । इसकी बिल्डिग पर 20 लाख रुपये खर्च होंगे । सवा लाख की आबादी पर एक कम्युनिटी सैन्टर बनेगा जिसकी बिल्डिग 50 लाख रुपये की होगी । उसमें आखों और दांतों आदि के स्पैशेलिस्टस होंगे । उसमें ऐक्सरे और दूसरी हर किस्म की सुविधाएं उपलब्ध होगी । हैल्थ पर 1966 में 1 रुपये 33 पैसे पर–कैपिटा के हिसाब से खर्च होता था लेकिन आज की तारीख मे 50 रुपये पर–कैपिटा के हिसाब से खर्च होता है । फैमिली प्लानिंग में भी हरियाणा इसके लिए फिक्स किए गए टारगैटस से कहीं आगे रहता है । किसी से कोई जबरदस्ती नही की जाती । लोगों में खुद इसे अपनाने की भावना जागृत हो चुकी है । 100 आयूवैर्दिक हस्पताल और 25 हौम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की भी सरकार की योजना है । सरकार होम्योपैथी को भी प्रोत्साहन देना चाहती है । हर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में एक आयु वैंदिक डाक्टर होगा । जिला लैवल पर उनका आर्गेनाइजेशन और स्टाफ अलग होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ऐनीमल हसबैडरी का ताल्लुक है इस 'पर 25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है । इसमें भी द्रुम सैन्ट्रल गवर्नमैंट के टार्गैट्स से कहीं आगे हैं । सैन्ट्रल गवर्नमैंट की हिदायतें हैं कि 10 हजार कैटल पापुलेशन पर एक वैटरिनरी सर्जन दिया जाए लेकिन आप देखते हैं कि हरियाणा में जगह जगह. स्टौकमैन सैन्टर्ज डिसपैन्सरीज और हस्पताल खुले हुए हैं । हरियाणा का पशु वैसे भी भारतवर्ष में सबसे अच्छा है ।

यहां की आबोहवा और जमीन कुछ इस ढंग की है कि इस दिशा में भी हम आगे हैं । यहां की मुर्रा भैस का दुनिया में मुकाबला नहीं है । ये जो फ्रोजन सीमन रखते हैं, यह 25– 25 साल तक भी खराब नहीं होता अब एक नयी टैक्नोलोजी चली है जिससे गाय का क्रौस ब्रीड कर सकते हैं जैसे होलस्टन और जरसी गाय की कौस बीड इसी तरह से हो सकता है । यह बड़ी लम्बी चौड़ी स्कीम है लेकिन इसके साथ साथ. हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हरियाणा नस्ल की गाय बैल हैं वह भी कायम रहे । हरियाणा नस्ल की गाय भैस के दूध को भी बढ़ाना है । हमें केवल आज के जमाने की रौ में बह कर बाहर की नस्ल या बाहर के क्रौस ब्रीड से ही दूध नहीं बढ़ाना है बल्कि हमारी अपनी गायें जो 16– 17 किलो तक दूध देती हैं, उसे भी कायम रखना है । उस तरफ भी हमें प्रोत्साहन देना है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक हुमारे यहां जो दूध की डेरिया सरकार की ओर से लगायी गई थी उनमें घाटा था त्रेकिन अब वहां भी ध्यान दिया जा रहा है । लोगों को भी डेरी के काम में काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जैसा कि सभी को मालूम है कि दिल्ली के अन्दर दूध की बड़ी भारी मार्किट है जहां पर प्राइवेट लोग दूध ले जाते हैं । दिल्ली की 70– 72 लाख की आबादी है जहां पर दूध की बड़ी भारी खपत है इसलिये डेरी की ओर खासतौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारी सरकार ने आई० आर० डी० पी० के तहत गरीब आदमियों को लोन भी दिया

है । जव से सरकार ने यह लोन देना शुरु किया है '' तब से घर घर में गाय और भैंस बन्धी हुई है । सरकार के कर्जा देने के बाद उन लोगों की आजीविका का साधन बन गया गै । डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी स्कीमे एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी ० पी० की कुंए जिनके तहत भी काफी काम हुआ है । आर० एल० ई० जी० पी० के तहत सौ दिन की दिहाड़ी अश्योरड है । इस स्कीम के तहत भी काफी काम हुआ है । हर साल के टारगैट को पूरा किया जाता है । हमारी सरकार ने गरीब आदमियों को प्लाटस भी दिये हैं । इसी तरह से एन० आर० ई० पी० के तहत 9.75 लाख मैन डेज का काम दिया है । अगले साल सन् 1986–87 में 13 लाख 26 हजार मैन डेज का काम दिया जायेगा । आर० एल० ई० जी० पी० स्कीम हन्डर्ड परसैन्ट सैन्टर से फाइनैन्सड है । इसके तहत इस साल 9 लाख 58 हजार मैन डेज का काम दिया है और अगले साल 9 लाख 42 हजार मैन डेज का काग दिया जायेगा । इसी तरह से हमने हिसाब लगाया है कि पावर्टी एलीवेशन का चार लाख से अधिक फैमिलिज को फायदा पहुंच चुका है चाहे उन्होंने भैंस गाय, झोटा बुग्गी, भेड बकरियां या सुअर खरीद कर अपना काम किया है लेकिन उनको काफी कामयाबी मिली है । आजीविका साधन जरूर मिला है । हमारी स्टेट में रोजगार के काफी साधन हैं । यहां पर राजस्थान, यू ० पी० और मध्यप्रदेश से लेबर आती है तब जाकर पूरा पटता है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा पंचायत का महकमा भी बड़ा भारी काम कर रहा है । उसने 2 करोड 12 लाख की मैचिंग ग्रान्ट दी है और अब डेढ़ करोड़ के केसिज बाकी हैं, जिसको लोग चाहते हैं कि उन्हें मिले' । अढ़ाई करोड़ की मैचिंग ग्रान्ट अगले साल के लिए रखी गई है । देहातों की हालत सुधारने के लिए स्मोकलैस चूल्हे लगाये जा रहे हैं । इस बारे मे साइंटिफिक रिसर्च हो रही शै और इस बारे में जगह जगह प्रचार हो रहा है ताकि देहात की औरतों की सेहत ठीक रहे । चूल्हे में फ्क मार मार कर देहात की औरतों की आखें रवराब हो जाती हैं, रोहे' हो जाते हैं या बच्चों की आखें खराब हो जाती हैं । देहातों में लैटरीन का फ्लश सिस्टम नही था केवल शहरों में था । फ्लश सिस्टम बहुत महंगा भी पड़ता है इसलिये सी क्लास म्यूनिस्पिल कमेटी में लो कौस्ट लैटरीन प्रोवाइड की जायेंगी । इसी तरह से देहातों में भी पांच साला प्लान में चौथाई आबादी को कवर करने के लिए लगभग डेढ हजार रुपये की कौस्ट से लैटरीन बनायी जायेंगी जिसमें एक सीट होगी और दो छोटे पिट्स होंगे जिनमें सारा ऐक्सक्रेटा ऐबजोर्ब हो जायेगा ताकि बदबू न आये । इस प्रकार लैटरीन सिस्टम चालू किया जा रहा है क्योंकि इस सिस्टम के लिए थोड़े पैसे की आवश्यकता है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके लिए ज्यादा पैसा दिया जाये ताकि देहातों का सुधार हो सके । वहां पर बड़ी भारी दिक्कत है । जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है, हरियाणा में 4690 प्रौब्लम विलेजिज हैं जिनमें 600 अब और ऐड हो गये हैं । मेरे ख्याल में ये गांवों दो

साल में कवर हो जायेंगे और पांच साला प्लान में सभी गांवों कवर हो जायेंगे या एक साल और भी लग सकता है । सरकार का प्रोग्राम है कि हरियाणा में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर पब्लिक हैल्थ की तरफ से पानी का इन्तजाम न हो । फोरैस्ट विभाग की ओर से दस करोड़ के करीब दरख्त हर साल लगाये जाते हैं । सैन्टर का नौर्म तो 33 परसैन्ट नहीं,. 25 परसैन्ट ग्रीन कवर्ड एरिया होगा लेकिन हरियाणा का मैदानी इलाका है, यहां पर पहाड़ बहुत थोड़ा है, केवल मोरनी हिल्ज अम्बाला जिले में है । इसलिये हमारे यहौ फोरैस्ट बहुत थोड़ा है । भिवानी में तो 1.77 परसैन्ट, हिसार में 1.73 परसैन्ट और सिरसा में 1.12 परसैन्ट एरिया में फोरैस्ट है और हरियाणा की ऐवरेज 3.84 परसैन्ट है । हमारे यहां फोरैस्ट के लिए जमीन कम है लेकिन फिर भी किसानों ने अपने खेतों के डोलों पर दरख्त लगाये हैं । सोशल फौरेस्टरी के लिए 67 करोड़ रुपया पांच साला प्लान में रखा है । पांच करोड़ रुपया आम फोरैस्ट के लिए विभाग को दिया गया णै । प्रांत में जहां पर भी कोई नयी सडक बनती है तो फोरैस्ट वाले अगले दिन ही दरख्त लगाने के लिये पहुंच जाते हैं । फोरैस्ट में इतनी बडी इन्वैस्टमैंट हो चुकी है कि आने वाले सालों में हमारे बजट के अन्दर आमदनी का बड़ा भारी भाग फोरैस्ट का होगा । सफेदा आठ साल में बिक जाता है और कीकर भी जल्दी ही बिक जाती है । पेडू लगाने से देश में हरियाली भी आती है और वर्षा भी अधिक होती है । दरख्तों से हमारे कागज के कारखानों को रा मैटरियल भी मिलेगा जैसे यमुनानगर में कागज का कारखाना है

और जीन्द में टैनरी है । जीन्द में जो टैनरी है उसे कीकर की कस से खाल के रंगने का रा–मैटीरियल मिलेगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे ऐजुकेशन के महकमे ने भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूशन्ज खोलने शुरू किये हैं और 10+2 का सिस्टम भी अपनाया है क्योंकि हमें सारे देश के साथ रहना है । इसलिए अब आगे जो मैडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में ऐडमिशन होगा वह उसी आधार पर होगा । सरकार ने क्वालिटी स्कूल भी खोलने का प्रोग्राम बनाया है । एक जिले के अन्दर एक शहर में और एक देहात में खोलने का प्रोग्राम है । गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जिलेवार सैन्ट्रल स्कुल खोलने का भी प्रोग्राम रखा है क्योंकि सैन्ट्रल गवर्नमैंट के मुलाजिम सारे देश में ट्रांसफर होते रहते हैं । इसलिये उनकी सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि एक ढंग का सिस्टम अपना सके । इसी तरह से 'चौलेन्ज आफ ऐजुकेशन' की बुकलैट हमारे प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी की ओर से मिनिस्टरी आफ ऐजुकेशन ने छपवा कर सभी जगह भेजी है ताकि सभी लोग हर लैवल पर ऐजुकेशनिस्ट, असैम्बली, पार्लियामेंट आदि में अपने विचार दे सकें । नयी ऐजुकेशनल पालिसी के लिए सभी जगहों से विचार इकट्ठे किये जा रहे हैं । इस बारे में पार्लियामैंट में तथा नैशनल कौंसिल में भी डिस्कशन होगी फिर वह नैशनल पालिसी औफ ऐजुकेशन बनेगी । डिप्टी स्पीकर साहब, बेरोजगारी का बड़ा भारी मसला है हालांकि हमने पांच साला प्लान में 78 हजार के करीब ऐम्पलायमेंट

जनरेशन का एम रखा है लेकिन फिर भी यह मसला इतना भारी है कि हर पढ़ा लिखा आदमी नौकरी चाहता है और वह भी व्हाईट कार्ल्ड जौब चाहता है । इसलिए वोकेशनल सिस्टम जारी किया गया है । कम्प्यूटराइ– जेशन सिस्टम पर हमारे प्रधान मन्त्री जी ने काफी जोर दिया है लेकिन उन्होंने साथ–साथ यह भी कहा है कि पुरानी वैल्यूज को भी नही भूलना है । हमें साइंटिफिक तरीकों को भी अपनाना है । हमें 21वीं सदी की तैयारी करनी है । जिन बच्चों का आज लालन–पोषण होना है, उन्होंने 21 वी सदी में जाना है इसलिये दुनिया के साथ कम्पीट करना जरूरी है । इसमें मौडर्न साईन्स और टैक्नोलोजी का प्रसार होना भी निहायत जरूरी है । हमारा हरियाणा दिल्ली के तीनों तरफ है । वहां पर काफी बड़े कारखाने खुल चुके हैं । गुड़गांव में 500 यूनिट्स इलैक्ट्रौर्निक्स के लगाने जा रहे हैं । वहां पर एक किस्म का अपना ही काम्पलैक्स होगा । इसी तरह से जो हमारे प्राईम मिनिस्टर का एम है कि मौडर्नाईजेशन हो, कम्पीटीशन हो और उसमें क्वालिटी भी हौ, उस को पूरा करने के लिए कोशिश हो रही है । हरियाणा में बड़े भारी कारखाने लगाये जा रहे है और लग भी चुके हैं । उनसे हमें टैक्स भी आता है । मिसाल के लिये मारुति कारखाना है । वहां से जो नई कारे निकली हें, उनमें पैट्रोल की कम खपत होती है । तेल यानी पैट्रोल और डीजल की सरकार ने कुछ कीमतें बढ़ाई है । हमारी सैन्ट्रल गवर्नमैंट नहीं चाहती कि तेल का इस्तेमाल ज्यादा हो । तेल की कमी सारी दुनिया में है । सारी दुनिया में इस समय 50– 55 साल के लिये

तेल है और हमारे देश में 250 साल के लिये कोयला है । आने वाले टाईम में इस बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैंट यह चाहती है कि तेल की खपत कम हो । तेल की खपत कम करके हम कोयले की खपत को बढ़ाये ताकि हम जो बाहर से तेल इम्पोर्ट करते हैं, उसको कट कर सके । हमारे भंडार डिपलीट न हों । इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम भी हमारी फाईव ईयर प्लान में बनायी गयी है । वर्ल्ड में यह फैनोमीना है कि बायो–गैस की तरफ– आजकल खास, तौर पर जोर दिया रुक रहा है । सारी एनर्जी का सोर्स तो सूर्य है । वही एनर्जी हमें लकड़ी की शक्ल में या किसी दूसरी फयूल की शक्ल में प्राप्त होती है । अब बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर सर्व की किरणों के बारे में तजर्बे किये गये हैं । आज से 1० साल पहले सूर्य को किरणों से या फोटो वोल्टिक सैल्ज से एनर्जी प्राप्त करने की कीमत बहुत ज्यादा आया करती थी परन्तु भविष्य में इसकी कीमत कम होती जायेगी । अगले पांच सालों में आप देखेंगे कि यह इकौनोमीकल होगी । आप जगह–जगह देखेंगे कि लोग दाल, सब्जी और चावल आदि सूर्य की किरणों की सहायता से पकाया करेंगे क्योंकि इसके लिये सुर्य की किरणों के द्वारा सब्जी, दाल तथा चावल पकाने के लिये कुकर्ज कम्पीटिटीव प्राईस पर बाजार में उपलब्ध होंगे! उसका लोग प्रयोग करेंगे । उसमें न बैठना पड़ेगा और न ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी । एक घंटे या डेढ़ घंटे में जो भी चीज लोग पकाना चाहेंगे, वह तैयार हो जाया करेगी । हँसी तरह से देहातों में तारे लगाने में बहुत खर्चा आता है । सूर्य की

किरणों के द्वारा फोटो वौल्टिक सैल्ज चार्ज हो जायेंगे और उसमें आटोमैटीकली चार्ज होते रहेंगे और इससे बिजली की बचत भी होगी और लोगों को रोशनी भी प्राप्त होगी । इस तरह से रीन्यूअल आफ एनर्जी भी हो सकेगी । फिर यहं देखा गया है कि गांवों को हम ठीक ढंग से बना भी नहीं पाये हैं । उनमें सफाई भी नहीं होती और गन्दगी भी काफी रहती है । एक तो सूर्य की किरणों से बिजली दी जा सकेगी और दूसरे वहां से गन्दगी कम की जा सकेगी । आहिस्ता –आहिस्ता इसके लिये स्कीमें बनाई जा रही हैं । जहां तक ऐनीमल हस्वैड्री का ताल्लुक है, हमने उसमें भी काफी तरक्की की है । ऐग्रीकल्चर में सैलाइनिटी से काफी प्रौब्लम्ज पैदा होती हैं । पहले तो वाटर लौगिग की प्रौब्लम पैदा होती है । वाटर टेबल बढ़ जाता है । यह एक बड़ी भारी प्रौब्लम णै । इसके दूर करने के लिये कौस्ट भी काफी आती है । एक एकड़ में 5– 6 हजार रुपया खर्च आता है ।

इसके लिये 5– 6 फुट नीचे तक जमीन को खोदना पडता है, उसमें पानी खड़ा करना पड़ता है । उसको आगे निकालना पड़ता है । हमने यहां पर मछली पालन की योजना बनाई है । समुद्र जिसमें 10 प्रतिशत नमकीन पानी है, वहां पर मछलियां रहती हैं तो हमारे यहां पर जिसे के पास 10 किल्ले ऐसी जमीन है, वह इस ढंग से मछली पालन की योजना का फायदा उठा सकता है क्योंकि ऐसी योजना हमारी सरकार ने पहले ही बनाई हुई है । हमारे पास इसके लिये बहुत बड़ी मार्किट दिल्ली

पास ही है । उससे काफी अच्छी आमदनी हो सकती है । इसके लिये भी हमारे यहा पर तवज्जूह दी गयी है । इसके अलावा मेवात डिवैल्प– मैट बोर्ड जो हमारे यहां पर बैकवर्ड इलाके की तरक्की के लिये बनाया गया है के लिये 15 करोड़ रुपया अगली पांच साला प्लान में डाला गया है । इसमें से अढ़ाई करोड रुपया इस साल खर्च होगा । इसके अलावा बैकवर्ड क्लासिज शिडयूल्ड कास्ट्स की वैल्फैयर की स्कीम्ज के लिये 34 करोड़ रुपये इसमें रखा गया है । इसमें इतनी स्कीमे है जिनका कोई अन्त नही है । वजीफा ही नही, बुक बेक्स की सहायता, वर्दी और कम्पीटिटीव एग्जामिनेशन्ज में बैठने के लिये क्लासिज भी इसमें शामिल हैं । स्पैशल कम्पोनैट उनके लिये हर स्कीम में रखा गया है । न केवल औरतों के लिये बल्कि बच्चों की न्यूट्रीशन के लिये भी पैसा रखा गया है । बड़ी भारी राशि यानी 28 करोड रुपया इसके लिये रखी गयी है ताकि उनको पौष्टिक और विटेमनाइज्ड भोजन दिया जा सके । इसके अलावा जो विकलांग और डिस–एब्ल्ड हैं, उन बच्चों के लिये इसमें कोशिश की गयी है कि सहूलियात दी जा सकें । जो ओल्ड एज्ड आदमी हैं, उनके लिये भी इसमें प्रावधान किया गया है । ऐसे बूढ़े आदमी या औरतों, जिनके या तो बच्चे नहीं हैं या फिर उनके– बच्चे उनको असहाय छोड़ देते हैं, के लिये भी पैशन देने की व्यवस्था की गयी है । चौधरी देवी लाल जी यह कहते है कि हम बूढ़ों को पैशन कर देंगे । मैं उनको यह बताना चाहता हू कि बूढ़ों को पैशन तो आज भी है । जो बेसहारा हैं, असहाय हैं, जिनके कोई बच्चा नही है और अगर है भी तो वह नु

के बराबर है, उनके सरकार आज भी पैशन देती है । आज कुछ अच्छे लोग तो पैशन लेना ही नहीं चाहते । जिन लोगों की माली हालत अच्छी है अगर उनको भी पैंशन देंगे तो वैसे ही पूरा नहीं पड़ेगा । हमने तो यह देखा है कि बूढ़े तो यह कहते हैं कि उनके बेटों को या उनके पोतों को नौकरो दी जाये! वे पैशन लेने मैं इन्ट्रैस्टिड नहीं हैं । जिनको जरूरत है, पैशन तो आज भी सरकार की तरफ से उनको दी जा रही है । इन्डस्ट्रीज के मामले में हमने केवल बड़े–बडे कारखाने ही नहीं लगाये है बल्कि स्माल स्केल ईडस्ट्रीज की तरफ भी खास तौर पर ध्यान दिया है । हमारे यहां ऐसे 63,000 यूनिटस लगे है जिनमें पढ़े–लिखे लोगों को रोजगार मिला हुआ है । अनएम्पलायड लोगों को हमारे यहां ऐसे यूनिट लगाने के लिये 25,000 रुपया कर्जा और उसमें 1/4 हिस्सा सबसिडी दी जाती है । इस तरह से बहुत सें नौजवान इस स्कीम का भी फायदा उठा रहे हैं । हमारे देहातो में लोगों का रूझान इस तरफ हो रहा है । जरूरत ईजाद की मां है । नौकरी न मिलने पर जरूरत के मुताबिक लोग यह कहते हैं कि हमें कर्जा ही दिलवा दौ । जो मेहनत करता है वह' इस इंडस्ट्री के अन्दर कामयाब भी हो रहा है । हमारे यहां पहले जो 4.50 करोड़ रुपये का माल ऐक्सपोर्ट होता था, वह अब दो सौ करोड तक पहुंच गया है । पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री ने भी बड़ी भारी तरक्की की है । मिलिटरी के कम्बलों का ज्यादातर माल हम सप्लाई करते हैं । हरियाणा में चारों तरफ से तरक्की हो' रही है । भारत में बनने वाले तीन में से दो ट्रैक्टर हरियाणा में बनते हैं', । इसी तरह से

साईकिल का और साईन्स का सामान हरियाणा में बन रख शै । हरियाणा इंडस्ट्री में हर तरह से आगे जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जैसे कि कम्प्यूटर का जमाना आ रहा है, आधुनिकीकरण का समय आ रहा है जिसमें इलैक्ट्रोनिक्स को बढावा दिया जा रहा है, उसमें भी हम आगे रहेंगे । नौन रैजीडैटं इंडिंयन्ज ने भी, लगभग एक हजार ने हमारे यहां ऐप्लाई किया है । उनमें से तीन सौ को तो हमने लैटर आफ अलाटमैंट भी इशू कर दिया है । इसके अलावा अढ़ाई सौ हम ऐसे लोगों को रजिस्टर भी कर चुके हैं जो हमारे यहां छोटे औरे बड़े कारखाने लगायेंगे क्योंकि उनके पास टैक्नीकल नो–हाऊ' भी है । हम उनको भी बडी भारी सहूलियत देंगे । इससे स्टेट की आमदनी बढ़ेगी और स्टेट की प्रोडक्शन बढेगी । हर तरह से हमारा हरियाणा प्रदेश चारों तरफ से प्रगति कर रहा है । जो फौजी' हैं या जो सावका फौजी णै, उनको भी सहूलियत दी जा रही हैं। इसके अलावा जो स्वतन्त्रता सेनानी है, उनके लिये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एलइन किया था कि उनकी पैशन एक सौ रुपये से बढ़ाकर दो सौ रुपये कर दी जायेगी । यह पैशन स्टेट गवर्नमैंट दे रही है । सैन्ट्रल गवर्नमैंट इसके अलावा पैशन दे रही है । इसके अलावा, जिन सेनानियों ने 5 साल से ज्यादा समय तक देश की आजादी के लिये जेल यात्रा की है, उनको 7–7 हजार रुपये भी दिये गये हैं और बसों के अन्दर मुक्त सफर करने की सहूलियत दी गई है। उनको बसों में सफर करने के लिए पास दिए जायेंगे । उनको मुफ्त मैडीकल एड क्य इन्तजाम भी किया

गया है । उनके बेटों, पोते और पोतियों को सर्विसिज में रि–जर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है । डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से' ऐक्स सर्विसमैन को सहूलियतें देने में भी हरियाणा फर्स्ट है । ऐक्स सर्विसमैन को ट्रेनिग दी जाती है । नौकरियों में उनके लिए रिजर्वेशन है । यहां पर हिन्दुस्तान में सव से ज्यादा सैनिक रैस्ट हाउसिज हैं ।

डिप्टी' स्पीकर साहब, जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, पिछले तीन साल से. हरियाणा का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट सारे हिन्दुस्तान में फर्स्ट आ रहा हैं । यह महकमा अधिक से अधिक सहुलियतें यात्रियों को और अपने कर्मचारियों को देता है। यहां पर कर्मचारियों की पेंशन है, ग्रेचुएटी है प्रोविडैन्ट फण्ड है और बोनस है' । हालांकि जहां पैंशन हो वहां बोनस का मतलब ही नहीं है लेकिन यहां पर दोनो चीजें हैं । कर्मचारियों की अच्छी तनखाह है । ड्राईवर्ज और कन्डक्टर्ज को नाइट हाल्ट भी मिलता है । बहुत से कर्मचारी (ड्राईवर्ज और कन्डक्टर्ज) रात को अपने घर जाकर ठहरते हैं लेकिन फिर भी नाइट हाल्ट मिलता है । हरियाणा रोडवेज की 3028 बसिज है और ग्यारह लाख लोग रोजाना इन बसिज से सफर करते हैं । हिसार का अड्डा हिन्दुस्तान में आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के हिसाब से फर्स्ट डिक्लेएयर किया गया है । हांसी का अस्पताल डिजाइन के हिसाब से हिन्दुस्तान में फर्स्ट गया है । एशियाड में भी बहुत अच्छा काम हुआ है । इन सब बातों से पता लगता है कि हमारे यहां आर्किटेक्चर डिपार्टमैंट

बहुत अच्छा काम कर रहा है । ट्रेड फेयर के अन्दर भी हम फर्स्ट आए हैं । पिछले तीन साल में 17 बस स्टैण्डज हरियाणा में बनाए गए हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के अन्दर चहुमुखी विकास हो रहा है । हरियाणा के अन्दर टूरिज्म डिपार्ट– मैंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है । यह बात ठीक है कि हमारे यहां नैचुरल स्पोट्स नहीं हैं लेकिन फिर भी 'हमने जगह–जगह टूरिस्ट कौम्पलैक्सिज बनाए हैं । 31 टूरिस्ट कौम्पलॉक्सज स्टेट हाडवेज पर बनाए हैं । उनकी सर्विसिज बहुत अच्छी हैं और वहां पर यात्रियों को हर तरह की सुविधा प्राप्त है । जब हम बाहर के सूबों में जाते हैं तो वहां के लोग हरियाणा के ट्रिस्ट कौम्पलैक्सिज की बहुत तारीफ करते हैं । हरियाणा का टूरिज्म विभाग सारे भारत में फर्स्ट आया है । अभी हाल में भी बहुत सी जगह जैसे बल्लभगढ़, रोहतक, फरीदाबाद जगहों पर टूरिस्ट कौम्पलैक्सिज का विस्तार किया जा रहा है । कुरुक्षेत्र में शीघ्र ही एक यात्री निवास तथा एक युवा निवास बनाया जाएगा । इसी ढंग से टूरिस्ट विलेजिल भी बनाने का प्रोग्राम है । ये टूरिस्ट विलेजिज गुजरात के पैट्रन पर बनाए जाएंगे। इनका बनाना इसलिये भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली के आसपास लोगों के पास बहुत पैसा है और उनके पास बहुत ब्लैक मनी है । उनकी जेब से पैसा निकालना बहुत जरूरी है जिससे कि वह पैसा ठीक ढंग से खर्च किया जा सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां सड्कों पर पुल भी बहुत बनाए गए हैं और अब भी बन रहे हैं । अम्बाला जिले में खास कर बहुत पुल बनाए गए हैं । यहां पर बहुत अधिक नदियां और नाले हैं उन पर ब्रिज बनाए गए हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता है कि आजकल एक करोड़ से कम में पुल नहीं बनता और जब हरियाणा में जगह जगह पर पुल बन रहे हैं इससे पता लगता है कि हरियाणा सरकार कितना रुपया पुलों पर खर्च कर रही है । यमुनानदी पर पलवल में जो पुल बना है उस पर साढ़े छः करोड रुपया खर्च हुआ है । करनाल मेरठ रोड पर एक पुल बना है । पिंजौर के पास घग्घर पर पुल बनाया गया है । आमला नदी पर पुल बनाया जा रहा है । मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार इस मद में काफी पैसा खर्च कर रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से सड्कों का हाल है । हरियाणा में सड़कों का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है । जो नौन– डायरेक्टरी विलेजिज हैं उनको भी सड़कों से जोडा जा रहा है । ढाक्तियों को भी सड़कें दी जा रही हैं । पंचायत घरों, अस्पतालों, स्कूलों, मंदिरों के लिये ' 2 4' करोड़ की योजना सड़कों की बन रही है । मार्किट कमेटियों से चालीसे प्रतिशत पैसा आएगा । आशा है कि वह दस बारह करोड़ रुपया हर वर्ष आ जाएगा । हैवी ट्रैफिक को कोप–अप करने के लिये सड्कों को चौड़ा किया जा' रहा है । ' मुरथल तक फोर लैन सड़क तैयार हो चुकी है और आशा है कि जल्दी ही करनाल और अम्बाला तक वह सड़क आ जाएगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, रेलवेज पर अठारह जगह ओवर ब्रिज बनाने की स्कीम है और जहां पर हैवी ट्रैफिक है वहां पर कई जगह काम चल रहा है और कई जगह कुछ ही दिनों में काम शुरू होने वाला है । डिप्टी स्पीकर साहब, इन. सब बातों से पता चलता है कि हरियाणा में बहुत तरक्की हो रही है । गवर्नर साहब का जो ऐड्रैस है वह हरियाणा की तरक्की की मुंह बोलती तस्वीर है और मैं गवर्नर साहब का जो अभिभाषण है उसके लिये उनका धन्यवाद करता हू ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना, एस० सी०) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी ईश्वर सिंह ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन क्रूरने के लिये खड़ा हुआ हूं । हरियाणा सरकार की जो नीति है, हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं और बेहतरी के लिए कार्य की जो दिशा है, वह हमारे राजपाल महोदय ने बहुत अच्छे शब्दों में 17 फरवरी, 1986 को इस सदन में जो उन्होंने अभिभाषण देने की कृ पा की है, उसमें दर्शाया है । अपनी स्पीच की ओपनिंग में ही उन्होंने यह साफ शब्दों में कहा कि मेरी सरकार अर्थ–व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति की तीव्र गति को बनाए रख सकी है, ताकि विकास के लाभ अधिक से अधिक लोगों को, विशेषकर गरीब –से गरीब व्यक्तियों को, उपलब्ध कराए जा सके । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि की दशा आपको भलिभान्ति मालूम है

और आप कृषि पर निर्भर गरीब मजदूर की दशा भी भली भान्ति जानते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, गरीब से गरीव स्तर तक इस योजना का लाभ पहुंचे धड वहुत ही अच्छी बात है और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह उपलब्धि इस क्रान्ति के युग में एक बहुत बड़ा कदम 'है । अभी चौधरी ईश्वर सिंह ने सारे आकड़े प्रस्तुत किए हैं लेकिन मैं भी कुछ आकड़े जिनकी आज बहुत चर्चा है और जिसके बारे में सरकार कुछ करने जा रही है, रखना चाहता है और वे हैं बिजली के औकड । उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली की मांग बहुत ज्यादा है हू यह मांग चाहे घर में है, चाहे खेत में और चाहे फैक्टरी में है, बिजली की बहुत ज्यादा मांग बढ़ती जा रही है । उपाध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा बना था तो हमारे पास केवल 38 हजार के करीब पम्पिंग सैट्स थे जिनको कि बिजली की आवश्यकता होती थी और आज 'यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास चौदह लाख के करीब पम्पिग सैट्स हैं । इससे पता लगता है कि खेत में बिजली की मांग बढ़ी है, घर में बढ़ी है और कारखाने में भी बिजली की मांग बढ़ी णै । हरियाणा बनने पर कितने कारखाने हमारे पास थे । बहुत कम थे और आज उनकी संख्या काफी बड़ी है । इस मांग को प्रा करने के लिये हरियाणा सरकार की ओर से बहुत सारे कदम उठाये जा चुकें हैं और उठाये जा रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, आप देखेंगे कि 1985 में एक 220 के० वी० उप–स्टेशन को, दो 132 के० वी० उप–स्टेशनों को, एक 66 के० वी० उप–स्टेशन को और आठ नये 33 के० वी० उप–स्टेशनों को बिजली दी गई । इसके इलावा दो

22० के० वी० उप–स्टेशनों तथा दो 132 के० वी० सब–स्टेशनों को इस साल अगले दो तीन महीनों के अन्दर लगाये जाने की संभावना है । 1986– 87 में 67 हजार जनरल कनैक्शन्ज तीन हजार इंडस्ट्रीयल कनैक्शन्ज और 1200 टयूबवैल्ज कनैक्शन्ज देने –की सरकार की योजना है ।

इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 408.28 करोड़ रुपये का प्रावधान बड़ी तथा दरम्यानी सिंचाई स्कीमों के लिये किया गया है । इस योजना के अन्त तक इससे 22.44 लाख हैक्टेयर इलाका इरीगेशन से कवर करने की संभावना है । इस तरह से सिंचाई क्षमता को अधिक मे अधिक बढ़ाने के लिये इस वर्ष परिरक्षित जल द्वारा 23,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिचाई हो सकेगी । इस योजना के अधीन आज तक 14,500 किलोमीटर चौनलज को पक्का किया जा चुका है । बाढ़ की रोकथाम के फलस्वरूप 16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ नियन्त्रण उपाय जुटाये गये हैं जिसके फलस्वरूप पैदावार बड़ी है चाहे अनाज की पैदावार है, चाहे गन्ने की पैदावार है, चाहे किसी और चीज की पैदावार हो, उसमें काफी तरक्की हुई है । खेतीबाड़ी के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सड्कों का भी जिक्र किया है कि इस साल सातवीं पंच वर्षीय. योजना के दौरान 1,834 किलोमीटर और सड्कों के निर्माण का

प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने इस अभिभाषण में बहुत अच्छे शब्दों में एक बात की चर्चा की है जोकि आज सारे हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है पंजाब हरियाणा विवाद की, पानी के विवाद की शौर हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को देने से सम्बन्धित मामले की उसमें चर्चा हए । अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमारी सरकार ने जो स्टैण्ड लिया है, हमारे मुख्यमन्त्री महोदय ने, हमारी पाटों के नेता वे स्नो स्टैण्ड लिया है कि चण्डीगढ़ तब सउ पंजाब को नहीं दिया जाएगा जब तक कि हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को नहीं दिये जाते यह एक बड़ा सराहनीय कदम है । इसके साथ साथ पानी के बारे में भी जो हमारी सरकार ने अपना निर्णय लिया, वह एक सराहनीय कदम था लेकिन हमारे अपोजीशन के भाइयों ने इस बात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की । अध्यक्ष महोदय,. आपको पता ही है कि यह सारा केस सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड' जज के सम्मुख रखा गया । अध्यक्ष महोदय, आप वकील हैं, आप अच्छी तरह से यह जानते हैं कि जब मुकदमा अदालत में पेश होता है तो उसके लिये वकील पेश होता है या गवाह पेश होते हैं, रिकार्ड पेश होता है, किन्तु किसी प्रकार के मुजाहरे वगैरह अदालतों के अन्दर या बाहर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उस कमीशन ने इन सभी बातों की परवाह न करते हुए यी निर्णय किया कि 85 हिन्दी भाषी गांव हरियाणा को मिलने चाहियें लेकिन एक गांव के मारे मेरे हाथ बन्धे हुए हैं, इसका निर्णय भारत सरकार ही कर सकती है । कमीशन ने साफ शब्दों में कहा कि चण्डीगढ़ के बदले कन्दूखेड़ा

हरियाणा को देने से ही शेष हिन्दी भाषी गांव हरियाणा को दिये जा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय हुआ नहीं था कि इन अपोजीशन के भाईयों ने जगह जगह पर सरकार के खिलाफ मुजाहरे करने शुरू कर दिये लोगों को सड्कों पर जबरदस्ती घसीटना आरम्भ कर दिया । सारे हरियाणा के बन्द का आह .वान कर दिया जिससे कि हरियाणा के हितों को गहरा आघात पहुंचा । इस तरह से मुजाहरे करने से, सड़कों पर लोगों को घसीटने से और लूट मार करवाने से क्या कोई इस बात का हल निकला? क्या अदालत ने कोई अन्तिम निर्णय दे दिया था जिस कारण सारे हरियाणा में बदअमनी फैलाने की कोशिश की गयी । हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि पानी तो अभी मिला नहीं, दूर है और जूती पहले ही निकाल ली । अदालत ने अभी तक अन्तिम फैसला तो दिया नहीं और इन्होंने यू ही निहत्थे लोगों को मरवाना आरम्भ कर दिया । इन अपोजीशन के भाईयों का तो काम ही यही है जिससे कि हरियाणा का अहित हो । अभी थोड़ी देर के लिये अपोजीशन के थोड़े से भाई सदन में आये थे और इसी बात. को उठाते हुए, बावेला मचाते हुए बाहर निकल गये क्योंकि उनको हरियाणा के हितों से कोई सरोकार नही है । हरियाणा को क्या मिलता है, उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है । उनको तो केवल इस बात की चिन्ता है कि राजनीति कैसे चलती है और किस तरीके से सरकार को गिराना है । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हरियाणा की भोली भाली जनता को उकसाना

गुमराह करना उचित बात नहीं है और न ही राजनीति में यह बात आनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि 1970 में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने एक अवार्ड दिया था कि अबोहर फाज्लिका हरियाणा को मिलेगा तो उस अवार्ड के ऊपर भी इन अपोजीशन के भाईयों ने हरियाणा के अन्दर हड़ताले करवायी थीं, गाड़ियां रोकी थी, बसें रोकी थीं और क्या कुछ नहीं इन्होंने हरियाणा के अन्दर करवाया था । कहने का मतलब यह है कि ये लोग किसी भी प्रकार से सरकार का साथ देना नहीं चाहते और न ही हरियाणा का व हरियाणावासियो का ही हित चाहते हैं । हरियाणा के हितों का ध्यान रखते हुए हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने, हमारी पार्टी के प्रधान ने हरियाणा के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके हाथों हरियाणा के हितों को किसी भी प्रकार का आयात नहीं पहुंचेगा । श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के सपुत्र श्री राजीव गांधी हमारे देश के कुशल प्रधानमन्त्री हैं हमें उन पर भी इरा पूरा विश्वास णै कि वे हमारे हरियाणा के हितों का पूरी तरह सें ध्यान रखेंगे और हरियाणा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे । हमारा जो पानी का हिस्सा बनता है, वह हमें अवश्य ही दिलवाया जाएगा । हमारी पार्टी का यी पक्का इरादा है, दिली कामना णै कि पंजाब समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाए । हम सब इस बात का पूरा समर्थन करते है कि यह समझौता पूरी तरह से लागू होना चाहिये उसके

अनुसार हरियाणा को उसका पूरा पानी का हिस्सा 3.5 एम० ए० एफ० मिलना चाहिये और उस के लिये आज तरह तरह के भ्रम खड़े हुए हैं कि पंजाब सरकार इस समझौते को लागू करवाना नहीं चाहती, नहर खुदवाना नही चाहती । अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नहर की खुदाई में काफी विलम्ब हो रहा है । इस बारे में हरियाणा ने अपना केस प्रस्तुत किया हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस काम को अपने हाथ में लेगी और हरियाणा का जो हिस्सा 3.5 एम० ए० एफ० पानी का बनता है, वह हरियाणा को अवश्य दिलाया जाएगा । इस' तरह की भावना राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में व्यक्त की और इस समझौते की चर्चा भी स्पष्ट शब्दों में की कि हरियाणा को हिन्दी भाषी क्षेत्र अच्छे ढंग से मिलेगे ।

अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों से ऊपर उठकर मैं यह भी कहना चाहंगा कि हरियाणा सरकार और उसकी पुलिस मुबारिकबाद की पाल है । जब कभी भी किसी गल्त प्रकार के आदमियों ने हरियाणा में गल्त काम करवाने की कोशिश की, अव्वल तो किसी की इस तरह की कार्यवाही करवाने की हिम्मत नहीं हुई और अगर किसी ने कायरतापूर्ण ढंग से कोई अनुचित कार्य राज्य में करवाया भी है तो सरकार ने व पुलिस ने ऐसे विद्रोह को मौके पर ही दबा दिया । इस बार भी सरकार ने और पुलिस ने अपनी सक्रिय कुशलता का परिचय दिया है । इससे साफ जाहिर है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति काबू में है

। इसलिये मैं एक बार फिर अपनी सरकार और अपने राज्य की पुलिस को इसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

12.00 बजे ।

अध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० नहर के बारे में भी 'गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में काफी चर्चा की है उन्होंने यह भी बताया है कि इस वक्त हरियाणा को पानी देने के लिये और कौन कौन से प्रोजैक्ट चल रहे हैं । मैं समझता हूं कि हरियाणा की सरकार इस बारे में पूरी तरह से जागरूक है क्योंकि खेती पानी पर और खाद पर काफी निर्भर करती है । जब तक हरियाणा के किसान को पूरा पानी, प्री खाद नही मिलती तब तक हरियाणा का किसान खुशहाल नहीं हो सकता । इसके लियें सरकार ने पूरी व्यवस्था की है । जब एस0 वाई० एल० नहर बनकर तैयार हो जाएगी तो हरियाणा की रूपरेखा ही और होगी । यह हारेयाणा की लाईफ लाईन है । अध्यक्ष महोदय, जब पूस ० वाई० एल० कैनाल का पानी इधर आएगा तो हमें और आपको भी आशा होगी कि दादुपुर से जो प्रस्तावित कैनाल निकलेगी वह मेरे और आपके क्षेत्र को भी सैराब करेगी । मुझे खुशी है कि हरियाणा सरकार ने वह स्कीम पास करवाई है और उसके लिए कुछ पैसा भी एलोकेट किया है । जमीन ऐक्वायर करने की इनकी प्रक्रिया चालू– हो गई है । इसके साथ साथ जो हथनी कुंड बैराज से तुक नहर निकालने का प्रस्ताव है, जब वह नहर निकलेगी तो उससे अम्बाला जिले में खेती बाडी के धंधे में भी वृद्धि होगी और

खेतों में उत्पादन बढ़ेगा । अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में फ्लड कंट्रोल का भी चर्चा किया गया है । काफी सारे क्षेत्र जो फ्लड की लपेट में आते थे उनकी रोकथाम के लिए इस हैड के तहत काफी कुछ किया गया है । मैं इस' बात के लिए भी सरकार को मुबारिकबाद देता हू । जितने फ्लड पहले आया करते थे आज वे कन्ट्रोल हो गए हैं । लेकिन मैं फ्लड कंट्रोल के अधिकारियों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी फ्लड कंट्रोल की योजना बनानी हो उस पर कार्य सुनिश्चित समय के अन्दर हो जाना चाहिए । देखने में यह आता है कि जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो स्कीम पर महकमा काम करना शुरू करता पै । इसका नतीजा यह होता है कि जितना काम किया होता है वह सारा बारिश में बह जाता है । मैं चाहुंगा कि स्कीम शुरुरू करने वाले अधिकारी उसको समय परशुरू करें ताकि पैसे का सदोपयोग हो । स्पीकर साहब, अपने और आपके क्षेत्र मे इरीगेशन के लिये मैं और भी सुझाव देना चाहूगा । हमारे यहां बरसात के रिवर मारकंडा और टांगरी हैं । हमारी प्रपोजल तो है कि मारकंडा बैराज बने लेकिन इस पर पैंसे की कमी के कारण कुछ समय लग सकता है । मैं चाहूंगा कि जब तक यह योजना लागू नहीं होती तब तक वहां थोड़े पैसे से काम हो सकता है । वहां पर चौक बांध लगा कर थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा किया जा सकता है जोकि खेती के लिए यूज हो सकता है । इसके लिए फौरेस्ट डिपार्टमैंट और ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट मिल कर इस योजना को पूरा कर सकते हैं । अगर ऐसा किया जाता है तो इससे उस एरिया की

सिंचाई में काफी सुविधा मिल सकती है । जहां तक ड्रिकिंग वाटर की बात है, पहले हरियाणा में बहुत सारे गांवों में पीने का पानी अवेलेबल नहीं था लेकिन आज ट्यूबवैल लगा कर इस समस्या को काफी हद तक दूर कर दिया गया है । फिर भी बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जो प्रौब्लम विलेजिज तो है लेकिन उनको नौन–प्रौब्लम डिक्लेयर किया हुआ है । पीछे इस बारे में शायद सर्वे भी हुआ था । मैं हैरान हूं कि किस तरह से सर्वे होता है । सर्वे में ठीक ढंग से दिखाया जाना चाहिए कि कौन से गांव में पीने के पानी की आवश्यकता है । अब भी बहुत सारे गांव ऐसे देखने में आए हैं जहां पीने का पानी नहीं, कुछ सूखे पड़े हैं लेकिन रिकार्ड में वे गांव नौन–प्रौब्लम हैं । तो इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । बिजली का मैंने जिक्र किया था । बिजली के लिये हमारे पास हाइड्रो थर्मल और ऐटोमिक प्लांट लगाने के साधन हैं । बिजली के तिये हमारें पास पानी के लिमिटड साधन हैं । जमुना नहर जो आती है उस पर स्लोप लिमिटड क्षेत्र मे ही है । गवर्नर महोदय ने इस बारे में चर्चा की है कि उस पर 8–8 मैगावाट के दो यूनिट शीघ्र चालू हो जाएगे । अध्यक्ष महोदय, इनमें से एक तो पिछले दिसम्बर में ही चालू हो जाना चाहिए था लेकिन उसमें देर हो गई । दूसरे हमारे पास थर्मल प्लांट हैं । ये प्रोजैक्टस फरीदाबाद, पानीपत में हुँ और जमुना नगर में बनाना प्रपोज्ड है । इसके अलावा ऐसे प्रोजैक्टस और भी लग सकते हैं । लेकिन हमारे थर्मल प्लांटस की जो जनरेशन कास्ट है वह बहुत ज्यादा है । आप कम्पेयर करके देखें,

हमारे प्लांटस की पर यूनिट कौस्ट दिल्ली के प्लांटस की कौस्ट से कहीं ज्यादा है । इसलिये ये हमे मंहगे भी पड़ते हैं । हमारे अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि थर्मल में जो त्रुटियां हैं, जो वहां लीकेज हैं, चाहे कोयले मै है या 'रिपेयर में है उनको ये अच्छी तरह से ढूंढे । अगर हम इन कमियों को प्लग कर लेते हैं तो कोई वजह नहीं कि दिल्ली से हमारी कौस्ट कम न हो । इसमें यह भी चर्चा की गई है कि हमारे यहा ऐटोमिक प्लांट को मंजूरी हो गई है और उसके लिए स्थान भी निश्चित कर लिया है । कण बड़ी अच्छी बात है । जब हरियाणा मैं ऐटोमिक प्लांट लगेगा तो हमे और भी बिजली मिलेगी । लेकिन इसके साथ साख मैं सोलर सिस्टम का सुझाव देना चाहता हूं । हमें बिजली की ज्यादा आवश्यकता ट्यूबवैलों के लिए होती है । बारिश हो जाती है तो बिजली भी आ जाती है लेकिन उन दिनों में ट्यूबवैलों को बिजली की आवश्यकता नहीं रहती । तो मैं यह चाहूंगा कि जैसे देश के और भागों में सोलर सिस्टम चालू हो गया है उसी तरह हरियाणा में भी शूरू किया जाए । दिन के समय सूरज की किरणों से बिजली बनाएं और उससे ट्यूबवैल्ज चलाए । इससे जो कारखानों और पावर प्लांटस में हम बिजली पैदा करते हैं उसमें भी बचत होगी । आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बिजली विभाग में मैटिरियल की बहुत शार्टेज रही । तार नहीं मिली, पोल नही मिले, मीटर और ट्रांस्फार्मर नही मिले । इसलिये मैं यह चाहूंगा कि सोलर सिस्टम से भी किसानों को बिजली दें । बिजली बोर्ड एक कमर्शियल कंसर्न है । किसानों को कहा जाता है किं वे

अपने टयूबवैल्ज पर कैपेस्टिर लगाए । किसानों के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे कैपेस्टिर लगा सकें । बिजली बोर्ड खुद लगा कर दे । आज ऐग्रीकल्चर की जान बिजली है, खाद है । हमारी इकोनोमी तभी ठीक से चल पाएगी जब हमारे पास बिजली के साधन सुनिश्चित हो जाएंगे । खेती में हमने बहुत उन्नति की है । सरकार की सहायता सै खेती के लिए हमें बहुत खाद मिली है और टैक्नोलोजी भी मिली है । जो भूमि अच्छी नही थी उस बारे में हम सायल टैस्टिग के जरिए पता लगा पाए हैं कि किस भूमि में किस खुराक के अंश की कमी है । उस कभी को हमने टैक्नोलोजी के जरिए पूरा किया है । आज यह देखने में आया है कि जहां हमारे पास खाद्यान की कमी थी वहां आज हम अन्न बाहर भेज रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा देहात में स्वास्थ्य सेवाओं की भी बहुत आवश्यकता थी । गवर्नर महोदय ने उसका भी बहुद अच्छे शब्दों में वर्णन किया है कि सरकार ने सभी जगह यह सुविधा प्रदान करने की चेष्टा की है 1 मुझे खुशी है कि सातवें प्लान में हर ब्लाक को पूरे ढंग से कवर किया गया है और धीरे धोरे हर साल स्कीमें बनाई जाएगी । जैसे हर ब्लाक में बडा हस्पताल होगा । मिसाल के सौर पर गलाना में, बराड़ा में और व्होटा में तथा केसरी में बड़े हस्पताल होंगे । और भी कई जगह इस प्रकार की योजना बनाई हैं कि वहां पर हम प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज देंगे । यह बहुत अच्छी बात है । एक समय था जब लोगों को ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं होती थी और छोटे मोटे इलाज के लिए भी लौगों को जिले के हस्पताल में जाना पडता था ।

इसके अलावा देहात में और भी कई स्कीमें सरकार ने बनाई हैं जैसे एन० आर० ई० पी० वगैरह की स्कीमें है । मैं दावे के साथ कह सकता है कि हमारी पंचायतों के जो सरपंच हैं अगर वे इन स्कीमों का सही ढंग से उपयोग करैं तो आप जो देखते है कि गांवों में जो गलियां कच्ची हैं, कही नालियां नही है और दूसरे साधन नही हैं उनका काम अच्छी तरह से हो सुकता है । डन स्कीमों का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो गांवों में बहुत अच्छा काम हो सकता है । इन स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से पैसा मिलता है । यदि सरपंच इन स्कीमों का सही ढंग से उपयोग करें तो इनसे गांवों में काम भी होंगे और बेरोजगारी भी हटेगी । लेकिन स्पीकर साहब मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन स्कीमों के लिए जो पैसा मिलता है उसके उपयोग में गड़बड़ी होती होती है । मैं इस बारे में अपनी सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि सरकार उस गडबडी को रोके ताकि वह पैसा ठीक ढंग से और ठीक प्रकार से इस्तेमाल हो सके । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हरिजनों और पिछड़ी श्रेणियों के लिये बहुत सारे साधन जुटाए हैं । छोटा मोटा काम काज करने के लिए हरिजनों के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम है जिससे वे ऋण ले कर अपना कोई काम धंधा कर सकते हैं । पिछड़ी श्रेणियों के लिए बेकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम है जिससे पिछड़े वर्ग के लोग ऋण लेकर अपना कोई काम धंधा कर सकते हैं और इसी तरह से एक इकोनोमिकली वीकर सैक्शन्ज के लिए निगम है वे उससे ऋण

लेकर अपना कोई काम धंधा कर सकते हैं । इन निगमों के जरिए अपना कोई छोटा मोटा काम किया जा सकता है जिसको एक प्रकार से स्वयं रोजगार योजना कहते हैं जिससे बेरोजगारी द्र होती है वह भी इन निगमों के जरिए होती है । सरकार ने इस तरह की काफी सुविधाएं दी हुई हैं । हमारी सरकार ने हरिजन बच्चों के लिए स्कूलों में, कालेजों में और नौकरियों में रिजर्वेशन दी हुई हैं । लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा किं इन स्कीमों को लागू करते समय जब इनकी इम्पलीमैंटे शन की जाती है तो वह सही ढंग से होनी चाडिए । इन स्कीमों को इम्पलीमैंटेशन में कोई गड़बड़ नही होनी चाहिए । जो कोआप्रेटिव अदायरे हैं उनमें पहले रिजर्वेशन नही होती थी लेकिन हरियाणा सरकार ने उनमें भी नौकरियों के अन्दर रिजर्वेशन की है । लेकिन वह रिजर्वेशन पू रो नही है जो रिजर्वेशन मे बैकलौग है उसको पूरा किया जाए । जो बैकलौग रहता है उसको ध्यान में रख करके आगे रिक्रूटमैंट की जाए । काफी अदायरों में रिजर्वेशन पू री नहीं है काफी बैकलौग है । स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हू ताकि रिजर्वेशन का बैकलौग पूरा हो सके । क्योंकि हरियाणा के अन्दर क्लास वन और क्लास टू में रिजर्वेशन नही है लेकिन. पं जाब और केन्द्र में क्लास वन और क्लास टू पोस्टों में रिजर्वेशन है । मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और हमारे हरियाणा में भी क्लास वन और क्लास टू में रिजर्वेशन का प्रावधान करे । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है

कि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में अब सुसंगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विप्र मान है । अब किसी भी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की रूलाई प्र एत करने के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता । खाद्य एवं पूर्ति महकमें की कायि सारी योजनाएं हैं यह महकमा भी अच्छे काम करता है । स्पीकर साहव, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी हमारा प्रान्त बहुत आगे है । पहले हरियाणा प्रान्त को इंडस्ट्रीज की दृष्टि से पिछड़ा हुआ समझा जाता था क्योंकि 1966 में जब हरियाणा बना उस समय केवल 4519 इंडस्ट्रीज थीं लेकिन आज बढ़ कर 60692 इंडस्ट्रीज हो गई हैं । देहात में इस बात की जरूरत थी कि रूरल इंडस्ट्रीयलाइजेशन हो लेकिन वह उतनी नहीं हो पाई है । उस तरफ सरकार अग्रसर है । दे हात में रूरल इंडस्ट्रीयलाइजेशन के बढ़ावे के लिए सरकार कदम उठ रही है ताकि देहात के लोग केवल खेती पर ही निर्भर न रहें क्योंकि खेती में अनाज कम होता है और उनका खाने का गुजारा मुश्किल से होता है । अगर देहात के लोग कोई छोटामोटा बता लगा लेते हैं तो उससे उनकी आमदन बढ़ती है । इसलिए मैं कहना चाहुंगा कि इस योजना को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि देहात के लिए एक ऐग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड है जिसके पास बहुत सारे फण्डज अवेलेबल हैं । यदि उन फण्डज का देहातों में ठीक ढं न से उपयोग किया जाए तो देहातों की बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं । जैसे सड़कों की हालत खराब है और मंडियों की

हालत खराब है उनकी समस्या हल हो सकती है । ऐग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड में जो पैसा इकट्ठा होता है अगर वह सही ढंग से इस्तेमाल हो जाए तो काफी समस्याओं का समाधान द्हो सकता है । देखने में आया है कि उनके पास पै सा पडा रहता है उसका उपयोग नहीं होता है । मैं इस बारे में सरकार को एक सूझाव देना चाहूंगा कि ऐग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड हरियाणा में जिस क्षेत्र से पैसा इकट्ठा करता है वह पैसा उसी क्षेत्र के कामों में खर्च कर दे ताकि उस क्षेत्र के लोगों को कोई शिकवा न रहे और उनके इलाके की समस्याओं का भी समाधान हो जाए । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा को क्षेत्र में भी हरियाणा के अन्दर काफी प्रगति हुई है । कई प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल और मिडिल स्कूल से हाई स्कूल अपग्रेड किए गए हैं । शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है अब बच्चों को ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि स्कूलों की बिल्डिगें अच्छी नही हैं । स्कूलों में साईंस ब्लाक नहीं हैं यदि हैं तो उनमें मैटीरियल पूरा नहीं है । स्टाफ की बहुत कम है मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे । इसके अलावा मैं यह कहना चाहूगा कि सड़कें बनाने की तरफ भी सरकार ने काफी ध्यान दिया है और इस साल लगभग 1834 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रावधान है । काफी जिलों मे सड़कें बन रही हैं और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आज हरियाणा के हर गांव में सड़क है, एक नहीं बल्कि ण्क एक गांव में कई कई सड़कें जुड़ी हुई हैं 1 इराके अलावा स्पीकर साहब, हुड्डा द्वारा देहातों में जो

प्लाटस काटे जाते है उनके बारे में भी इस अभि– भाषण में विवरण आया है और खुशी की बात है कि इस अदायरे ने देहातों में बहुत अच्छी अच्छी कालौनीज बनाई हैं शौर इंडस्ट्रीयल कम्पलैवत भी बनाए हैं । इस बारे मैं मैं एक बात कहना चाहूगा कि जो रैजीडैशियल प्लाटस हैं उनमें रिजर्वेशन है लेकिन जो कामर्शियल प्लाटस हैं उनमें रिजर्वेशन नही है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कामर्शियल प्लाटस में भी रिजर्वेशन की जाए ताकि गरीब समाज के लोग उसका पूरा पूरा लाभ उठा सके' । स्पीकर साहब, एक्स सर्विस मैन को बहुत सहूलियतें दी गई हैं और स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए भी काफी सहूलियतें दी गई है । यह बहुत ही खुशी की बात है । जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए लडाइयां लडी उसके लिए हुमारे प्रधान मन्त्री जी ने और हमारी सरकार ने उनको समुचित ढंग से आदर दिया है । उनको पैंशन दी है, मैडीकल फैसेलिटीज दी है, सड़कों द्वारा यात्रा करने में सुविधा दी है, उनके बच्चों को नौकरियों में सुविधाएं दी हैं करि उनको करनों में भी सुविधाए दी हैं । मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा करके सरकार ने उनको बहुत आदर और सम्मान दिया है यह वहुत ही खुशी की बात है । चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बोलते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार की जो गतिविधियां चल रही हैं और चलने वाली हैं उनके बारे में काफी विस्तार से चर्चा की है और आकड़े दे कर बताया है । आज हरियाणा प्रान्त चहूमूखी प्रगति कर रहा है और तरक्की की ओर अग्रसर है । हमारी पार्टी और हमारी सरकार का प्रोग्राम हमें

समाजवाद की ओर ले जाना है और साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ना है और गरीबी के खिलाफ लड़ना है । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी इन्द्र सिह नैन, पदासीन हुए) चेयरमैन साहब. बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ना है. और मंहगाई के खिलाफ भी लड़ना है । हम कह सकते हैं कि यह अभिभाषण सरकार की नीतियों की रूपरेखा है और प्रदेश की प्रगति की ओर एक कदम है और हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार के कदम पर हम चलें । अगर हम अपने प्रान्त को, अपने देश को एक अच्छी नीति के साथ लोगों की बेहतरी वाली सरकार दे सकते हैं तो हम सरकार की नीतियों पर चलें । हमें पूरा विश्वास है कि हम इस कदम पर चल सकेंगे । इन शब्दों के साथ चौधरी ईश्वर सिंह जी ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और अनुमोदन करता हूं ।

श्री सभापति : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि गवर्नर साहब को एक एडैरस फालोइंग टर्मज में प्रेजैन्ट किया जाए–

''कि इस सैशन में असैम्बल हुए हरियाणा विधान सभा के मैम्बर्ज उस ऐड्रैस के लिए गवर्नर साहब के डीपली ग्रेटफुल हैं, जो उन्होंने 17 फरवरी, 1986 को हाउस में डिलिवर करने की क्रपा की है'' ।'

श्री निहाल सिंह (अटेली) : चेयरमैन साहब, यह जो गवर्नर साहब ने. हाउस में ऐड्रैस पेश किया है मैं उसके बारे में कुछ अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं । गवर्नर साहब ने अपने ऐडैरस के पहले ही सफे पर लिखा है कि उनकी सरकार राजीव–लौंगोवाल एकोर्ड का का स्वागत करती है । मैं समझता हूं कि यह ऐसा ऐकौर्ड नहीं जिसका स्वागत किया जाना चाहिए । यह ऐकोर्ड कितना गलत था यह बात 26 जनवरी, 1986 को साबित हो गई । 26 जनवरी की जो सीमा इस एकोर्ड की रखी गई थी वह बगैर सोचे– समझे रखी गई थी । प्रधान मन्त्री को प्री तरह से सारी बातों से अवगत नहीं कराया गया जिसकी वजह से यह फैसला जल्दबाजी में हुआ । इस बात को प्रधान मन्त्री जी भी और दूसरे लोग भी मान रहे हैं कि यह ऐकोर्ड जल्द बाजी में किया गया था । 26 जनवरी को समझौता लागू कराने के लिए यहां पर दोनों विधान सभाओ के सदस्य सैशन के लिए बैठे रहे लेकिन सैशन नहीं हुआ । इस ऐकौर्ड के अन्दर बेसिकली गलत बातें लिखी गई थी जिसकी वजह से यह ऐकोर्ड लागू नहीं हूआ । पंजाव के लोगों ने इस बात को खूब कहा कि कन्टीग्यूटी वाली बात लागू होनी चाहिए । इसके विपरीत जब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने ऐकौर्ड किया था तो उस समय यह साफ लिखा था कि पंजाब के जो हिन्दी भाषी गांव हरियाणा को मिलने हैं उनके लिऐ पंजाब से रास्ता दिया जायेगा जबकि डस समझौते में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से यह समझौता सिरे नही चढ़ सका । दूसरे न ही इस समझौते के अन्दर हरियाणा

को पार्टी वनाया गया । जब हरियाणा को पार्टी ही नहीं बनाया गया तो उसी का कारण है कि हरियाणा के हितों की रक्षा को मद्देनजर नहीं रखा गया । यदि उस एकोर्ड में हरियाणा पार्टी होती तो वह अपनी बात सामने रखती और सही बात होती । हरियाणा कोइस एकौर्ड में पार्टी न बनाना भी एक बहुत गलत बात थी । हरियाणा को पार्टी न बनाये जाने की वजह से ही हरियाणा में कुछ हालात खराब हुए । हरियाणा को पार्टी न बनाये जाने की वजह से और हरियाणा के लोगों की बात को ध्यान से न सुनने की वजह से ही यहां के लोगों को मजबूरन सडक पर आना पड़ा, ऐजिटेशन करना पड़ा और रास्ता रोको जैसा कदम उठाना पड़ा । जैसा कि मैंने अभी कहा है कि 26 जनवरी तक की सीमा का जो ऐकोर्ड था वह तो फेल हो गया है । दूसरा जो कमीशन पानी के बंटवारे के लिए बैठाया गया है वह भी फेल होगा। इस में यह शर्त रखी हुई है कि पहली जुलाई, 1985 को जितना पानी जिन जिन स्टेट्स को मिला था वह तो बना रहेगा और बाकी के पानी का बंटवारा यह कमीशन करेगा । पहली जुलाई की जो शर्त रखी गई है उस की वजह से भी यह समझौता सिरे नहीं चढ़ पायेगा और यह भी फेल हो जायेगा । पहली जुलाई की शर्त से तो यह लगता है कि जो झगड़ा अब पानी के बारे में चल रहा था वह चलता रहेगा और इसके हल होने की कोई उम्मीद नहीं है । जब ऐकौर्ड में हरियाणा को पार्टी नही बनाया गया तो फिर यह सुनने में आया है .... जब यह बात हो गई तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर

पंजाब के मन्त्रियों और अकाली नेताओं ने शोर मचाया कि अदर फैक्टर वाली जो बात हे वह ऐकार्ड से बाहर की बात है ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, चेयरमैन साहब, राव साहब बहुत सीनियर मैम्बर हैं । ये सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं । .... यह बात हमने नही लिखवाई । मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बात रिकार्ड पर न आये क्योंकि इसका मतलब दूसरा समझा जायेगा और यह स्टेट के इन्ट्रैस्ट के खिलाफ भी जाता है ।

श्री सभापति : ठीक है, इस बात को रिकार्ड पर न लाया जाये ।

श्री निहाल सिंह : यदि इनका यह एतराज है .... तो यह तो रिकार्ड पर लाया जाये कि कुछेक लोगों ने मिलजूल कर अदर फैक्टर्ज' वाली बात टर्म्ज आफ रैफरैस में रखवा दी । इस वात पर पंजाब के नेताओं ने, पंजाब के मुख्य मन्त्री ने और दूसरे लोगों ने बावेला मचा दिया कि 'अदर फैक्टर्ज' वाली जो बात है यह ठीक नहीं है । जब यह तोर मचाया जा रहा था तो अखबारों में यह आया था ..... इस किस्म की बात करवा दी । उस वक्त हरियाणा के किसी भी पार्टी के नेता ने चाहे वह रूलिंग पार्टी से था – चाहे अपोजीशन पार्टी से था, यह नही

कहा कि ' अदर फैक्टर्ज ' वाली – बात ठीक है और बिल्कुल वाजिब है ।

श्री सभापति : राव साहब, अखबारों में तो बहुत सारी बातें आती रहती हैं ।

श्री निहाल सिंह : इन बातों का नोटिस लेना चाहिए था । अखबारों में ' अदर फैक्टर्ज ' वाली बात का बार–बार जिकर आया और यह लगने लगा कि पंजाब के मुख्य मन्त्री खुद ' अदर फैक्टर्ज ' की बात लिखे जाने का क्रैडिट ले रहे हैं और हरियाणा के मु ख्य मन्त्री को ब्लेम कर रहे हैं तब भी हरियाणा के किसी एम ० पी ० ने या दूसरी पार्टी के नेता ने यह बात नहीं उठाई कि ' अदर फैक्टर्ज वाली बात ठीक है और न ही इस बारे में प्रधान मल्टी को बताया गया । इसके विपरीत अदर फैक्टर्ज' वाली बात के बारे में प्रधान मन्त्री ने यह कह दिया य ह बात गलत लिखी गई है । हमारे नेताओं को इस बात का स्टैण्ड लेना चाहिए था कि ' अदर फैक्टर्ज ' वाली बात सही है । दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहत ख हूं कि जब यह समझौता हुआ तो उस समय केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हरियाणा मैं भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है । ठीक समझौता न हो ने की वजह से ही पंजाब से कांग्रेस को अपनी कीमत च कानी पड़ी । मेरे कहने का मतलब यह है कि व हां से कांग्रेस की सरकार खोनी पड़ी । यदि आज के दिन हरियाणा में चु नाव हो जाते हैं तो इस समझौते के तहत हरियाणा के लोग इस बात की मोहर लगा दें गे कि यह

समझौता गलत है और यहां की कांग्रेस सरकार भी इनके हाथ से जाती रहेगी । मैं तो इस बात से सहमत हूं कि अपने हिस्से के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए । सभी पार्टियों को एक साथ आवाज उठानी चाहिए । अब भी समय है कि पानी का फैसला, नहर की खुदाई का फैसला और जो इलाके तबदील किए जाने हैं, उनका फैसला एक साथ होना चाहिए । अब हमने अखबार में पढा है कि पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार सुरजीत सिंह बरनाला इस बात पर रजामन्द हो गए हैं कि एक नया कमीशन बै ठा दिया जाये ' पं जाब वाले कमीशन बै ठाये जाने के लिए तो हमेशा तै यार हो जाते हैं लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कमीशन का फैसला आ जाता है तो उसको इम्पलीमैंट नहीं होने देते । अब एक नया कमीशन बैठाने वाली बात भी सरासर गलत बात होगी । सैन्ट्रल सरकार को जो फैसला करना? है वह खुद अपने हाथ में लेकर करे और जो इलाके तबदील किए जाने हैं, उनको बोल्ड स्टैप उठा कर तबदील करे ।

चेयरमैन साहब, मैं ऐसे इलाके से आता हूं जहां पानी की बड़ी दिक्कत है । सिंचाई के पानी की बात तो दूर रही वहां पीने के पानी के लिए भी लोग तरसते हैं । सरकार ने लिफ्ट. इरीगेशन स्कीम के तहत वहां खाल, नहर और पुल आदि बनाने के लिए करोंडो नहीं बल्कि अरबों रुपये खर्च कर दिए हैं लेकिन पानी आने की कोई उम्मीद नहीं है । पंजाब वाले नहर के मसले में

ढील डाले हुए णै । वे चाहते है कि चण्डीगढ तो ले लें लेकिन बाकी मसले लटकते रहें । उनकी इच्छा है कि हरियाणा उनके रहमोकर्म पर हो जाए । हमारे लिए जरा सी भी दर्द उनके दिल में नही है । जो इलाके आज सूखे हैं, जो इलाके पानी के न होने से गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके बारे में वे नहीं सोचते कि वहां पानी पहुंचे और वे खुशहाल हों । मुझे तो दु:ख इस बात का है कि सरदार सुरजीत सिंह बरनाला अपनी जन्मभूमि को भी पानी नहीं दे रहे हैं । वे महेन्द्रगढ़ जिला में अटेली में पैदा हुए थे जहां से मैं एम०एल०ए० बन कर आता हूं ।

श्री सभापति : राव साहब, आप ही उनसे बात करके देख ले ।

श्री निहाल सिंह : बात तो आपके थू ही होगी । चेयरमैन साहब, सरदार बलवन्त सिंह पंजाब कैबिनेट में नं० 2 पर हैं । लोग कहते हैं कि पंजाव ऐकौर्ड के पीछे उनका ही माइन्ड था । वे भी वहां के हालात को जानते कुंए क्योंकि वे वहां बी०डी०ओ० रह चुके हैं । मैं तो यह चाहता हूं कि सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जी को, जिनका महेन्द्रगढ़ जिले में जन्म हुआ और सरदार बलवन्त सिंह जी को, जो वहां सर्विस करते रहे हैं, उस इलाके से हमदर्दी होनी चाहिए । उन्हें हुमारे साथ बड़े भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए । हिन्दू संस्कृति के तहत हमारे गांवों में हर जगह यह बात देखने में आती है कि जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तो हमेशा छोटे भाई की औप्शन रहती

है कि वह कौन–सा हिस्सा ले । पंजाब हमें छोटे भाई की तरह टूटि नहीं कर रहा है । वह तो हमें दुश्मन समझता है और हमारे रास्ते में हमेशा रुकावटें पैदा करता रहा है । तो मैं अर्ज करूंगा कि आज हरियाणा के लोग चाहते कि हमें पानी और इलाके के लिए एक जुट होकर लड़ना चाहिए लेकिन हरियाणा के नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, इस बात में डंट्रैस्टिड नहीं हैं । हरियाणा को पानी मिले या न मिले, इलाका मिले या न मिले, इसका कोई फायदा हो या न हो, इस बात का उन्हें कोई फिक्र नहीं । चौधरी भजन लाल चाहते हैं कि चौधरी देवी लाल की किसी तरह से बदनामी हो और चौधरी देवी लाल चाहते हैं कि किसी तरह से चौधरी भजन लाल जी हटें, चाहे हरियाणा के साथ कुछ भी होता रहे जबकि इस इशू पर हम सबको एक होना चाहिए और हरियाणा के पक्ष में आवाज बुलन्द करनी चाहिए ।

श्री सभापति : इस इशू पर आप तो चौधरी भजन लाल जी के साथ हैं ।

श्री निहाल सिंह : हम तो हरियाणा की जनता के साथ हैं । चौधरी भजन लाल जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं । 25 जनवरी, 1986 को जब सैशन के लिए पंजाब विधान सभा के मैम्बर्ज यहां आर' हुए थे और हरियाणा विधान सभा के मैम्बर्ज यहां आए हुए थे तो हरियाणा के एक नेता और पंजाब के एक नेता, जो दोनों मुख्य मन्त्रियों की कुर्सियों पर निगाह लगा।? बैठे हैं, की आपस में टैलिफोन पर बात हुई । पंजाब वाले नेता ने

कहा कि तुसीं ये गांव लेंके हाडा पिंड छडो लेकिन हरियाणा वाले चौधरी नेता ने कहा कि गांव की बात बाद में कर लेंगे आप पहले हमें पानी दे दो । नतीजा यह कि कोई न कोई लकूना रहने से दोनों मुख्य मन्त्रियों की छुट्टी हो और इनका नम्बर पड़े । चौधरी नेता से मेरा मतलब चौधरी देवी लाल से नहीं है, हरियाणा में और भी बहुत से चौधरी हैं । चेयरमैन साहब, मुख्य मन्त्री जी की हालत पर मुझे बडा रहम आता है क्योंकि इन्हें कई फ्रन्ट पर लड़ना पड़ता है । अपनी पार्टी के फ्रन्ट पर भी इन्हें लड़ना पड़ता है क्योंकिं कुछ लोग चाहते. हैं कि वे इनकी कुर्सी पर बैठ जाए । अपोजीशन का तो खैर यह राईट है और वैसे भी चौधरी देवी लाल जी के साथ इन्होंने धक्का किया है । अगर वे इन्हें राईटली औस्ट करने की कोशिश करें तो इसमे कोई बुराई नहीं है । फिर इन्हें सैन्ट्रल गवर्नमैंट के साथ भी काफी ऐग्जर्ट करना पड़ता है जबकि इन्हें स्पोर्ट न तो हरियाणा के लोगों से मिलती है और न अपनी पार्टी से पूरी स्पोर्ट मिलती है

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : ऐसी बात नहीं है । अपनी पार्टी से मुझे पूरी स्पोर्ट मिलती है ।

श्री निहाल सिंह : चेयरमैन साहब, गवर्नर ऐड्रैरस में डिवैल्पमैंट के बारे में बहुत बातें कही गई हैं लेकिन अफसोस की वात यह है कि महेन्द्रगढ़, भिवानी और दूसरे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस के बैकवर्ड एरियाज की डिवैल्पमैंट के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है । इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि

इनको डिवैल्प करने के लिए क्या कोशिश की जाएगी । (विघ्न) बैकवर्ड एरियाज में एक तो ऐम्पलायमैंट की अपर्चुनिटीज बहुत कम है । महेन्द्रगढ़ और नारनौल में न तो कोई प्राइवेट बड़ा कारखाना है और न ही गवर्नमैंट की कोई अन्डरटेकिंग है जिसमें लोगों को ऐम्पलायमैंट दी जा सके । और तो और पिछली बार जो जे०बी०टी० टीचर्ज की भर्ती हुई है, वह भी बाहर से हुई है क्योंकि वहां टीचर्ज अवेलेबल नहीं थे । टीचर्ज इसलिए अवेलेबल नहीं थे क्योंकि जे ०बी०टी० ट्रेनिंग सैटर महेन्द्रगढ डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं ।

चौधरी भजन लाल : रिवाड़ी में ओ०टी० सैन्टर है ।

श्री निहाल सिंह : वहां पंजाबी ओ०टी० है हिन्दी ओ०टी० नहीं है । इसके अलावा चेयरमैन साहब भर्ती करने के जो अदायरे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन और सुबार्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड, उनमें भी जिला महेन्द्रगढ का एक भी मैम्बर नहीं है । यह भी हमें एक डिसऐडवैन्टेज है क्योंकि जिस जिले का कोई मैम्बर होता है उस जिले के कुछ न कुछ लड़के सिलैक्शन में आ जाते हैं । (विघ्न)

चेयरमैन साहब, सुनने में आया है कि हरियाणा में एक नया इंजीनियरिंग कालेज खुलेगा । मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कालेज बैकवर्ड एरिया में खोलने में इनके सामने कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए ।

कुरुक्षेत्र जिला तो पहले ही डिवैल्पड है । वहां यूनिवर्सिटी भी है । मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि 1986 में यदि नया इंजीनियरिंग कालेज या नया मैडिकल कालेज खोलने का इरादा हो तो वह महेन्द्रगढ़ जिले में खोला जाना चाहिए वरना हम यह सोचेंगे कि बैकवर्ड एरियाज के लिए सरकार के दिल में कोई हमदर्दी नहीं चेयरमैन साहब, वकीलों का ऐजीटेशन हुआ था । यह गलत था या सही था, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । वकील भी गलत हो सकते हैं और ऐडमिनिस्ट्रेशन भी गलत हो सकती है । मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि एक पुलिस आफिसर की डियूटी लगायी है कि बहु इंक्वायरी करेगा कि किस का कसूर है । पुलिस अफसर की इंक्वायरी के लिए पुलिस अफसर ही लगाया है । यह बात ठीक नहीं लगती । यह मैं मानता हूं कि जो अफसर इंक्वायरी पर लगाया है, श्री नेगी, वह बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक हैं लेकिन उनकी जगह पर सीनियर आई०ए०एस० अफसर को लगाना चाहिए क्योंकिं पुलिस अफसर की इंक्वायरी पुलिस अफसर से नहीं करवानी चाहिए ।

चौधरी भजन लाल : वकीलों ने माना है, इसलिए उन्हें लगाया है ।

श्री निहाल सिंह : आपको नहीं मानना चाहिए था ।

चौधरी भजन लाल : पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील को लगाया था लेकिन अब उन्होंने इनको मान लिया तो इन्हें लगा दिया ।

श्री निहाल सिंह : चेयरमैन साहब, हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर के बारे में कुछ चर्चा चल रही है और आज अखबार में भी मैंने पढ़ा है कि उसे वहां से बदला जाये । यह बात डाक्टर मंगल सैन जी ने कही है कि उसे वहां से बदला जाये, यह बात तो ठीक है कि डिप्टी कमिश्नर डिवैल्पमैंट के काम में काफी अच्छी रूचि लेता है लेकिन डाक्टर मंगल सैन जी उन्हें बदलवाना चाहते पैं तो कोई न कोई बात तो होगी । इलैक्शन के दिनों में डिप्टी कमिश्नर ने काफी गड़बड़ की थी । इसलिए पब्लिक ओपीनियन को ध्यान में रखते हुए. उन्हें बदल दिया जाये तो ठीक रहेगा । (विघ्न)

श्री सभापति : आप उसको पब्लिक इन्ट्रैस्ट में बदलवाना चाहते हैं?

श्री निहाल सिंह : जी हां । चेयरमैन साहब, जिन सदस्यों ने विधान सभा से इस्तीफा दिया है उनके बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं । लोक दल के सदस्यों ने इस्तीफा दिया लेकिन मै जू र नहीं हुआ । इसका नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने उन्हें इलैक्ट करके भेजा थ अब वे सफर कर रहै हैं । उन लोगों की बात यहां पर कोई नहीं कह सकता ।

श्री सभापति : उन्हें यहां आना चाहिए और आपको भी उन्हें कहना चाहिएं कि वे यहां आयें और अपनी बात कहें ।

श्री निहाल सिंह : इसलिए मेरी अर्ज है कि उनके इस्तीफे मंजूर होने चाहिए और नये इलैक्शन होने चाहिए ताकि आम जनता सफर न करे ।

लोक निर्माण मन्त्री (श्री अमर सिंह) : इस्तीफा देने वालो में तो राव निहाल सिंह जी का भी नाम आया था ।

श्री निहाल सिंह : मैंने स्पीकर साहब को इस्तीफा नहीं दिया था । चेयरमैन साहब जब इस्तीफे की बात चली तो उस समय यह बात आयी थी कि सैशन का बाइ–काट करें, सै शन में न आयें लेकिन मैं यह कह सक ता हूं कि हमारे प्रैजीडेन्ट बाबू जगजीवन राम जी, जो आज देश में सियाने, अक्लमन्द और सोबर पोलि– टिशियन हैं, ने यह कहा था कि इस्तीफा देने से क्या हल होगा? अपोजीशन के भाइयों ने अब भी जो फैसला किया है कि हम सैशन का बाइकाट करौ और सैशन में नहीं आयेंगे, हम भी उनके साथ हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह पालिसी गलत है । अपोजीशन के भाइयों को या तो इस्तीफा देना चाहिए और हाउस में नहीं आना चाहिए । अगर इस्तीफा नहीं देना है तो हाउस को अटैन्ड करना चाहिए । यह पार्लियामैंटे रीयन कनवैन्शन के खिलाफ बात है कि वे इस्तीफा भी न दें और हाउस भी अटैन्ड न करें ।

चेयरमैन साहब, मैं आज ही उनके साथ शामिल हो जाऊगा और अपनी बात कह कर मैं भी सैशन अटैन्ड नही करूंगा । 23 तारीख को हमारे प्रैजीडेन्ट साहब लन्दन से आ रहे है । हम उनसे कहेंगे कि या तो हमें आप सैशन अटैन्ड करने की इजाजत दें या इस्तीफा देने की इजाजत दें । हम इस्तीफा भी न दें और सैशन भी अटैन्ड न करें, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं । अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपना फर्ज पूरा नहीं करेंगे । हम बाबू जगजीवन राम जी से बात करेंगे और उसके बाद वे जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम करेंगे ।

चेयरमैन साहब, चौधरी ईश्वर सिह जी ने गवर्नर साहब के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव मूव किया है और श्री फूल चन्द मुलाना ने सैकिन्ड किया है । मैं भी गवर्नर साहब का धन्यवाद करता अगर गवर्नर साहब छे सा कह देते कि चार साल आप लोगों ने राज कर लिया अब एक साल ये लोग राज कर ले । पहले गवर्नर नें जो किया था उसका मैंने बदला उतार दिया है ते । मैं भी उनका धन्यवाद करता परन्तु गवर्नर साहब के ऐड्रैस में यह नहीं लिखा । गवर्नर साहब के ऐडैरस में चौधरी भजन लाल जी ने यह नही लिखने दिया । भजन लाल जी ने कह दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए । इसलिए यह जो ऐड्रेस है जिसमें सरकार की कारगुजारी बतायी गयी है इसमें यह बात भी आनी चाहिए कि आज हरियाणा की जनता की जो मांग है वह मानी जानी चाहिए । यह जो पानी और टैरेटरी की बात है, यह पार्टी

पौलिटिक्स से ऊपर उठ कर की जानी चाहिए । यह बात सैन्ट्रल गवर्नमैंट में और इसरी जगह इफैक्ट डालती है । सब पर दबाव डालना चाहिए । जनता के हितों के लिए पार्टी मतभेद नहीं होने चाहिएं । हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हरियाणा को पूरा पानी मिले और हिस्सा मिले । ऐकौर्ड तो अपनी मौत अपने आप मर गया है । उसमें कोई दम नहीं है ।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी) : चेयरमैन साहब, सोमवार 17 फरवरी, 1986 को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण हाउस में दिया है और इस अभिभाषण पर जिस अच्छे तरीके से चौधरी ईश्वर सिंह जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव मूव किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू । सब से पहली बात तो यह है कि हमारे सूबे ने काफी तरक्की की है और तरक्की भी चहुंमुखी की है । बराबर के पड़ोसी प्रदेश के हालात शान्त नहीं रहे और वहां पर अशान्ति होने पर हमारे यहां भी गड़बड़ हो सकती थी लेकिन हमारे सूबे के हालात पूरी तरह से शान्त रहे, हालात खराब नहीं होने दिये । इसके लिये हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है कि उन्होंने उन गड़बड़ के हालात में भी अपने सूबे में सैकुलेरिजम को कायम रखा और हालात में खराबी आने में मदद नहीं दी । श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 1970 में अवार्ड दिया था, उस अवार्ड ने सैट्रल गवर्नमैंट को और मैथ्यू कमीशन को एक रास्ता दिखाया । मैथ्यू कमीशन सितम्बर, 1985 को मुकर्रर हुआ । उस कमीशन ने यह रिपोर्ट दे दी कि दो करबे, अबोहर '

और फाजिल्का, और 83 गांव ऐसे हैं जो हिन्दी भाषी तथा उन पर हरियाणा का हक है । हरियाणा सरकार ने इसके लिये अपना पक्ष वहुत अच्छी तरह से पेश किया जिसके फलस्वरूप यह नतीजा निकला कमीशन ने यह रिपोर्ट दी और यह पता चला कि 2 कस्बे और 83 गांव ऐसे हैं जो हिन्दी भाषी हैं । 26 जनवरी को चण्डीगढ़ के बदले हिन्दी भाषी इलाके हमें मिलने थे । यह उस ऐकौर्ड में बात कही गयी थी जो 24 जुलाई, 1985 को हुआ था । हिन्दी भाषी इलाकों का फैसला नहीं हो सका । ' क्योंकि कडू खेडा की वजह से उन गांवों से कान्टीगयूटी नहीं बनती थी जो हरियाणा को ट्रांसफर होने थे इसलिये कमीशन ने यह कह दिया कि इसका फैसला सरकार द्वारा किया जाये । कायदे के मुताबिक तो यह बात ठीक है क्योंकि उस ऐकौर्ड में तीन बातें हैं । एक बात तो यह है कि 15 अगस्त 1986 तक नहर बननी चाहिये लेकिन वह नहर हमें बनती दिखाई नहीं देती क्योंकि पंजाब सरकार इसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है । कडू खेड़ा जिसको पंजाबी भाषी गांव करार दिया गया है, की वजह से कान्टीगयूटी नहीं बनती इसलिये चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं दिया गया । मैं भी एक दिन कपूरी के पास के एक गांव में एक शादी में गया था । वहां पर मैंने देखा है कि काम बहुत धीमी गति से चल रहा है । इस गति से अगर 10 साल भी चलता रहे तो भी यह नहर पूरी नहीं हो सकती । दूसरे लोगों ने भी देखा है कि वहां पर काम इतना आहिस्ता–आहिस्ता चल रहा है और यह काम पूरा होता दिखाई नहीं देता । पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है । अगर पंजाब चाहे

तो यह नहर शीघ्र बनकर तैयार हो सकती है लेकिन वह इसको बनाना ही नहीं चाहता. । पानी एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं चल सकता । हमें 3.5 एम ०ए ०एफ ० मिला हुआ है जिस पर हमारा हक है और बहुत पहले यह फैसला हुआ था । मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जो कमीशन अब मुकर्रर हआ है, वह भी हमें उतना ही पानी देगा । मुझे वहां से भी पूरे इन्साफ की उम्मीद है । अपोजीशन के हाथ में अप्लाई साल तक हकूमत रही, क्या वह यह बतायेंगे कि उन्होंने कोई राक भी काम इस नहर को बनाने के बारे में किया हो जो यह लोगों को बता सकें कि हमने यह किया था । अब यह कहना कि एक साल के लिये हकूमत हमें दे दो, यह ठीक बात नहीं है । भीख मांगने से हकूमत नहीं मिलती । हकूमत तो वोट से मिलती है । अगर वोट से यह हकूमत में आ जायेंगे तो हम अपने आप ही उधर चले जायेंगे । हुकूमत कभी भी भीख मांगने से नहीं मिला करती । हमारी सरकार सैकुलेरिज्म में, हूर तरह से शांति कायम रखने में विश्वास रखती है । हरियाणा के लोगों ने यहां पर शान्ति कायम रखने में आ र प्रदेश में खुशहाली लाने को टोप प्रायरिटी अदा की है, इसके लिये हरियाणा के लोग बधाई के पात्र हैं । हरियाणा में ट्रांजिस्टर बम के कुछ केस हुए थे लेकिन सब गुनाहगार पकड़ लिये गये । कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो गुनाहगार हो और इस सरकार ने या पुलिस ने कैच न किया हो । ला एण्ड आर्डर की जो पोजीशन है, वह अगर खराब होती तो ये सारे आदमी कैसे पकडे जाते । यह लोग पकड़े नहीं जाते । यह खुशी की बात है

कि हरियाणा की आर्थिक अवस्था लगातार तरक्की कर रही है । पहले की 1562 करोड़ की आमदनी अब बढ़ कर पांच साला प्लान में 2900 करोड़ रुपये हो गयी है । इसमें शक नहीं कि सिचाई के काम में और बाढ के कामों में बड़ा भारी रुपया रखा गया है । जहां तक शहरों का ताल्लुक है, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उनके लिये कोई पैसा नही रखा गया है । मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इनके लिये भी कुछ न कुछ पैसा जरूर रखा जाना चाहिये ताकि शहरों को भी बाढ़ से बचाया जा सके । आज हरियाणा की 30 प्रतिशत आबादी तो शहरों में रहती है और 70 प्रतिशत टैक्स वे लोग अदा करते हैं । अगर उनकी बाढ़ की समस्या की तरफ कोई ध्यान न दिया जाये, तो कोई ठीक बात नहीं है । मेरा कहना यह है कि शहरों में डेर गेज की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि शहरों को भी बाढ़ से बचाया जा सके । अब मैं 20 सूत्री प्रोग्राम की बात भी कहना चाहूंगा । 20 दुखी कार्य कम सही मायनों में देश की तरक्की के लिये एक बढ़िया कार्यक्म है । क्ये देश को आगे ले जाया जा सकता है । 1977 में नसबन्दी और नलबन्दी का कुछ जहर था जिसकी वजह से लोगों ने हकू मत पलट दी । आज लोगों ने महसूस करना शुरू किया है कि जब तक वे इस ओर विचार नहीं करेंगे तब तक उनका विकास नहीं हो सकेगा । जमीन उतनी ही रहेगी और उनको खाना भी नहीं मिल सकेगा और न ही अनाज मिल सकेगा । आज सबसे बड़ी समस्या लोग प्रदेश की तरक्की के लिये यह महसूस कर रहे हैं कि आबा दी बढने से रुके और इसके लिये

कोई न कोई व्यवस्था करना जरूरी है । जो कर्जे हमारे बैंक देते हैं, उनके देने में सही मायनों में बैंक आजकल रुकावट हैं । इस बारे में जो दिक्कत पेश आ रही हैं, इसके लिये जो कुछ बैंक कर रहे हैं, वह जिम्मेवार हैं । जब आखिर में लोग चक्कर लगा–लगा कर 1500 रुपये लेने के लिये थक जाते हैं तो वह मजबूर होकर वापिस चले जाते हैं । बैंकों को कोई भी अथोरटी नही होनी चाहिये सिवाये इस बात के कि वह पैसा उसको दें जिसकी ऐप्लीकेशन उनके पास आ गयी है । मैं इसके लिये यह रिक्वैस्ट करूंगा कि भारत सरकार से दरख्वास्त की जाये कि जो भी ऐ प्लीकेशन पास हो जाये, उसको पैसा जल्दी और जरूर मिलना चाहिये । बिजली की कमी को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं । यह खुशी की बात है । आजकल बिजली की रिक्यायरमैंट बहुत बढ़ गयी है । जहां पर पहले केवल एक बल जला करता था, वहां पर आजकल टी ०वी ०, फ्रिज और हीटर हो गये हें जो यूज किये जाते हैं । बिजली की पैदावार भी बढ़ाना जरूरी है । आजकल हालत यह है कि बिजली चाहे मिले या न मिले, बिजली का बिल जरूर ज्यादा आ रहा है । परमाणु बिजली पै दा करने की योजना बनाई जा रही है, यह एक बहुत ही अच्छी बात है । परमाणु बिजली घर के लिये जो हरियाणा सरकार जगह तलाश कर रही है या की गयी है, मुझे पता नहीं वह कौन सी है लेकिन अम्बाला छावनी मैं समझता हू कि सबसे बेहतर जगह है । जगह भी बहुत है और मुकाम भी बहुत बढिया है । अम्बाला तहसील में करीब 7000 छोटे कारखाने लगे हुए हैं जिनका काम

बिना बिजली के ठप्प हो जाता है । अम्बाला तहसील हरियाणा की टोटल ऐक्सपोर्ट का वन थर्ड माल ऐंक्सपोर्ट करती है । बिजली का वहां पर इन्तजाम होना निहायत ही जरूरी है । अम्बाला तहसील इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार देने के लिये मैंने दो साल पहले एक रैजोल्य्शन दिया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने आन दी फ्लोर आफ दी हाउस यह वायदा किया था कि हम इसको करायेंगे । मुझे पता नही सिरसा कैसे हो गया और अम्बाला नहीं हुआ । मेरी समझ में यह नही आता कि यह कैसे हुआ? मेरी प्रार्थना यह है कि भारत सरकार से दोबारा सिफारिश की जाये और इस काम को टौप प्राय– रिटी दी जानी चाहिये ताकि यहां पर जितने भी कारखाने लगे हुए हैं, वह अच्छी तम् से चल सकें । एस ०वाई ०एल ० जो है, वह इन हालात में तो बनती नजर नहीं आती । अगर पंजाब सरकार की यही ढिल–मिल की नीति हुस बारे में है तो हमें भारत सरकार से यह रिक्वैस्ट करनी चाहिये कि वह इस काम को अपने हाथ में ले तब यह शायद जल्दी बन जाये । हरियाणा को आज सबसे ज्यादा जरूरत पानी की है । पानी के बगैर हमारा सारा हरियाणा प्यासा है । पीने के लिये हमारे पास पानी नहीं है । उधर उनके यहां सेम लग रही है । इसके अलावा पानी पाकिस्तान को वेस्ट जा रहा है । लेकिन अगर एक छोटे भाई को पानी मिल जाये तो उनको तकलीफ है । अम्बाला कैट में जो फ्लड सिस्टम है, उसको मामूली खर्चा करके ठीक किया जा सकता है और फलड्ज को रोका जा सकता है । वहां पर ड्रेन्ज का यदि इन्तजाम कर दिया जाये तो वहां पर शायद कभी भी

फ्लड्ज न आने पायें । अम्बाला छावनी में जो पुरानी डिग्गिया थी, वे आहिस्ता–आहिस्ता भरती जा रही हैं । वहां पर पानी के निकास का कोई प्रबन्ध नहीं है । जब तक वहां पर पानी के निकास का कोई इन्तजाम नहीं होगा, वहां पर फ्लड आयेगा । अगर कोई ड्रेनेज होगा तो नहीं आयेगा । हमारा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । इसमें पिछले साल की 13 लाख 63 हजार टन उपज के मुकाबले में इस वर्ष 16 लाख 42 हजार टन उपज हुई है । इसी तरह से धान के मामले में भी तरक्की हुई– है । हरियाणा मछली पालन की ओर भी आगे बढ़ रहा है । यह सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा है । पहले यह कहा गया था कि हरियाणा मकी ईटर न होने की वजह से इसमें कामयाब नहीं होगा लेकिन यह स्कीम बहुत कामयाब हो रही है । मैं पी ०ए०सी ० के साथ वहां पर गया था और मैंने देखा है कि यह काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है । इससे, जैसा कि कहा गया है, 5,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । मुझे आशा है कि यह रोजगार अवश्य मिलेगा । हरियाणा में चाहे मछली इस्तेमाल नहीं होती लेकिन मछली दिल्ली में बिक सकती है । हरियाणा के जिलों में जो विकास का प्रोग्राम चल रहा एं, वह बहुत अच्छी तरह से चल रहा है लेकिन गरीब आदमी के घर पर जितना पैसा पहुंचना चाहिये, उतना पैसा सही मायनों में नहीं पहुंच रहा है । इन जातियों के उत्थान के लिये छठी योजना में 1070 लाख रुपया खर्च किया गय था लेकिन इस सातवीं योजना में 3400 लाख रुपया की राशि नियत की गई है । पिछड़ी जातियों और अनु– सूचित जातियों तथा विमुक्त जातियों

के लिए ये स्कीम्ज बहत अच्छी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले पांच साल में हरियाणा सरकार इन कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए और भी नई स्कीम्ज तैयार करेगी । चेयरमैन साहब, हरियाणा सरकार चालीस हजार लोगों को बुढ़ापा पैंशन देगी । ये वे लोग हैं जो उमर में ज्यादा हैं और कमाने की स्थिति में नही हैं । यह हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है

चेयरमैन साहब, 1985– 86 मैं हरियाणा ने खाद्य उत्पादन मे भी काफी वृद्धि की है । इस साल 1960 लाख टन गेहूं की प्राप्ति की है और 7.28 लाख टन धान की खरीद की है । मैं इस मामले में हरियाणा के किसानों को मुबारिकबाद देता हूं क्योंकि उनकी मेहनत से ही ऐसा हुआ है कि इतनी अधिक उपज बढ़ी है।

चेयरमैन साहब, आवश्यक वस्तुओं के लिए सिविल सप्लाइज डिपार्टमैंट ने जो यह इन्तजाम किया है कि प्रत्येक डिपो वाला विभाग से कोई परमिट मांगे बिना थोक विक्रेता से वस्तुओं का अपना कोटा उठा सकेगा, यह बहुत अच्छी बात है । उससे भ्रष्टाचार दूर होगा ।

चेयरमैन साहब, हरियाणा ने इंडस्ट्रीज में बहुत तरक्की की है । 1966 में 4519 लघु यूनिटों के मुकाबले में अब यह संख्या 60,692 तक पहुंच गई है लेकिन इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनमें से कितने चालू हैं और कितने बन्द हैं ।

चेयरमैन साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । ऐड्रैस मैं कहा गया णै कि सातवी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिए पांच सौ प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से इस साल सौ स्कूल खोले जा चूके हैं । चेयरमैन साहब, अम्बाला छावनी में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं है इसलिए वहां पर भी एक स्कूल खोला जाना चाहिए । हम भी 1/90 हिस्से में आते हैं और इस 1/ 90 हिस्से के मुताबिक अम्बाला छावनी में स्कुल खोला जाना चाहिए । वहां पर सोशल और धार्मिक संस्थाएं स्कूल चला रही हैं लेकिन वहां पर सरकारी स्कूल कोई नहीं चेयरमैन साहब, वर्ष 1986–87 में 1, 228 लाख रुपए देहाती इलाकों में अस्पताल खोलने के लिए खर्च किए जाने हैं । मेरा कहना यह है शहरों में भी अस्पतालों की बहुत जरूरत है और शहरों में अस्पताल खोले जाने चाहिए । मेरे शहर में पचास बैड का अस्पताल है और वह सौ साल पुराना है लेकिन आज भी वह पचास बैड का है । शायद वह अस्पताल 75 बैड का होने जा रहा है ।

चेयरमैन साहब, 98 प्रतिशत सड्कों को पक्का करने की योजना है लेकिन इसमें शहरों का जिक्र नहीं किया गया गांवों का ही जिक्र किया गया है । इस सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों की काफी सहायता की है । सच्ची बात हुँ कि इनकीं वजह से ही भारत आजाद हुआ है और मैं इनको नमस्कार करता हूं । इनकी पैशन सौ रुपया से बढ़ाकर दो सौ रुपया कर दी है और भारत

सरकार ने इनकी पैंशन पांच सौ रुपया कर दी है । हमारी सरकार ने इन लोगों को और भी सुविधाएं दी है इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता है ।

चेयरमैन साहब, शुमाली हिन्दुस्तान में सेल्ज टैक्स का रेट एक होना चाहिए इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी । चेयरमैन साहब, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने यह धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है और चौधरी फूल चन्द ने इसका समर्थन किया है । मैं भी इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

चौधरी अजमत खां (नुह) : चेयरमैन साहब, मैं गवर्नर महोदय ने जो ऐड्रैस हाउस में रखा है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे बोलने का टाईम दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हू । चेयरमैन साहब, इस ऐड्रैस में हरियाणा में चहुंमुखी तरक्की का जिक्र किया है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । यह तरक्की सूरज की रोशनी की तरह चारों तरफ फैली हुई है । चाहे इंडस्ट्री है, चाहे वाटर सप्लाई शै, चाहे बिजली है, चाहे पानी है और चाहे नौकरी के मसाइल हैं, इन सभी में हरियाणा सब तरह से आगे बढ़ रहा है और इस सब के लिए जो सरकार कर रही है वह बधाई की पात्र है । चेयरमैन साहब, इस ऐड्रैस में एक बात का जिक्र आया है उसके ऊपर भी और कुछ और बातों पर भी मैं रोशनी डालूंगा । ।एस०वाई०एल० के बारे में कहा गया है कि वह 15 अगस्त, 1986 तक पूरी होनी है और

इसके लिए 110 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को दिया गया है और नब्बे करोड़ रुपया अभी और देना है । मेरा कहना यह है कि यह नब्बे करोड़ रुपया पंजाब सरकार को न दिया जाए क्योंकि अभी तक जो 11० करोड रुपया पंजाब को दिया गया है वह नहर के काम में नहीं लगाया गया बल्कि उससे लोगों को नौकरियां दी गई, बंगले बनाए गए हैं और कारें आदि खरीद ली गई हैं लेकिन काम जरा भी आगे नहीं बढ़ा है । इसलिए मेरी दरखास्त पै कि नब्बे करोड रुपया उस समय दिया जाए जब भारत सरकार इस नहर के काम को अपने हाथ में ले ले।

चेयरमैन साहब, इस ऐड्रैस में इंडस्ट्रीज का भी जिक्र किया गया है । मेरे दोस्त ने अभी बोलते हुए कहा कि जो बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया जाए उसमें और अधिक सुविधाएं दी जातु । मेवात के एरिया में अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज खोली जानी चाहिए जिससे कि कहां के लोगों को फायदा हो सके । इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हू कि हुड्डा इंडस्ट्रीज के लिए जो ऐग्रीकलचरल लैड एक्वायर करता है वह पांच–पांच साल तक बेकार पड़ी रहती है जिससे प्रदेश की खेती बाड़ी पर बुरा असर पड़ता है । जमीन उस वक्त ऐक्वायर करनी चाहिए जब फौरी तौर पर काम शुरू करना हो । चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि पांच दस साल तक जमीन बेकार पड़ी रहे, न तो उसमें फसल हो और न ही उसको इंडस्ट्रीज के लिंए या किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाए इससे कितना अधिक नुक्सान स्टेट को होता

है । जिस बैकवर्ड एरिया में जमीन ऐक्वायर की जाए, होना तो यह चाहिए कि उस इलाके के लोग इंडस्ट्रीज का फायदा उठाएं लेकिन ऐसा होता रही है । जब भी वहां पर कोई इंडस्ट्री लगती है तो यू ०पी०, बिहार और दूसरे प्रान्तों के आदमियों को नौकरी में ले लिया जाता है और उस इलाके के लोगों को और बच्चों को नौकरी तक से महरूम कर दिया जाता है । मजदूर की नौकरी भी उस इलाके के लोगों को नहीं मिलती । हालत यहां तक है कि आई०टी०आई० से पासशुदा लड़के बेकार फिरते रहते हैं उनको भी नौकरी में नहीं लिया जाता । बैकवर्ड इलाके की जमीन ऐक्वायर करने का वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होता । फायदा सिर्फ उन्हीं लोगो को होता है जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं । ऐसा करने से वहां के लोग ऊपर नहीं उठ सकते । मेरा कहना यह है कि बैकवर्ड एरिया में जब भी जमीन ऐक्वायर की जाए तो केवल वहीं के लोगों को नौकरी में लिया जाना चाहिए और इंडस्ट्री के प्लाटस देने में भी वहीं के लोगों को अहमियत देनी चाहिए ।

13.00 बजे

चेयरमैन साहब, ऐड्रैस मे कहा गया है कि इस वर्ष 23 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना है और इस सिंचित भूमि में से चार सौ एकड़ यानी एक सौ पचास हेक्टेयर भूमि मेवात के इलाके में सिंचित होनी है । हमारा पांच पर– सैंन्ट हुक बनता है और इस हिसाब से मेवात के एरिया में सिंचाई की सहूलियत

मिलनी चाहिए । तेईस हजार हेक्टेयर में से केवल एक सौ पचास हेक्टेयर भूमि सिंचित करना यह मेवात के साथ एक 'मजाक है । चेयरमैन साहब, मेरा एक सुझाव है कि तेईस हजार हेक्टेयर एरिया सिंचित करने की बजाय इरीगेशन डिपार्टमैंट ने जो नहरें और खालें केवल कागजों पर बना दिये हैं और वहां असल में कुछ भी नहीं है, उनको अगर बना दें तो अच्छा रहेगा । चेयरमैन साहब, देखने में यह आया है कि कागजों में नहर खुदी हुई है, खाल खुदे हुए हैं लेकिन असल में कुछ भी नहीं है केवल कागजी कार्यवाही है । मेरा कहना यह है कि ऐसे खालों को मौके पर जाका खोदा जाए । चेयरमैन साहब, हमारे यहां एकु असायसीका गांव है । वहा पर कागजों में आठ साल पहले वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पानी दे दिया गया लेकिन वास्तव में वहां कुछ भी नहीं है । आठ साल बाद जव पानी दिया गया तो कहा गया कि लोगों ने वहां से नत वगैरह चुरा लिए । मेरा कहना यह है कि (जब वहां पानी दिया ही नहीं गया और नल वगैरह लगाए ही नहीं गए तो चुराने का तो मतलब ही कुछ नहीं है । चेयरमैन साहब, इरिगेशन डिपार्टमैंट कों सब से ज्यादा रुपया दिया जाता है और अगर सही मायने में वह खर्च किया जाए और उस खर्च पर चौक रखा जाए तो बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है । विजिलैस औफिसर्ज चाहे इसी डिपार्टमैंट के लगाएं जाएं लेकिन वे ऐसे होने चाहिए जिनकी ईमानदारी पर कोई शक न हो । आज तक कई ओवरसीयर और एस ०डी ०ओज ० इन कामो में अपना हिस्सा–पत्ती लेते रहे हैं और जो अफसर कभी ऐसे केसिज की जांच के लिये जाते हैं, वे

भी उसी पार्टी के होते है जिससे जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं हो पाती है । मैं आप को बताता हू । मेरे इलाके में एक नहर है जिस पर शायद एक छटांक मिट्टी नहीं डाली गई है और फिर भी रात–रात में लाखों रुपये की उसकी पेमैंट हो गयी और उस की जांच भी हुई है लेकिन आज तक दोषी अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो अफसर जांच के लिये जाते हैं, वे सभी साथ मिल जाते हैं और तकरीबन वे जांच अधिकारी उसी पार्टी के होते हैं अब आप ही बताएं कि इस से क्या इन्साफ मिल पाएगा? जो व्यवस्था पहले अधिकारियों ने बना रखी थी, वही व्यवस्था अब विजीलैन्स विभाग ने भी बना रखी है । इसलिये सरकार कोई इस तरह का माहौल बनाए कि जो रिपोर्ट दी जाए, वह अफसरों के हित की न हो और पब्लिक हित में हो । सी०आई०डी० अलग होना चाहिये और विजीलैन्स डिपार्टमैंट अलग होना चाहिए । इन विभागों में तन्ख्वाहें भी अधिक होनी चाहिए । ताकि करप्शन के चासिज कम हों । इस समय हरियाणा में हर तरफ करप्शन है । कहीं जात–बिरादरी की करप्शन है, कहीं मजहब की और कहीं पर पैसे की करप्शन है । जब ऐसे केसिज के बारे में बातचीत उठाई जाती है तो उनकी इन्कवायरी के लिये जो अफसर जाते हैं, वे उसी विभाग के ही होते हैं और वे उसी गन्दे माहोल में से निकल कर आते हैं तो फिर आप ही बतलाए कि ऐसे अफसरों को दूसरों से क्या बदबु आएगी ? इसलिये मेरा निवेदन है कि इरीगेशन विभाग की तरफ से ऐसे मामलों पर चौक लगाना बहुत आवश्यक है । जितना

अधिक पैसा सरकार इस विभाग को देती है उतना काम तो हमें नजर नहीं आता लेकिन कई दूसरे विभाग क्रैश जिनको पैसा तो कम दिया जाता है लेकिन उनका काम पब्लिक की निगाह में कृत हो रहा है और सराहनीय है ।

चेयरमैन साहब, मेवात के इलाके के बारे में भी गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रैस में जिकर किया है । इस बारे में मैं यह कहना चाहता है कि मेवात के इलाके की बहबूदी के लिये केवल मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का ही जो पैसा होता है, वही इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उस पैसे से इस इलाके का कुछ बनने वाला नहीं है । इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि केन्द्र व राज्य की दूसरी स्कीमें जैसा कि आर०एल०जी०पी० और एन०आर०इ ०पी० हैं, उनका पैसा भी इस इजाके की बहवूदी के लिये खर्च किया जाना चाहिये । इन स्कीमों से सरकार को काफी फायदा हो रहा है । इसलिये इस काम के लिये ज्यादा से ज्यादा रकम दी जानी चाहिये ।

इसी तरह से मछली पालन का पेशा भी हरियाणा के अन्दर काफी बढ़ रहा है । इस काम के तिये सरकार ने जो राशि निर्धारित की हैं, उसमें और बढ़ौतरी की जानी चाहिये । खेतीबाड़ी के काम में तरक्की के लिये किसान और सरकार दोनों ही बधाई के पान है । इसके साथ साथ मैं सहकारिता विभाग का भी जिकर करना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की स्थिति में इसका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा बै । अगले साल में 220

करोड़ रुपया प्राथमिक सहकारी ऋण के रूप में दिया जाएगा । हरियाणा स्टेट लैन्ड मार्गेज बैक 1986–87 में 62 प्राथमिक सहकारी भुमि विकास बैंकों के जरिये 60 करोड़ रुपये का कर्जा देगा । यह एक बहुत बड़ा कदम है । मैं सुझाव दुंगा कि इस राशि को और बढ़ाया जाए ताकि केसों को हर प्रकार से राहत मिल सके' ।

चेयरमैन साहब, मैं एक बात की तरफ इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता है कि हमारी सरकार ने पौधों की तरफ खास ध्यान दिया है क्योंकि हरियाणा के अन्दर पौधे बहुत कम हैं लेकिन आज हालत यह है किं किसान पौधे लगाने में कम रुचि ले रहा है क्योंकि उसके पौधों को खरीदने वाले ग्राहक नहीं है । मन्डी में उनके पोधों की अच्छी लागत नही है जिसके कारण से किसान बेचारे डि–मारेलाईज हो रहे हैं । सरकार की तरफ से भी उन पौधों को खरीदने की कोई सुविधा उप– लब्ध नहीं है । इसलिये .मेरी रिक्वैस्ट है कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और उस के पौधों को सही कीमत पर बिकवाने का भी कोई न कोई हल होना चाहिये । मण्डियों में जाकर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नही होनी चाहिये । इस प्रकार की मण्डियों की भी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि किसान को प्रोत्साहन मिले ।

चेयरमैन साहब, मेरी सरकार राज्य के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने व उनमें वैज्ञानिक स्वभाव डालने के लिये

विज्ञान और टैक्नोलोजी के प्रयोगों को बढावा देने को उच्चतम प्राथमिकता दे रही है । मुझे इस बात की पूरी खुशी है और यह केन्द्र हिसार में 15 करोड़ की लागत से कायम किया जा रहा है । लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेवात का मेरा इलाका एक पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां पर युवकों के रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है । मेरे इलाके में एक कोटला लेक है और साथ में पहाड़ भी हैं इसलिये वहां पर अगर यह केन्द्र स्थापित किया जाए तो सरकार का बहुत कम खर्चा आएगा । वहां की जमीन अच्छी है, रेत नही है । मशीनरी पर भी कम खर्च आएगा । इससे वह इलाका भी खुशहाल होगा और वहां पर लोगों को रोजगार के साधन भी मुहैया होंगे । इसलिये मेरी यह ख्वाहिश है कि सरकार अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करे । ऐजुकेशन की तरफ भी सरकार की काफी तवज्जो है । मेवात के इलाके में टीचर नही मिलने थे और अब सरकार ने वहां पर जे०बी०टी० क्लासिज खोल दी हैं इसलिये मैं सरकार का शुक्रगुजार है । मेरी एक सुजैशन है कि सरकार ने जिस तरह से नजदीक के स्कूल कालेजों में साईस की तालीम का इन्तजाम किया है, उसी तरह से जिन जगहों पर इस तरह का इन्तजाम नहीं है वहां जो कालेज और स्कूल दूर दूर हुं उनमें भी साईंस की तालीम देने का इन्तजाम किया जाना चाहिये । लोगों को ऐसा न होने से काफी परेशानी है और मुझे भी इस बात से काफी परेशानी है । खास तौर पर नगीना कालेज में इस तरह की साईस की तालीम की क्लासिज अवश्य आरम्भ करवायी जानी चाहिये । (घण्टी)

चेयरमैन साहब, सड़कों का भी बुरा हाल है । कई कई जगहों पर तो हस्पताल वगैरह जाने के लिये लोगों को 20, 25 किलोमीटर्ज का फासला तय करणें जाना आना पड़ता है । कुछेक ऐसे सड्कों के छोटे छोटे से टुकडे हैं, जोकि फ्लड की वजह से टूट गये थे और –लोगों को दो दो किलोमीटर के फासले की बजाय अब वजह लम्बा फासला तय करके आना पड़ता है । यह सब कुछ गल्ल प्लैनिंग की बजह से हुआ है । इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस तरह के जो छोटे छोटे सडकों के टुकड्रे है, उनको लनाने में पहले प्राथमिकता दी जाए । दूसरी सड्कों की तरफ बाद में ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में इतना बड़ा लम्बा फासला तय करके न जाना पड़े, । इन अलफाज के साथ मैं गवर्नर साहब के ऐड्रैस का स्मर्थन करता इं और उनका इसक्रे लिये शुाक्रिया अदा करता हूं ।

जय हिन्द ।

चौधरी सूबे सिंह पूनिया (उचाना कलां) : चेयरमैन साहब, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हू । इस प्रस्ताव के शुरु में जो सब से सहत्वपूर्ण बात कही गयी है वह है 24 जुलाई, 1985 को श्री राजीव मौगोवाल समझौता या पंजाब केन्द्र समझौता और उसकी तरफ आज केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देशवासिंयों का ध्यान लगा हुआ है । इस समझौते की पहली कड़ी जो कुनडरती,

थी, जिसका निर्णय होना था, उसके अनुसार 26 जनवरी, 1986 को चडीगढ पंजाब को दिया जाना था और पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिये जाने थे । इसके लिये कमीशन बैठाया गया था । मैथ्यू आयोग के सामने जो संलग्क्ता और निरन्तरता आदि की दर्मज आफ रेफरेन्स रखी थीं, वह पूरी नहीं उतरी । लेकिन उस विषय के ऊपर मैं अपने विचार व अपने क्षेत्र के लोगों के विचार, उनकी भावनाएं यहां सदन की भावनाओं के साथ जोड़ना चाहता है । चौयरमैन साहब, चण्डीगढ़ एक अनूठा दुनिया में अपनी ही तरह का शहर है और उनकी आबादी का 80 प्रतिशत भाग हिन्दी बोलने वाला है । जब समझौते के अनुसार इस को पंजाब को देने का फैसला किया जा सकता है तो कंदूखेडा, जिसकी आबादी केवल 3– 4 हजार की ही है, उसमें चाहे सभी पंजाबी भाषी क्यों न हों, जिसकी वजह से हरियाणा को 85 हिन्दी भाषी गांव न्हीं मिल पाये, वह गांव हरियाणा में क्यों नहीं किराया जा सकता? अगर चण्डीगढ की तरह यह गांव हरियाणा को दे दिया जाए तो उसके साथ 85 गांव भी हरियाणा में शामिल हो जाएंगे । मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि यह क्षेत्रीय मामला आज केगों की भावना के साथ जुड़ा हुआ है । चण्डीगढ़ को देने के वक्त एक साथ ही फाजिल्का अबोहर का इलाका हरियाणा को मिलना चाहिए। इसके साथ 'साथ इस समझौते में एस० वाई० एल० के निर्माण की बात भी कही गई है कि यह कर 12 अगस्त, 1986 तक बन कर तैयार हो जाएगी । इसके साथ ही यह भी तय होना है कि कितना कितना पानी किस किस राज्य को मिलेगा ।

इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीन पार्टिया हैं । इस बारे में एक ट्रिब्यूनल बैठाया गया है जिसके फैसले की इंतजार हम कर रहे हैं । इसकी पैरवी हमारी सरकारर बहुत अच्छे ढंग से कर रही है । मैं. उम्मीद करता हुं कि हरियाणा वासियों की भावना को देख कर 3.5 एम० ए० एफ० पानी तो हमें मिलना ही चाहिए । मैं चाहता हूं कि सरकार इससे भी ज्यादा पानी लेने की पैरवी करे । हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, इस पानी के आते ही हरियाणा में चहुंमुखी विकास के दरवाजे खुल जाएंगे । हमारे आदरणीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी का स्वप्न है कि देश को 21वीं शताब्दी में एक नई दिशा देनी है । इसमें हरियाणा सारे भारत में पहली मिसाल होगा । इस नहर के बनने के बाद जो पानी आएगा उससे हरियाणा का चप्पा– कया लहरा उठेगा । इसलिये हरियाणा की खुशहाली के लिए, हरियाणा को पूरे देश में प्रगतिशील ढंग का प्रदेश साबित करने के लिए हम सब का यह प्रयास रहे कि एस० वाई० एल० निर्धारित समय पर बन कर तैयार हो जाए । इसके लिए जो हमारे पडौसी भाई की नियत है यानी इस नहर का काम अधूरा पड़ा हुआ है इस बात के लिए केन्द्र सरकार पर दवाव डाला जसा । इस काम को केन्द्र सरकार खुद करे या किसी बोर्ड अथवा कार्पोरेशन के हाथ में दे और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह नहर 15 अगस्त, 1986 तक बन कर तैयार हो जाएगी । इस नहर के पानी को आगे ले जाने के लिए हरियाणा ने अपनी ओर तो सारे प्रबन्ध कर रखे हैं । यानी सारी नहरें वन चुकी हैं । जैसे जवाहर लाल नेहरु कैनाल है, लोहारू उठान योजना है ये सब बन

कर तैयार हो चुकी हैं । इस पानी की हिसार, जींद, महेन्द्रगढ़ और भिवानी के इलाकों के लोग विशेष कर मुंह बाएं बाट देख रहे हैं कि कब हमारे इलाकों में पानी आएगा, हमारे घरों में खुशहाली होगी आरे खेतों में हरियाली होगी । इसके लिए चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा यह गुजारिश करूंगा कि केन्द्र पर बराबर दबाव डाला जाए कि इस नहर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और' हरियाणा के हितों को ध्यान में रखा जाए । दूसरी आज प्रदेश में सब से गंभीर समस्या बेरोजगारी की है । आज हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमें जो सौ दर्खास्तें मिलती हैं उनमें 95 बेरोजगार लडकों की होती? हैं । इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उद्योग लगाने के लिए जो 25 हजार रुपए की नई स्कीम चलाई गई है इसी तरह कृषि क्षेत्र को भी उद्धोग का दर्जा देकर ऐसी स्कीमें लागू की जाएं । देहात में जैसे एस० एस० आई० और आर० आई० एस ० की स्कीमें हैं इनमें और सुधार लाया जाए । जो नई स्कीमें चलाई जाए वे इस तरह से चलाई जाएं कि जो यूनिट जितना माल बनाए वह सारा सरकार खरीदे या वह ऐसी प्रोडक्शन हो जिसकी मांग बाजार में ज्यादा हो । मेरी समझ के अनुसार इस सदन में बहुत से सदस्य किसान हैं । आप सब जानते हैं किं कृषि की जोत बहुत छोटी होती जा रही है । आज बहुत से किसान केवल आधे आधे एकड़ के ही मालिक हैं । आबादी दिन प्रति दिन बढती जा रही है इस वजह से छोटी जोत होती जा रही है । मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कृषि को उद्योग का

दर्जा दे दिया जाए और किसानों के लडकों को भी कृषि उपकरणों के लिए और जमीन खरीदने के लिए कर्जे और अनुदान दिए जाएं । इसके अलावा जो कृषि से संबंधित छोटे मोटे उद्योग लगाए उसके लिए भी 25 हजार रुपए जैसी स्कीम चलाई जाए और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए । इससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी और नई पीढ़ी के नौजवानों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वे एक अच्छे नागरिक की तरह अपना गुजारा कर सकेंगे । इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान प्रदेश में बनी हुई सड्कों की ओर दिलाना चाहता हूं । इन सड्कों की हालत बहुत खस्ता है खास कर जो देहात में लिंक रोडज हैं उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खस्ता है । इन पर पैसे भी कम रखे गए हैं या कम खर्च हुए हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन लिंक रोडज की तरफ खास ध्यान दिया जाए । इन सड्कों, की रिपेयर की जाए और आगे के लिए इनके लिए ज्यादा पैसा रखा जाए । बहुत सी लिंक रोडज तो ऐसी हैं जिन पर बनने के बाद दोबारा रिपेयर ही नहीं हुई । उनके ऐसी हालत हो गई है कि वे सड़कें दोबारा बनानी पड़ेगी । जो सड़कें गांवों को आपस में जोड़ती है उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए । आज हरियाणा राज्य चहुंमुखी प्रगति कर रहा है इस वजह से शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई है । मेरे इलाके में उचाना एक ब्लाक स्तर का शहर है लेकिन इसमें कोई कालेज नहीं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र आया है कि फरीदाबाद में एक लड़कियों का कालेज खोला जाएगा तथा एक सरकारी कालेज देहाती इलाके में खोला जाएगा । सरकार से

मेरी प्रार्थना है कि यह सरकारी कालेज उचाना में खोला जाए । क्योंकि इस साल होने वाली दसवीं की परीक्षा में मेरे क्षेत्र के हजारों की संख्या में बच्चे अपीयर होंगे इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जो सरकारी कालेज है वह उचाना में ही खोला जाए ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके, साईंस की शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की कर सके और उन्नति कर सके । इन शब्दों के साथ जो चौधरी ईश्वर सिंह जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं । धन्यवाद ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : चेयरमैन साहब, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि के बारे में जो आकड़े दिए गए हैं उनमें उन्होंने बताया शै कि राज्य में उपज को बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं । जैसे जल मार्गो को पक्का करना, नहरों को पक्का करना और उनके साथ साथ दूसरे कार्य भी किए जा रहे हैं । चेयरमैन साहब, हरियाणा की एक कारपोरेशन एम० आई० टी० सी० है उसने हरियाणा के अन्दर 14500 किलोमीटर लम्बे जलमार्ग पक्के करके किसानों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम किया है । जल मार्गो को पक्का करने से किसानों की उपज काफी बढ़ी है उससे पानी में भी बढ़ौतरी हुई है । जब से एम०

आई० टी० सी० ने काम शुरू किया है उस समय से अब तक किसानों को 0.66 एम० ए० एफ० पानी ज्यादा मिलता है । इतने पानी की बढ़ौतरी हुई है यह बहुत ही सराहनीय काम है । (इस समय भी अध्यन पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया पै कि वर्ष 1984. कें 13.63 लाख टन की उपज के मुकाबले में अब धान की 16.12 लाख टन की अभूतपूर्व रिकार्ड उपज हुई है । इसी तरह से उन्होंने आगे बताया है कि इस वर्ष अनाज के लक्ष्य 77.65 लाख टन निर्धारित किए हैं । इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह लक्ष्य तभी प्रे होंगे यदि सरकार उपज बढ़ाने की तरफ ध्यान देती रही। यदि कृषि के लिए पानी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी तों यह लक्ष्य भी पूरे होंगे जो कपास की 8.30 लाख गांठों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है यह भी एक सहरानीय कदम है और इसमें भी हम काफी उन्नति कर रहे हैं । हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है और मेहनत करके हरियाणा प्रान्त की तरक्की कर रहा है । पहले जहां दूसरे देशों से अनाज मंगाया जाता था अब वही हरियाणा और हमारा पड़ोसी प्रान्त पंजाब दोनों मिलकर सारे देश को अनाज के मामले में' आत्म निर्भर करने में लगे ध्यू हैं । हरियाणा सरकार की यह पालिसी है कि जो बंजर भूमि थी जहां पर पानी नहीं. पहुंचता था उस बंजर भूमि के लिए लिपट इरीगेशन स्कीम से, नहरें पक्की करके और रजबाहे पक्के करके पानी पहुंचाने का काम किया है यह इस सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है । चेयरमैन साहब, जो एम० आई० टी० सी० है मैं उसका चूकि चेयरमैन हूं इसलिए

मुझे पता है कि इस कारपोरेशन में कुछ दिक्कतें हैं उसके लिए मैं अपने वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि उन दिक्कतों को ध्यान में रखें और इस वजट में उसके लिए ज्यादा पैसा रखें । इस कारपोरेशन का उपज बढ़ाने में काफी योगदान रहा है । किसानों की भलाई के लिए इम कारपोरेशन ने जो जलमार्गो को पक्का किया था अभी तक उस पैसे की वसूली किसानों से नहीं हो पाई है इसलिये मैं वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस कारपोरेशन के लिए इस बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखें ताकि इस कारपोरेशन का काम सुचारू रूप से चल सके और खालों को पक्का करके पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा सके । इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में बताया पैं किसानों की उपज को मंडियों में लाने के लिए पहले बहुत दूर–दूर तक मंडियों में जाना पड़ता था लेकिन अब किसानों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए 10 किलोमीटर के एरिया में परचेज सैन्टर, मार्किट कमेटियां और सब–मार्केट यार्ड बना कर दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को अपना माल बेचने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े । इसके अलावा इस अभि–भाषण में सड्कों के बारे में भी जिक्र किया गया है । हरियाणा सरकार ने प्रान्त के हर गांव को सड्कों के साथ जोड़ दिया है ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो । हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी इस तरफ काफी ध्यान दिया गया है । जहां पहले लोग पैदल चलते थे आज वहां पक्की सउके होने के कारण लोग रोडवेज में यात्रा करते हैं । हर गांव पक्की सड़क से जुद्ध जाने

से –लोगों को काफी सुविधाएं मिली हैं । यह एक बहुसे ही सहरानीय काम है किसानों को इस तरफ की सुविधाए दी जा रही हैं ये खुशहाली और उन्नति के बहुत बड़े कार्य हैं । इसके अलावा इस अभिभाषण में एस० वाई० एल० नहर 'के बारे' मै भी जिकर किया गया है । इस बारे में मेरे दूसरे माननीय सदस्यों ने बोलते हुए बताया है कि हरियाणा सरकार एस० वाई० एल० नहर को मुकम्मल करकने के लिए बहुत कोशिश कर रही है । एस ० वाई० एल० नहर के लिये जरे समझोता हमारी स्वर्गीय प्रधान मल्टी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था कि हरियाणों को 3.5 एम०ए० एफ० पानी मिलेगा इस बारे में मेरे से पहले बोलने वाले मेरे साथियों ने बताया है कि अपोजीशन वालों ने उस समझौते के लिरा भी यह कदु था कि यह पानी कम है, इसलिये पंजाव को चण्डीगढ क्यों दे दिया । लेकिन आज अपोजीशन के भाई कहते है कि हमें इतना पानी मिलना चाहिए । मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार हमरि चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व मे इस केस को मजबूती के साथ लड़ेगी । यह हम मानते हैं कि पंजाव के एरिया से यह नहर खुद कर हरियाणा में आनी है और इस समय उसकी खुदाई का काम भी उनके हाथ में दिया हुआ है और पंजाब की सरकार उसकी खुदाई का काम भी तेजी से नहीं कर रही है । ऐकौर्ड में दिया गया है कि इस नहर का कार्य 15 अगस्त, 1986 तक पूरा हो जाना चाहिए लेकिन इतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है । उस नहर का काम तेजी से करवाया जाना चाहिए ताकि नहर मुकम्मल हो और हरियाणा के किसानों को पानी मिल जाए यदि

उस नहर का पानी किसानों को मिल जाता है तो इस समय हरियाणा का किसान जितनी उन्नति कर रहा है उससे दोगूनी उन्नति होगी । मैं यह कहना चाहूंगा कि एस० वाई० एल० नहर की खुदाई का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले और 15 अगस्त 1986 तक नहर मुकम्मल करके हरियाणा को पानी दे दे । एस० वाई० एल० नहर का पानी इस्तेमाल करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अन्दर अरबों रुपया खर्च करके नहरें और जलमार्ग पक्के कर रखे हैं । जब तक एस० वाई० एल० नहर का पानी हरियाणा में नही आता तब तक जो पैसा खर्च किया जा चुका है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा । एस० वाई० एल० नहर के पानी के लिए नहरें और रजबाहे पक्के करने पर हरियाणा सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह बरबाद हो जाएगा । एम० वाई० एल० नहर की जितनी जल्दी खुदाई हो सके वह की जाए । हरियाणा सरकार सैन्ट्रल गवर्नमैंट पर दबाव डाले कि वह इस नहर को जल्दी मुकम्मल करवाए । जितनी जल्दी हो सके, चाहे एक हफ्ते में में चाहे 10 दिन में हरियाणा सरकार केन्द्रीय सरकार से यह प्लान करवाए कि इस नहर की खुदाई का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले लेगी । तब हरियाणा के किसानों को तसल्ली होगी कि नहर मुकम्मल हो जाएगी । मेरे अपोजीशन के भाइयों ने रास्ता रोको आन्दोलन करके यह कहा है कि हमने चण्डीगढ़ पंजाब को नही जाने दिया । यह क्रैडिट उनकी पार्टी को नहीं जाता बल्कि हमारी सरकार को जाता है क्योंकि सरकार ने प्रान्त में शान्ति कायम रखने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न किए जो

एक सहरानीय काम है वरना उस आन्दोलन में ककी नुक्सान हो सकता था लेकिन हरियाणा सरकार ने शान्ति कायम रखने के लिए बहुत सहरानीय काम किए । हरियाणा सरकार की भी काफी इच्छा है कि एस ० बाई ० एल ० नहर का पानी हरियाणा के अन्दर जल्दी से जल्दी आए । मैं यही कहूंगा कि हरियाणा सरकार इस नहर को मुकम्मल करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले और इसका काम भी केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मार्किट कमेटियों के बारे में भी जिक्र आया है । इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मार्किट कमेटियों ने जो एक परसैन्ट सैस लगाया था वह सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया । उसमें व्यापारियों ने किसानों से जो करोड़ों रुपया सैस का वसुल किया हुआ है वह उनके पास जमा पड़ा है । वह पैसा सरकार उनसे वापिस ले या उन्होंने जिसका माल लिया था उसको वापिस दें । सरकार किसी भी तरीके से कोई कायदा कानून बना कर उनसे वह पैसा वसूल करे और अपने खजाने में जमा करे वरना जिनका माल था उनको वापिस दे दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : टाईम हो गया है, आप कल रिज्यूम करेंगे । अब हाउस कल बाद दोहपर 2.00 बजे तक के लिये एडजर्न किया जाता है ।

13.30 बजे

(तत्पश्चात् सदन बुधवार दिनांक 19– 2– 1986 बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ) ।